Tuesday, 30 May, 1967

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th LOK SABHA DEBATES

Preservation Unit
6.7.12
Fumigated
On 4.1.84
Parliament Library

चतुर्थ माला
Fourth Series

खंड 3, 1967 / 1889 (शक)
Volume (iii), 1967/1889 (Saka)

[22 मई से 5 जून, 1967 / 1 ज्येष्ठ से 15 ज्येष्ठ, 1889 (शक)]
[May 22 to June 5, 1967/ Jyaistha 1 to Jyaistha 15, 1889 (Saka)]

दूसरा सत्र, 1967/1889 (शक)
Second Session, 1967/1889 (Saka)

(खण्ड 3 में अंक 1 से 10 तक हैं)
(Volume (iii) Contains Nos. 1 to 10)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

1353

विषय–सूची/CONTENTS

अंक 6—मंगलवार, 30 मई 1967/9 ज्येष्ठ 1889 (शक)

No. 6—Tuesday, May 30, 1967/Jaistha 9 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*तारा० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
151.	खाद्य नीति के बारे में मुख्यमंत्रियों तथा खाद्य मंत्रियों का सम्मेलन	Chief Ministers 'and Food Ministers' Conference on Food Policy	706—717
152.	भूख से मृत्यु	Starvation Deaths .	717—719
अल्प-सूचना प्रश्न S. N. Q. No.			
3.	मनी आर्डरों का भुगतान न किया जाना	Non Payment of Money Orders	719—721

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

तारा० प्र० संख्या Starred Question No.			
153.	सूखाग्रस्त क्षेत्रों से लोगों का प्रव्रजन	Migrations from drought hit Areas	721—722
154.	सुपर बाजार, नई दिल्ली	Super Bazar, New Delhi	722—723
155.	केन्द्र द्वारा उत्तर प्रदेश को खाद्यान्न की सहायता	Central Foodgrains Assistance to U, P.	723—724
156.	बिहार में अकाल की घोषणा	Declaration of Famine in Bihar	724—725
157.	निर्वाचन अर्जियां	Election Petitions .	725
158.	अकाल संहिता	Famine Code .	726
159.	सड़क परिवहन कराधान जांच समिति का प्रतिवेदन	Road Transport Taxation Inquiry Committee's Report	726
160.	आसाम में नदी स्टीमर सेवा	River Steamer Services in Assam	726—727
161.	इण्डियन एयरलाइंस कारपोरेशन के विमान इंजीनियर	I. A, C. Aircraf. Engineers	727—728

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
	प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.	
162.	कृषि में अनुसंधान और शिक्षा	Research and Education in Agriculture	728
163.	राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्र	Drought affected areas in Rajasthan	728—729
164.	इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन तथा एयर इण्डिया द्वारा संचालित आधुनिक परिवहन विमान	Modern Transport Aircraft used by I. A. C. and Air India	729
165.	विधायकों के लिये आचार संहिता	Code of Conduct for Legislators	729—730
166.	उड़ीसा में पर्यटन	Tourism in Orissa	730
167.	रबी की फसल का उत्पादन	Rabi Crop Production	730—731
168.	पाकिस्तान द्वारा रोके गये जहाजों का वापस लौटाया जाना	Release of Impounded Vessels by Pakistan	731—732
169.	गुजरात में अकाल की स्थिति	Famine Conditions in Gujarat	732
170.	पी. एल. 480 के अन्तर्गत अनाज पर व्यय	Expenditure on Foodgrains under PL 480	732—733
171.	पशुओ के चारे तथा भूसे का निर्यात	Export of Cattle Food and Bran	733—734
172.	कपास का उत्पादन	Cotton Production	734
173.	उर्वरको के मूल्यों का पुनरीक्षण	Revision of Pertiliser Prices	734—735
174.	खाद्यान्नों के लिए प्रयुक्त कीटनाशक दवाइयों का मानव के स्वास्थ्य पर प्रभाव	Effect of Insecticides used for Food on human health	735
175.	दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध की सप्लाई	Milk Supply by DMS	736
176.	केरल राज्य को अनाज की सप्लाई	Supply of Foodgrains to Kerala State	736—737
177.	गत साधारण निर्वाचन के दौरान में मतदान के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Polling during last General Elections	737—738
179.	गेहूं के बीज की शीघ्र उपज वाली किस्म	Quick yielding variety of Wheat Seeds	738—739

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.			
180.	केरल में छोटी बन्दरगाहों का विकास	Development of Minor Ports in Kerala	739—740
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
769.	भारत में चावल की स्थिति	Rice position in India	740
770.	विदेशों से खाद्य उपहार	Food Gifts from abroad	740
771.	मसूर की दाल की खेती	Cultivation of Masoor Dal	741
772.	पैट्रोलियम मल्व	Petroleum Mulve	741—742
773.	तूतिकोरिन बन्दरगाह परियोजना	Tuticorin Harbour Project	742
775.	डमडम का टर्मिनल हवाई अड्डा	Terminal at Dum Dum Airport	743
776.	राष्ट्रीय राजपथ	National Highways	743
777.	भारतीय लाख अनुसधान संस्था	Indian Lac Research Institute,	743—744
778.	रिवर स्टीम नेविगेशन कम्पनी	River Steam Navigation Company	744
779.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम सम्बन्धी जांच समिति का प्रतिवेदन	Enquiry Committee's Report on Hindustan Shipyard Ltd., Visakhapatnam	744—745
780.	दिल्ली दुग्ध योजना के डिपो मैनेजर	Delhi Milk Scheme Depot Managers	745
781.	केरल में कृषि विश्व-विद्यालय	Agricultural University in Kerala	745—746
782.	नाइट्रोजन उर्वरकों का वितरण	Distribution of Nitrogenous Fertilizers	746
783.	मध्यप्रदेश और गुजरात में नलकूपों के लिये सर्वेक्षण	Survey for Tubewells in Madhya Pradesh and Gujarat	746—747
784.	पर्यटन निधि	Tourist Fund	747—748
785.	कलकत्ता बन्दरगाह पर डाक व तार विभाग का वर्कशाप	P. & T. Workshop at Calcutta Port	748
786.	सुपर बाजार, नई दिल्ली	Super Bazar New Delhi	748
787.	सुपर बाजार, नई दिल्ली	Super Bazar New Delhi	749

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
	प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
788.	केरल में चावल और गेहूं के राज सहायता से निर्धारित मूल्य	Subsidy price of rice and wheat in Kerala	749—750
789.	बिहार में अकाल की घोषणा	Declaration of Famine in Bihar .	750—751
790	जापान से कृषि विशेषज्ञों की पेशकश	Offer of Agricultural Experts from Japan	751
791.	इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का आधुनिकीकरण	Modernisation of I. A. C. .	751—752
792.	दिल्ली में सड़क कर का भुगतान	Payment of Road Tax in Delhi .	752
793.	गो-हत्या सम्बन्धी समिति	Committee on Cow Slaughter	752—753
794.	राज्यों में राशन व्यवस्था	Rationing in States	753
795.	कृषि के क्षेत्र में रूस के साथ करार		753—754
796.	भारत में फार्म प्रदर्शन के लिये इसराइल सरकार को सुविधायें	Facilities to Israel Government for Farm Demonstration in India . .	754
797.	भारत और पाकिस्तान के बीच हवाई सेवा को पुन: चालू करना	Restorpation of Indo-Pak Air Services	754—755
798.	दिल्ली को खाद्यान्नों की सप्लाई	Food Supplies to Delhi	755
799.	पर्यटक सप्ताह	Tourist Week .	755—756
800.	फालतू अनाज वाले राज्यों द्वारा कमी वाले राज्यों को अनाज की सप्लाई	Supply of Foodgrains by Surplus States to deficit States	757
801.	पर्यटक कार	Tourist Cars . .	757—758
802.	मध्य आकार के फार्मों पर मशीनों से खेती करना	Machanization of Medium size farms .	758
803.	कृषि उत्पादन के लिये नया तरीका	New Strategy for Agricultural Production	758—759
804.	पालम हवाई अड्डा	Palam Airport	759
805.	रामेश्वरम तलाई-मन्नार नौका सेवा	Rameswaram Talaimannar Ferry service	759—760
806.	आयात किये गये गेहूं के मूल्य	Prices of imported wheat	760

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

807.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का पुनर्गठन	Reorganisation of ICAR	760
808.	दिल्ली श्रीनगर जैट विमान सेवा	Delhi-Srinagar Jet Service	760
809.	हैलीकोप्टर सेवा	Helicopter Service	761
810.	इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की दिल्ली पठानकोट सेवा को पुनः चालू करना	Resumption of Delhi Pathankot IAC Flights	761
811.	शीघ्र तैयार होने वाली फसलें	Short Duration Crops	761—762
812	इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन में डकोटा विमानों के स्थान पर दूसरे विमान	Replacement of IAC Dakotas	762
813.	राज्यों को सूखे की स्थिति का सामना करने के लिये सहायता	Drought Relief to States	762—764
814.	उर्वरक का लदान	Handling of fertilizer Cargo	764
815.	सहकारी क्षेत्र में पटसन का कारखाना स्थापित करना	Setting up of a Jute Mill in Cooperative Sector in Assam	764—765
816.	भारतीय खाद्य निगम द्वारा अनाज का समाहार	Procurement of Foodgrains by Food Corporation of India	765—766
817.	मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) जिले में दुर्भिक्ष की स्थिति	Famine conditions in Mirzapur District (U. P.)	767
818.	कोलम्बो योजना के अधीन आस्ट्रेलिया को द्विसदस्यीय दल का खाद्य सम्बन्धी अध्ययन के लिये दौरा	Visit by 2-men Team to Australia for Food Study under Colombo Plan	767
819.	विशाखापत्तनम पत्तन	Visakhapatnam Port	767—768
820.	छोटी सिंचाई योजना	Minor Irrigation Schemes	768
821.	सोहना कस्बे का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास	Development of Sohana as a Tourist Centre	768—769
822.	भारत में प्रमुख राजपथ	Trunk Highways in India	769—770
823.	जल संभरण के लिये जलभृतों (ऐक्विफर्ज) का प्रयोग	Use of Aquifers for Water Supply	770

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.			
824.	मैसूर राज्य में बाजरे का सरपल्स स्टाक	Surplus Stock of Bajra in Mysore State	770—771
825.	गन्ने की खेती	Cultivation of Sugar Cane	771
826.	खाद्यान्न के मूल्य	Prices of Foodgrains	771—772
827.	उड़ीसा में नारियल का उत्पादन	Coconut Production in Orissa	772
828.	उड़ीसा द्वारा बिहार को धान का संभरण	Supply of Paddy by Orissa to Bihar	772—773
829.	1966–67 में उड़ीसा में फसलों की हुई क्षति	Damage to Crops in Orissa (1966-67)	773
830.	केरल में कोवालम का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास	Kovalam as Tourist Centre in Kerala	774
831.	भारतीय खाद्य निगम	Food Corporation of India	774
832.	हवाई सेवाओं को रोकना अथवा देरी करना	Holdups and Delays of Air Service	775
833.	जयन्ती शिपिंग कम्पनी	Jayanti Shipping Company	775—776
834.	बलियापट्टम नदी पर सड़क का पुल	Road Bridge over Balliapattam River	776
835.	नीडकारा पुल	Neendakara Bridge	776—777
836.	दिल्ली में शीतागार	Cold Storages in Delhi	777
837.	पर्यटन केन्द्र के रूप में इजूमलाई (केरल) का विकास	Ezhumali (Kerala) as a Tourist Centre	777—778
838.	बीज फार्म	Seed Farms	778
839.	बिहार राज्य के लिये खाद्यान्नों की सप्लाई	Supply of Foodgrains to Bihar State	779
840.	ओबराय इन्टरकांटिनेन्टल होटल, नई दिल्ली	Oberoi Inter Continental Hotel New Delhi	779
841.	मैदा और सूजी आदि का राशनिंग	Rationing of Maida Suji etc.	779—780
842.	खाद्यान्नों का पकड़ा जाना	Seizure of Foodgrains	780
843	दिल्ली में खोया बनाने पर प्रतिबन्ध	Ban on Khoya Preparations in Delhi	780—781
844	बिहार में अकालग्रस्त क्षेत्र	Famine Areas in Bihar	781
845.	बिहार में अकाल	Famine in Bihar	781
846.	सुपर बाजार, नई दिल्ली	Super Bazar, New Delhi	782

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

847.	राष्ट्रीय समुद्री दिवस	National Maritime Day	782
848.	सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारियों द्वारा डाक द्वारा भेजे गये मतपत्र	Ballot Papers sent by Post by the Armed Forces personnel	783
849.	गोसंवर्धन तथा पशुपालन के लिये राशि का नियतन	Allocation for Gosamvardhan and Animal Husbandry	783
850.	सूखे से पीड़ित व्यक्तियों के लिये निर्धारित धन का दुरुपयोग	Misuse of money earnmarked for drought hit people	783—784
851.	अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष	International Tourist Year	784—785
852.	खण्ड विकास अधिकारियों के पद की समाप्ति	Abolition of the post of Block Development Officers	785
853.	चुनावों के दौरान हैलिकाप्टरों का प्रयोग	Use of Helicopters during Elections	786
855.	अमरीका से खाद्य सहायता	Food aid from USA	786
856.	बिहार, उत्तर प्रदेश और मद्रास में नलकूप	Installation of Tubewells in Bihar UP and Madras	786—787
857.	खाद्यान्नों के मूल्य	Prices of Foodgrains	787
858.	संसद् तथा विधान सभाओं के लिये चुनाव	Elections to Parliament and Vidhan Sabhas	787—788
859.	पटना के समीप गंगा नदी पर पुल	Bridge over Ganges near Patna	788
861.	दिल्ली में राशन में मिलने वाली वस्तुओं के मूल्य	Prices of Rationed Commodities in Delhi	788—789
862.	सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा	Tour of drought affected Areas	789
863.	उड़ीसा से चावल का निर्यात	Rice Export from Orissa	789—790
864.	उड़ीसा में चावल वसूली का मूल्य	Rice Procurement Price in Orissa	790—791
865.	केरल में धान की वसूली का भाव	Procurement Price of Paddy in Kerala	791
866.	त्रिवेन्द्रम और एर्नाकुलम हवाई अड्डे	Tribandrum and Ernakulam Airports	791—792
867.	खाद्यान्नों के आयात पर व्यय	Expenditure on Import of Foodgrains	792
868.	खाद्यान्नों का आयात	Import of Foograins	792—793

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
	प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
869.	कुमाली (केरल) में हवाई अड्डा	Airport at Kumali (Kerala)	793
870.	कालीकट हवाई अड्डा	Calicut Airport	793
871.	एर्नाकुलम टीकाय पीर-मार्ड राष्ट्रीय राजपथ	Ernakulam-Teekoy-Peermade National Highway	793—794
872.	जयन्ती शिपिंग कम्पनी	Jayanti Shipping Co	794
873.	शिलांग जवाई बदरपुर सड़क	Shillong-Jowai-Badarpur Road	795
874.	काश्मीर जाने वाले पर्य-टकों के लिये सुविधायें	Facilities to Tourist visiting Kashmir	795—796
875.	दिल्ली परिवहन के जाली टिकटों की बिक्री	Selling of faked DTU tickets	796
876.	डमडम् हवाई अड्डे से इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की उड़ानों की समय-सारिणी	IAC Flight Schedules from Dum Dum Airport.	796—797
877.	शिलांग के निकट हवाई अड्डा	Airfield near Shillong	797
878.	मिजो हिल जिले में विधान सभा के निर्वाचन	Assembly Elections in Mizo Hill District	797—798
879	खाद्य स्थिति का अनुमान लगाना	Assessment of Food Situation	798
880.	अनाज का समाहार	Procurement of Foodgrains	798
881.	पंजाब से हिमाचल प्रदेश को वस्तुओं को निर्बाध ले जाया जाना	Free Movement of Articles from Punjab to Himachal Pradesh	799
882	हिमाचल प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों की पंजाब में कृषि भूमि	Agricultural Land of Himachal Pradesh Ex-Servicemen in Punjab	800
883.	केन्द्रीय सरकार द्वारा खरीदा गया गेहूं तथा चावल	Wheat and Rice Purchased by Central Government	800
884.	रासायनिक खाद	Chemical Manures	800—801
885.	खाद्यान्नों का आयात	Import of Foodgrains	801
886.	कार्बनिक खाद	Carbonic Manure	802
887.	कुमारकोम का एक पर्य-टन केन्द्र के रूप में विकास	Development of Kumarkom a Tourist Centre	802

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
888.	कलकत्ता पत्तन शुल्कों में वृद्धि	Increase in Calcutta Port Charges	803
889.	राज्यों में चावल के मूल्य	Prices of rice in States	803
890.	भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल का समाहार	Rice Procurement by Food Corporation of India	803—804
891.	जिस भूमि पर खेती नहीं होती उसे कृषि योग्य बनाने के लिये अनुदान	Grants for Reclamation of Uncultivated Land	804
892.	बूचड़खाना	Cattle Slaughter House	805
893.	राष्ट्रीय पार्क	National Parks	805—806
894.	ग्वालियर में हवाई अड्डा	Aerodrome in Gwalior	806
895.	लेबनान से प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता से दिल्ली राज्य के गांवों का विकास	Development of Delhi Villages with Financial Assistance from Labanon	806—807
896.	डकोटा विमान सेवा से इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को हुई हानि	Loss Suffered by IAC on Dakota Service	807
897.	एवरो जेट विमान	Avro Jets	807—808
898.	भारत में खाद्य उत्पादन	Food production in India	808
899.	सिलचर मनीपुर सड़क	Silchar Manipur Road	808—809
900	भूमिहीन कृषि श्रमिकों को बसाना	Settlement of Landless agricultural labourer	809
901.	बिहार के लिये खाद्यान्न का कोटा	Quota of foodgrains for Bihar	809—810
902.	राजपथ विकास कार्यक्रम	Highway Development Programme	810—811
903.	पटसन उत्पादन का लक्ष्य	Jute Production Target	811
904.	कलकत्ता बन्दरगाह में जहाजी कर्मचारियों की हड़ताल	Strike by Marine Crew at Calcutta Port	812
905.	खाद्य नीति	Food Policy	812—813
906.	राजस्थान में केन्द्रीय कृषि फार्म	Central Agricultural Farm in Rajasthan	813
907.	बीकानेर (राजस्थान) में ऊंट पालन केन्द्र	Camel farm at Bikaner (Rajasthan) .	813
908.	विदेशी पर्यटक	Foreign Tourists .	813—814
909.	केन्द्रीय देशान्तर्गत जल परिवहन निगम	Central Inland water transport corporation.	814

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

910.	आन्ध्र प्रदेश में प्रयोगात्मक नलकूप संगठन	Exploratory tubewells organisation in Andhra Pradesh	815
911.	बड़ौदा के लिये हवाई सेवा	Air Service to Baroda	815
912.	गन्ने की खेती वाली भूमि का क्षेत्रफल	Area under Sugarcane Cultivation	815—816
913.	बिहार तथा उत्तर प्रदेश के अकालग्रस्त क्षेत्रों के लिए सहायता	Relief to Famine Areas in Bihar and U. P.	816—817
914.	पटना और मधुबन तथा पटना और सहरसा के बीच हवाई सेवा	Patna-Madhuban and Patna-saharsa Air Services	817
915.	रूस द्वारा गेहूं का दिया जाना	Wheat donation from U.S.S.R.	817
916.	भारतीय पर्यटक कार्यालय, लन्दन	Indian Tourist Office, London	818
917.	वैलोर हवाई अड्डा	Vellore Airport	818
918.	पारादीप पत्तन	Paradeep Port	818—819
919.	उड़ीसा की गेहूं की आवश्यकता	Wheat Requirement of Orissa	819—820
920.	छिद्र (बोर) करने वाली मशीनें	Boring Machines	820
921.	दिल्ली में दूध का मूल्य	Price of milk in Delhi	820
922.	दिल्ली में एयर इण्डिया के चालकों के लिये निवास स्थान	Accommodation for Air India Crew in Delhi	820—821
923.	माही में पर्यटक केन्द्र	Tourist Centre at Mahe	821
924.	कप्पड़ में पर्यटक केन्द्र	Tourist Centre at Kappad	821
925.	बक्सर में पुल	Bridge at Buxar	821—822
926.	उड़ीसा को उर्वरकों का सम्भरण	Supply of Fertilizers to Orissa	822—823
927.	उड़ीसा और राजस्थान में कृषि उत्पादन	Farm output in Orissa and Rajasthan	823
928.	कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार विभागों को मिलाना	Integration of Departments of Agricultural Community Development and Cooperation	823
929.	बीदर (मैसूर) में हवाई अड्डा	Aerodrome at Beedar (Mysore)	824

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	PAGES
930.	खेती की उपज के लिये मैसूर को अनुदान	Grant to Mysore State for Agricultural Production	824
931.	केन्द्रीय सरकार के गोदामों में अनाज की क्षति	Damage to Foodgrains in Central Government Godowns	824—825
932.	राज्यों में चावल का मूल्य कम करने के लिये सहायता	Subsidy to bring down price of rice in States	825
933.	निजामबाद और बिदर में हुए निर्वाचन	Elections held in Nizamabad and Bidar	825—826
934.	संयुक्त फार्म प्रायोगिक योजनाए	Joint Farm Pilot Sechemes	826
935.	राजस्थान को उर्वरकों का भेजा जाना	Supply of Fertilizers to Rajasthan	826—827
936.	राजस्थान में बागवानी का विकास	Development of Horticulture in Rajasthan	827—828
937.	राजस्थान में गन्ने की खेती का विकास	Development of Sugarcane cultivation in Rajasthan	828
938.	राजस्थान और उड़ीसा में युवक होस्टल	Youth Hostels in Rajasthan and Orissa	828—829
939.	दांतवाला समिति का प्रतिवेदन	Dantwala Committee's Report	829
940.	विशाखापत्तनम में ग्रेविंग डॉक परियोजना	Graving dock project at Visakhapatnam	829
941.	ओखला में खाद का उत्पादन	Production of Manure at Okhla	830
942.	मंगलौर पत्तन परियोजना	Mangalore Port Project	830
943.	कृषि नीति	Agricultural Policy	831—832
944.	समस्तीपुर सेन्ट्रल शूगर कम्पनी लिमिटेड	Samastipur Central Sugar Co. Ltd.	832
945.	पर्यटक सप्ताह (मार्च, 1967)	Tourist week [March 1967]	833
946.	संघीय सड़क परिवहन प्राधिकरण	Federal Road Transport Authority	833
947.	"सूरज सलामत" पाल वाला जहाज	Sailing Vessel 'Suraj Salamat	833—835
948.	सांताक्रुज हवाई अड्डा	Santacruz Airport	835
949.	हिमाचल प्रदेश में खाद्य पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि	Rise in Prices of Food stuff in Himachal Pradesh	835

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
	प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
950.	कान्टांज के सिडनी जाने वाले बोइंग विमान की दुर्घटना	Accident to Sydney bound Qanta Boeing	836
951.	ताइचुंग नेटिव—1 धान	Taichung Native—1 Paddy	836—837
952.	दिल्ली शहादरा में कूड़ा खाद का प्रयोग	Use of Compost Manure in Shahdra Delhi	837
953.	राज्यों में खाद्यान्नों के मूल्य	Prices of Foodgrains in States	837—938
954.	बिहार में उपहार स्वरूप प्राप्त कपड़ों की बिक्री	Sale of gift clothes in Bihar	838
955.	पोर्ट ब्लेयर में जहाजों का रोका जाना	Detention of Vessels at Port Blair	838—839
956.	कलकत्ता से पोर्ट ब्लेयर को इण्डियन एयरलाइन्स की निर्धारित उड़ान	Scheduled IAC flights to port Blair from Calcutta	839
957.	अन्दमान लेबर फोर्स कापरेटिव सोसाइटी	Andaman Labour Force Co-operative Society	839—840
958.	पोर्ट ब्लेयर से जहाज सेवा	Sailings export Blair	840—841
959.	बिहार का खाद्यान्नों को सप्लाई	Supply of Foodgrains to Bihar	841
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	841
	कुछ केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा बिड़ला बन्धुओं से वेतन पाने के बारे में छपे समाचार	Reported news about some of the Central Ministers being on the pay roll of Birlas	841—844
	श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	841
	श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	841—842
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	844—849
	याचिका का उपस्थापन	Presentation of Petition	849
	केरल को सप्लाई किये गये अनाज के बारे में निर्देश 115 के अन्तर्गत वक्तव्य	Statement under Direction 115 re. foodgrains supplied to Kerala	849—853
	समितियों के लिये निर्वाचन	Elections to Committees	853—854
	(1) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्	(i) Indian Council of Agricultural Research; :	853

असा० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

(2) राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड	(ii) National Shipping Board:	853—854
(3) राष्ट्रीय खाद्य तथा कृषि संगठन सम्पर्क समिति	(iii) National Food and Agriculture Organisation Liaison Committee	854
रेल्वे 1967-68 आयव्ययक सामान्य चर्चा	Railway Budget 1967-68 General Discussion	854—856
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri A. B. Vajpayee	854—856
श्री कृष्णकुमार चटर्जी	Shri Krishna Kumar Chatterji	856—857
श्री रामचरण	Shri Ram Charan	857—858
श्री न० कु० साघी	Shri N. K. Sanghi	858—859
श्री सामिनाथन	Shri Saminathan	859—860
श्री हेमराज	Shri Hem Raj	860
श्री दत्तात्रेय कुन्टे	Shri Dattatraya Kunte	861
श्री परिमल घोष	Shri Parimal Ghosh	861—862
श्री रघुवीरसिंह शास्त्री	Shri Raghuvir Singh Shastri	862—863
श्री चेंगलराया नायडू	Shri Chengalraya Naidu	863—864
श्री एच० अजमल खाँ	Shri H. Ajmal Khan	864
श्रीमती सावित्री श्याम	Shrimati Savitri Shyam	864—865
कुछ आरोपों के बारे में नियम 357 आदि के अन्तर्गत व्यक्तिगत स्पष्टीकरण	Personal Explanation under Rule 357 re. certain allegations	865—866
श्री सत्यनारायण सिंह	Shri Satya Narayan Singh	865
श्री कृष्णचन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant	866

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 30 मई, 1967/9 ज्येष्ठ, 1889 (शक)

Tuesday, May 30, 1967/Jyaistha 9, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में प्रश्न लिये जायेंगे । श्री श्रीचन्द गोयल

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, All questions from 151 to 156 pertain to one subject that is food. I suggest that all of them should be taken together. It will be saving the time of the House.

अध्यक्ष महोदय : यदि सभा इसे स्वीकार करे तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है ।

Shri Onkar Lal Berwa : Question No. 154 is on the subject of Super Bazar.

श्री प्र० के० देव : ऐसा करने से कुछ कठिनाइयां पैदा होंगी, क्योंकि जिसने दो प्रश्न पूछे हैं और जो चार पूरक प्रश्न पूछ सकता है, उसे केवल एक पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति होगी ।

अध्यक्ष महोदय : यह बात सच है । परन्तु दूसरी कठिनाई यह है कि पहला प्रश्न लगभग 50 सदस्यों ने मिलकर रखा है और यदि सभी प्रश्न-कर्त्ताओं को एक-एक पूरक प्रश्न भी करने दिया गया तो पूरा प्रश्नकाल समाप्त हो जायेगा । इस प्रश्न पर केवल चार-पांच पूरक प्रश्न किये जाने के बाद अगला प्रश्न ले लिया जायेगा ।

खाद्य नीति के बारे में मुख्य मन्त्रियों तथा खाद्य मन्त्रियों का सम्मेलन

151. श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री नाथपाई :
श्री हेम बरुआ :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री वी० कृष्णमूर्ति :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री शारदा नन्द :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री राम सिंह आयरवाल :
श्री मधु लिमये :
श्री स० मो० बनर्जी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री जार्ज फरनेडीज :
श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री नि० र० लास्कर :
श्री राम किशन गुप्त :
श्री जे० बी० सिंह :
श्री रणजीत सिंह :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री एन० एस० शर्मा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री म० सुदर्शनम् :
प्रो० प्र० के० देव :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री धीरेन्द्र नाथ :
श्री देवकी नन्दन पटोदिया :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री पार्थसारथी :
श्री आर० डी० रेड्डी :
श्री डी० एस० पाटिल :
श्री आर० बरूआ :
श्री सी० सी० देसाई :
श्री वाई० ए० प्रसाद :
श्री एन० के० सांघी
डा० कर्णी सिंह :
श्रीमती निर्लेप कौर :
श्री के० सूर्यनारायण :
श्री मनीभाई जे० पटेल :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री मीठा लाल :
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री सम्बन्धन :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य नीति के मामले में 8 और 9 अप्रैल, 1967 को नई दिल्ली में हुए मुख्य मंत्रियों और खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन में किये गये निर्णयों का ब्योरा क्या है, और

(ख) क्या देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिये कोई अखिल भारतीय खाद्य नीति निश्चित की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में ~~राज्य~~ मंत्री (श्री ~~अन्ना साहब शिन्दे~~) : (क) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है ।

(ख) जी हां ।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। विवरणों की प्रतियां उन सदस्यों को भी नहीं मिल पाती हैं जिन्होंने प्रश्न रखा है। अतः मैं यह निवेदन करता हूँ कि उत्तर देने वाले मंत्री महोदय विवरण का सार अवश्य दे दिया करें जिससे, वे सदस्य भी जिन्हें विवरण की प्रति नहीं मिली है, पूरक प्रश्न पूछ सकें।

अध्यक्ष महोदय : विवरण की प्रतिलिपि प्रत्येक सदस्य को मिलनी चाहिये। इस बात का जिक्र दो-तीन रोज पहले भी हुआ था और यह सुझाव दिया गया था कि सम्बन्धित मंत्रालय इतनी प्रतियां भेजा करे जिससे सभी सदस्यों को प्रति प्राप्त हो सके। अब मंत्री महोदय इस विवरण को पढ़ दें।

विवरण

दिल्ली में 8 व 9 अप्रेल, 1967 को मुख्य मंत्रियों तथा खाद्य मंत्रियों के हुए सम्मेलन के निष्कर्ष

मुख्य मंत्रियों तथा खाद्य मंत्रियों के 8 व 9 अप्रेल, 1967 को हुए सम्मेलन के निष्कर्षों को सार रूप में नीचे दिया जा रहा है :—

1. कमी और अभाव की वर्तमान स्थिति में यह अनुभव किया गया है कि परिस्थिति का सामना करने के लिये अन्न के निर्बाध लाने-ले जाने की व्यवस्था पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिये यह निश्चय किया गया कि एक राज्य से दूसरे राज्य में अनाज को निजी व्यापार हेतु लाने-ले जाने पर लगे क्षेत्रीय व्यवस्था के प्रतिबन्धों को जारी रखा जाये। हालांकि चने के अतिरिक्त शेष सभी दालों का निर्बाध-रूप से लाना-ले जाना बना रहेगा।

2. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और दिल्ली के गैर-राशन वाले क्षेत्र से बने वर्तमान गेहूँ के क्षेत्र को तोड़कर एक राज्यीय क्षेत्र बनाया जायेगा। इसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के पृथक-पृथक गेहूँ क्षेत्र होंगे।

3. यह स्वीकार किया गया कि सम्मेलन के सामने रखे गये राष्ट्रीय खाद्य बजट की अपनी कुछ सीमाएं थीं क्योंकि उत्पादन और खपत सम्बन्धी उपलब्ध आंकड़े बिल्कुल सही नहीं थे। इस वर्ष विषम परिस्थिति में सामना करने के लिये यह आवश्यक है कि तदर्थ आधार पर कार्य किया जाये और आंकड़े एकत्र करने की व्यवस्था को सुधारा जाये ताकि बाद में एक उचित तथा ठीक आंकड़ों पर आधारित बजट तैयार किया जा सके।

4. यह भी मान लिया गया कि चावल के मामले में स्थिति विषम है। इसलिये यह स्वीकार किया गया कि देश के अधिकता तथा कमी वाले सभी राज्यों में चावल की वसूली के लिए ठोस प्रयास करना चाहिये ताकि कमी वाले राज्यों में वितरण के लिये चावल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके। आन्ध्र प्रदेश ने यह मान लिया है कि वह राज्य 2 लाख टन आयातित गेहूँ और मिलों के बदले में केन्द्र को कुल 6 लाख टन अन्न देगा। पंजाब सरकार ने केन्द्र को कुल 6 लाख टन अनाज देने का वचन दिया है। उड़ीसा केन्द्र को 75000 टन चावल देगा और हो सका तो वह केन्द्र द्वारा दिये गये अनाज के बदले में भी केन्द्र को उपरोक्त मात्रा के अतिरिक्त चावल देगा।

5. वसूली के मामले में यह तय किया गया कि प्रत्येक राज्य को किसी भी प्रकार का वसूली का तरीका अपनाने की छूट होगी। साथ ही प्रत्येक राज्य को यह प्रयास करना होगा कि वसूली अधिकाधिक हो।

6. यह भी अनुभव किया गया कि कृषि मूल्य आयोग ने जो वसूली का भाव रखा है, वह कुछ कम है। यह निर्णय किया गया कि मुख्य रूप से रबी की फसल उगाने वाले राज्यों के साथ इस प्रश्न पर पुन: चर्चा की जायेगी और रबी के अनाजों के भावों के बारे में कुछ ही दिनों में घोषणा कर दी जायेगी।

7. इस बात पर भी सहमति हो गई कि अनाज की वसूली और खरीद के बारे में भारत के खाद्य निगम द्वारा अदा की जाने वाली भूमिका की जांच की जानी चाहिये और प्रत्येक राज्य को खाद्य निगम के उस उद्देश्य को पूरा करने में सहायता करनी चाहिये, जिस उद्देश्य से उसकी स्थापना की गई है। इस बात पर भी बल दिया गया है कि ऐसा प्रयास करना होगा, जिससे खाद्य निगम कुशलतापूर्वक कार्य कर सके और वह बेकार का बिचौलिया न बन जाये।

खाद्य निगम के खर्च और उसको होने वाले लाभ की जांच करने के लिये भी सबने सहमति प्रकट की। इससे यह स्पष्ट हो जायेगा कि खाद्य निगम को स्थापित करने से मूल्यों में वृद्धि हुई है या नहीं।

8. यह निश्चय किया गया है कि कमी वाले और अधिकता वाले राज्यों के मुख्य मंत्रियों को मिलाकर एक स्थायी समिति बनाई जायेगी जो समय समय पर उठने वाली खाद्य समस्याओं पर विचार किया करेगी।

9. यह अनुभव किया गया कि इस वर्ष की विषम खाद्य स्थिति को देखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि देश में उत्पादन बढ़ाया जाये और इसके लिये रबी फसल की कटाई और खरीफ फसल की बुवाई के बीच वाले समय में यथासम्भव अधिक क्षेत्र में अल्पकालिक फसलें पैदा की जानी चाहिए।

श्री श्रीचन्द गोयल : हमारे यहां खाद्य उत्पादन अनाज की आवश्यकता की तुलना में कितना कम होता है। चालू वर्ष में अन्न की कमी को पूरा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : वैसे तो आंकड़े अभी अन्तिम रूप से प्राप्त नहीं हुए हैं परन्तु इस वर्ष 760 लाख टन अनाज के उत्पादन का अनुमान है। इसके अतिरिक्त 70 से 90 लाख टन अन्न का आयात किया जायेगा। इस उपलब्ध मात्रा में ही हमने अपना काम चलाना है।

श्री श्रीचन्द गोयल : खाद्य समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है और प्रत्येक देशवासी को अनाज देना संघ सरकार का कर्त्तव्य है। क्या केन्द्रीय सरकार, राज्यों में उत्पादन के प्रश्न को अलग रखते हुए, पूरे देश में अनाज का समान और उचित रूप से वितरण करेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मैं इस बात को नहीं मानता हूँ कि लोगों को अनाज देने की जिम्मेदारी केवल केन्द्रीय सरकार की है। केन्द्रीय और राज्य सरकारों की यह संयुक्त जिम्मेदारी है। केन्द्रीय सरकार उन राज्यों को अन्न के संचित भंडार में से अधिकाधिक अनाज देने का प्रयास करती है, जहां अनाज आवश्यकता से कम पैदा होता है।

श्री हेम बरूआ : चूँकि संघ सरकार को अनाज की अपेक्षित मात्रा विदेशों से मंगाने में सफलता नहीं मिली है इसलिये कुछ राज्य सरकारों ने यह सुझाव दिया है कि उन्हें विदेशों, खासकर श्रीलंका और बर्मा, से खुद अनाज मंगाने की अनुमति दी जाय। क्या यह सच है? यदि हां तो केन्द्रीय सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है?

श्री जगजीवन राम : किसी भी राज्य सरकार से इस आशय का सुझाव नहीं आया है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : विवरण से यह ज्ञात होता है कि खाद्य निगम के कार्य-संचालन की जांच की जायेगी और यह प्रयास किया जायेगा कि खाद्य निगम फिजूल का बिचौलिया न बन जाये। क्या सरकार ने खाद्य निगम के कार्य अभी स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं किये हैं? क्या राज्य सरकारें खाद्य निगम की अन्न प्राप्त करने में सहायता करने को राजी हैं? क्या कुछ राज्य इसका विरोध कर रहे हैं? यदि हां तो वे कौन से राज्य हैं?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : वास्तव में समझौता इस बात पर हुआ था कि खाद्य निगम के अनाज खरीदने और वसूल करने सम्बन्धी कार्य-पद्धति की जांच की जायेगी। यह शिकायत की गई थी कि खाद्य निगम अनाज वसूल करने के लिये बहुत अधिक चार्ज करती है। सम्मेलन में यह तय हुआ था कि इस सम्बन्ध में जांच की जायेगी और इस प्रभार को उचित बनाने के लिये प्रयास किया जायेगा। साथ ही यह बात भी स्पष्ट की गई थी खाद्य निगम के कार्य में अड़चन पैदा न की जाये, जिससे खाद्य निगम का उद्देश्य पूरा हो सके।

Shri Yashpal Singh : In sowing season a farmer is supplied the wheat seeds at the rate of Rs. 65/- per maund, while the same wheat is being purchased from the same farmer at the rate of Rs. 34/- per maund. Is it not a big disparity. May I know whether it has been given the serious consideration in the conference of Chief Ministers or Cabinet meeting that wheat must be supplied to the farmers throughout the year at the rate, at which the wheat is purchased from them ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : यद्यपि कृषि मूल्य आयोग ने कम मूल्य निर्धारित करने का सुझाव दिया, फिर भी खाद्य तथा कृषि मंत्री के कहने पर रबी के अनाजों के दाम अधिक निर्धारित किये गये हैं। ऐसा करते हुए किसानों के हित का ध्यान रखा गया है तथा इसे राज्य सरकारों की सहमति भी प्राप्त है।

Shri Yashpal Singh : There should be some rule to take stern action against hoarders and profiteers.

Shri Jagjivan Ram : We have issued such instructions to States.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : प्रसिद्ध संख्याविदों तथा अर्थशास्त्रियों का यह विचार है कि उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े एकत्र करने का ढंग दोषपूर्ण है। ठीक आंकड़े एकत्र करने के लिये सरकार कौन से नये तरीके अपनाने के बारे में विचार कर रही है ? क्या यह सच है कि देश में अनाज की कमी नहीं हैं बल्कि अनाज के अभाव का प्रचार किया जा रहा है ताकि वसूली कार्यक्रम को विफल बनाया जा सके ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : आंकड़े एकत्र करने के लिये हमने एक संगठन की स्थापना की हुई है। यह विभिन्न राज्यों में काम करता है और राज्य सरकारें इसकी मदद करती हैं। ठीक आँकड़े एकत्र करने का प्रयास किया जाता है, परन्तु हर काम की कुछ सीमाएं होती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि देश में अनाज की मात्रा आँकड़ों के आधार पर आंकी गई मात्रा से अधिक उपलब्ध है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही: उड़ीसा सरकार ने केवल 75,000 टन चावल बेचने का वायदा किया था जबकि वह 95,000 टन चावल अब तक दूसरे राज्यों को दे चुकी है। केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा को 10,000 टन चावल देने को कहा था परन्तु उसे केवल 3,000 टन चावल अभी तक दिया गया है। अब उड़ीसा से भुखमरी की खबरें आ रही है। क्या केन्द्रीय सरकार उड़ीसा को उतना अनाज देगी जिसके लिये उसने वायदा किया था?

श्री जगजीवन राम : यह पूरक प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। यदि माननीय सदस्य एक पृथक प्रश्न इस बारे में पूछेंगे तो उन्हें पूरी जानकारी दे दी जायेगी।

Shri Bibhuti Mishra : Is it a fact that Bihar has met this fate on account of zonal system, which prevents the traders of Bihar to purchase the wheat from surplus State like Punjab ? Is it not leading to disunity ?

Shri Jagjivan Ram : The system of zones was introduced with a view to put restrictions on trade in foodgrains as well as to know the surplus and deficit states in matter of foodgrains and further to know whether the movements of foodgrains is towards deficit areas or towards the areas where the prices of the foodgrains are high. Normally it is the tendency of the traders that they move the foodgrains to the areas where they get higher prices. They do not care for the needy areas. Secondly we have not the buffer stock of foodgrains at present. In view of these circumstances this system was introduced.

श्री प्र० के० देव : मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि श्री पाणिग्रही का पूरक प्रश्न विवरण से सम्बन्धित कैसे नहीं है। विवरण के चौथे पैरे में यह लिखा है कि उड़ीसा सरकार गेहूँ के बदले 75,000 टन चावल देने के लिये राजी हो गई है। उड़ीसा को 25,000 टन गेहूँ और मिलना चाहिये। अब उड़ीसा में गेहूँ और आटे का भीषण अभाव है। क्या सरकार उड़ीसा को इतना गेहूँ तत्काल भेजेगी ?

श्री जगजीवन राम : यहां पर जो वक्तव्य दिया गया है, माननीय सदस्य ने उसे ठीक तरह नहीं सुना है। वक्तव्य में कहा गया था कि उड़ीसा 25,000 टन चावल बेचने के

लिये तैयार है। तब हमने उड़ीसा के मुख्य मंत्री को, कुछ और चावल देने के लिए प्रार्थना की और उन्होंने उत्तर दिया कि यदि उनको समान मात्रा में गेहूँ दे दिया जाये तो वह उस पर विचार करेंगे। निश्चय ही मैं इसकी जांच करूंगा; गेहूँ की सप्लाई में जो कमी है मैं निश्चय ही उसको पूरा करने का प्रयत्न करूंगा।

श्री रा० बरूआ : वक्तव्य से यह प्रतीत होता है कि कमी वाले राज्यों और बहुतायत वाले राज्यों क मुख्य मंत्रियों की एक स्थायी समिति बनाई जायेगी। क्या इसका काम समय-समय पर खाद्य से सम्बन्धित समस्याओं की जांच करना है ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : यह बताया गया है कि आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल, मद्रास, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बगाल के मुख्य मंत्री मिल कर एक स्थायी समिति बनायेंगे।

Shri A. B. Vajpayee : Is it a fact that the Chief Minister of Madhya Pradesh had drawn the attention of the Conference to the deteriorating food situation in his state ? Did he make a mention that famine conditions prevail in certain districts of Madhya Pradesh; that people are sustaining themselves by eating leaves of trees and roots and that thousands of the people of Kharguja District have shifted to Pulamai district of Bihar where relief operations are afoot, if not, whether the hon. Minister has his own information regarding the food situation of Madhya Pradesh and if so, what measures have so far been taken on that basis ?

Shri Jagjivan Ram : There was no occasion to raise these issues at that time. The food situation of Kharguja had deteriorated later on. He, of course, mentioned that Madhya Pradesh, which was surplus in food, has now due to the failure of rains become deficit in the matter of food. We are also giving some quantity of foodgrains to Madhya Pradesh. As regards the condition of Kharguja, we have started taking some measures. We have opened some free kitchens for feeding the people and some hand manual works have also been started to provide relief. But I admit that the present measures are not adequate and they need to be intensified.

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : अन्न के समाहार में अब तक अनुभव की गई कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने राज्य व्यापार निगम को गल्ले क व्यापार करने का सुझाव दिया है ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : जी हां। वास्तव में इस विषय पर काफी चर्चा हुई थी। समाहार किस तरीके से किया जाये यह मामला राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ दिया गया है। परन्तु सभी मुख्य मंत्रियों ने हमें आश्वासन दिया कि वे समाहार के लिये अपना भरसक प्रयत्न करेंगे।

श्री जी० भा० कृपलानी : मैं जानना चाहता हूँ कि खाद्य मंत्री उस राज्य के बारे में क्या करेंगे जो अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करता है परन्तु जिसके कुछ क्षेत्रों में अकाल पड़ा हुआ है? क्योंकि यह राज्य अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करता है और राज्य सरकार अपनी हठधर्मी के कारण केन्द्र से सहायता नहीं मांगती और राज्य में

भी एक तहसील और दूसरी तहसील के बीच प्रतिबन्ध हैं, इसलिये उन लोगों के सम्बन्ध में क्या किया जायेगा जो कमी वाले क्षेत्रों में रहते हैं और जो उसी राज्य के अधिक मात्रा वाले क्षेत्रों से अनाज प्राप्त नहीं कर सकते ? मध्य प्रदेश के लगभग 5 जिलों में ऐसी स्थिति है, और एक क्षेत्र में तो जिलाधीश ने घोषणा भी की थी कि वहां पर अकाल की स्थिति है परन्तु भी कोई उपाय नहीं किये गये हैं ।

श्री जगजीवनराम : मैं माननीय सदस्य की इस धारणा को स्वीकार नहीं कर सकता कि कोई ज़िम्मेदार राज्य अपने क्षेत्रों के प्रति अनवधानता बर्तेगा और उस क्षेत्र की सहायता के लिये केन्द्र का आना आवश्यक होगा ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यही तो हो रहा है । **(व्यवधान)**

श्री जगजीवन राम : मेरे माननीय मित्र जो चाहे आरोप लगा सकते हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह एक तथ्य का प्रश्न है । माननीय मंत्री स्वयं इन क्षेत्रों का दौरा कर के देखें ।

श्री जगजीवन राम : हमें भूलना नहीं चाहिये कि राज्य में भी उतने ही जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं जितने कि यहां पर । जब तक राज्य सरकारें काम कर रही हैं और राज्य विधान मण्डलों में लोगों के प्रतिनिधि मौजूद हैं, तब तक मुझे यह नहीं समझना चाहिये कि वे राज्य की दशा से बेखबर हैं ।

जहां तक केन्द्र का सम्बन्ध है, मैंने कहा है कि मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भारी विपदा है और कुछ कार्य किया गया है । परन्तु जैसा कि मैंने बताया, वे सब उपाय पर्याप्त नहीं हैं और हम लगभग 35,000 से 40,000 टन अनाज मध्य प्रदेश को भेज रहे हैं । पीड़ित क्षेत्रों में मुफ्त वितरण के लिये मैंने 2,000 टन गेहूँ मध्य प्रदेश भेजने का आदेश दिया है ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : क्या मंत्री महोदय ने विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों से यह पूछा है कि खाद्यान्न के अतिरिक्त उनको कितनी मात्रा में उर्वरक, धन और मशीनों की आवश्यकता होगी और यदि हां, तो क्या खाद्य मंत्री राज्यों के खाद्य मंत्रियों से यह प्रश्न पूछने की वांछनीयता पर विचार करेंगे कि वह यह सुनिश्चित करें कि इन आवश्यकताओं को पूरा किया जायेगा और किसानों को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जायेगा ताकि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिये उत्पादन में वृद्धि की जा सके ?

श्री अन्ना साहब शिन्दे : विभिन्न राज्य सरकारों की इन सभी आवश्यकताओं की जांच की जाती है । जहां तक उर्वरक की आवश्यकता का सम्बन्ध है हमने राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरक वितरण नीति का निर्माण किया है ।

Shri George Fernandes : May I know whether any Chief Minister had urged in the conference to lift the zonal restrictions on the movement of foodgrains ? Has any concrete decision been taken to raise short term crops during the intervening period between

the two main crops and have any steps been taken to implement it ? The former President in his broadcast to the nation on the 26th of January had remarked that one third of our food production goes waste. Was this issue discussed in the Chief Ministers Conference and the decision taken to prevent this wastage ?

श्री जगजीवन राम : कुछ मुख्य मंत्री खंडीय प्रतिबन्धों को हटाने के पक्ष में थे। अल्पकालिक फसलों के सम्बन्ध में क्रियात्मक उपाय किये गये हैं और सभा को यह जान कर खुशी होगी कि लगभग 11 लाख एकड़ भूमि में अल्पकालिक फसलें बोई गई हैं।

जहां तक अपव्यय का सम्बन्ध है, मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में उस पर विचार नहीं किया गया था और क्रियात्मक कार्यवाही की जा रही है।

वास्तव में मैं खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से एक प्रतिवेदन परिचालित करने जा रहा हूँ जिसमें कि सारा ब्योरा होगा कि खाद्यान्न के अपव्यय को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

Shri Prakash Vir Shastri : May I know whether the hon. Food Minister has received reports to the effect that like the inhabitants of Sarguja District, the inhabitants of Mirzapur, Allahabad and Banaras districts of Uttar Pradesh are shifting to Palamau district of Bihar to seek relief from hunger because good and ample facilities exist there, if so, whether some specific steps are being taken to meet the demands of these districts after gathering information from U. P. Government ?

Shri Jagjivan Ram : So far as Uttar Pradesh is concerned, adequate arrangements did not exist in Mirzapur in the beginning, but now the arrangements are quite sufficient and working well. From my personal knowledge I can say that U. P. Government and private organisations are doing good work.

Shri Prakash Vir Shastri : The Bharat Sewak Samaj should be withdrawn from there.

Shri Manubhai Patel : The Government had announced that we shall achieve self-sufficiency in food by 1971. Did the Chief Ministers Conference discuss as to how to achieve this target in the changed conditions ? Do Government still stick to the belief that we shall achieve self-sufficiency by 1971; if so, the concrete programme that has been chalked out for this ?

Shri Jagjivan Ram : This aspect was considered in the previous conference and steps are being taken to implement the decisions arrived thereat.

Shri Onkar Lal Berwa : In Rajasthan out of the total population of 2.25 crore, 13 lakh people are famine-stricken. May I know what matters relating to Rajasthan were discussed in the Chief Ministers Conference and the Food Ministers Conference held recently, by whom Rajasthan was represented and the scheme if any is there to give aid to Rajasthan ?

Shri Jagjivan Ram : Rajasthan was represented by the Adviser of Rajasthan. So far as the aid to Rajasthan is concerned, we are giving 40,000 tonnes of foodgrains to Rajasthan every month.

Shri Onkar Lal Berwa ; Only 40,000 tonnes for a population of 2,25,00,000 ?

अध्यक्ष महोदय : मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे माननीय सदस्य अपने स्थानों पर खड़ हो रहे हैं । इस प्रश्न पर हम पहले ही 35 मिनट खर्च कर चुके हैं । यदि सभा की यह इच्छा है कि इस प्रश्न को एक घंटा दिया जाये तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

Shri Madhu Limaye : Sir, had my suggestion been accepted and Question Nos. 151, 152, 153, 155 and 156 been taken together, we would have finished five questions as also all the hon. Members would have got an opportunity.

श्री को० सूर्यनारायण : क्या सरकार को पता है कि गोदावरी जैसे अधिक मात्रा वाले क्षेत्रों में खाद्य निगम एक ही किस्म के चावल के लिए साधारण व्यापारियों की अपेक्षा उपभोक्ताओं से अधिक मूल्य ले रहे है ।

अध्यक्ष महोदय : हम उन ब्यौरों में जा रहे हैं जो इस प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आते ।

श्री नाथ पाई : पिछले सत्र में एक प्रश्न के उत्तर में श्री जगजीवन राम ने बताया था कि वह आशा करते हैं कि मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में एक राष्ट्रीय खाद्य बजट तैयार कर लिया जायेगा । सम्मेलन हो चुका है, परन्तु बजट तैयार न किये जाने का कारण अब यह बताया जाता है कि पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। क्या एक राष्ट्रीय बजट तैयार न करने का यह कारण है या इसका यह कारण है कि केन्द्रीय सरकार ने इस दिशा में अग्रसर होने से इन्कार कर दिया ?

(ख) क्या कुछ राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने यह भी सुझाव दिया था कि उन्हें सीधे ही खाद्य आयात करने की अनुमति दी जाये और यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं ? आपने अपने पत्र में मेरे मित्र श्री बरूआ को एक प्रकार का उतर दिया है । मैं इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ क्योंकि हम यह सुनते रहते हैं कि कुछ राज्यों के मुख्य मंत्री सीधे आयात करने की स्थिति में हैं और केन्द्रीय सरकार उनके मार्ग में बाधक सिद्ध हो रही है । क्या सरकार ने इस नीति सम्बन्धी प्रश्न पर विचार किया है ?

श्री जगजीवन राम : (क) अलबत्ता विभिन्न राज्यों को तथा मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में एक प्रकार का एक राष्ट्रीय बजट परिचालित किया गया था, यह महसूस किया गया था कि उसमें जो तिथि रखी गई थी वह सभी राज्यों को स्वीकार्य न थी। केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के प्राधिकारों का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं था । इस मामले में हमारे पास कोई सांवैधानिक प्राधिकार नहीं है । खाद्य तथा कृषि एक राज्य का विषय है और राज्य सरकारों की सद्भावना से ही हम कार्य कर सकते हैं ।

श्री नाथ पाई : राष्ट्र को बचाने के लिये एक राष्ट्रीय बजट आवश्यक है ।

श्री जगजीवन राम : यह महसूस किया गया था और मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूँ कि एक राष्ट्रीय खाद्य बजट तैयार करने के लिये विभिन्न राज्यों के उत्पादन के आंकड़ों और विभिन्न राज्यों के तरीकों और एक ही राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में उपभोग के तरीकों की पूरी जांच करना आवश्यक होगी । अतः यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ख) किसी राज्य सरकार द्वारा ऐसा सुझाव नहीं दिया गया था ।

श्री नाथ पाई : आपका क्या रवैया है ?

श्री जगजीवन राम : मैं किसी वैकल्पिक प्रश्न का उत्तर देने को तैयार नहीं हूं।

श्री न० कु० सांघी : यह एक मानी हुई बात है कि देश में अनाज का बड़ा संकट है। क्या फसलों के कीटाणुओं और चिड़ियाओं को नष्ट करने के लिये सरकार किसी राष्ट्रीय नीति पर विचार कर रही है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इसका मुख्य प्रश्न से क्या सम्बन्ध है ?

Shri Kachwai : The Shohdol District of Madhya Pradesh is facing a very grim food situation and the people there have to sustain themselves on tree leaves. Have Government ensured the proper distribution of the foodgrains sent to that district ? Madhya Pradesh Government had stated that it had procured 5 lakh quintal of wheat, 7 lakh quintal of millets and 29 lakh quintal of gram. What quantity was sent for distribution to those districts from where procurement was made and have those persons been given the liberty to sell their produce in the market after the levy has been realised from them, if not what steps the Central Government propose to take in this matter ?

Shri Jagjivan Ram : All these questions should be put to the State Governments, I am not at all concerned with these.

Shri Hukam Chand Kachwai : Are Government in a position to say that the distribution was properly carried out ?

श्री जगजीवन राम : यह केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। जहां तक राज्यों के बीच वितरण का सम्बन्ध है राज्य सरकारें ऐसा करने के लिये पूरी तरह सक्षम हैं।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : खाद्य मंत्री के अपने वक्तव्य के अनुसार कि राज्य के अन्न क्षेत्रों ने यह स्थिति पैदा कर दी है कि अमरीका से कमी वाले राज्यों के लिए अन्न का आयात सरल है बहुतायात वाले राज्यों की अपेक्षा तथा वसूली के मामले में भी अमरीका से अन्न मिलना सरल है वहां के क्षेत्र की अपेक्षा तथा उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने कहा है कि उन्हें वसूली के लिए 90 रु० प्रति क्विन्टल देना पड़ता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए क्या खाद्य मंत्री वसूली मूल्यों में समानता लाने तथा राज्य खाद्य खण्डों को समाप्त करने का प्रस्ताव रखते हैं ?

~~खाद्य तथा कृषि मंत्री~~ **(श्री जगजीवन राम)** : मेरे विचार में वसूली तथा वसूली के मूल्यों में कोई समानता नहीं हो सकती। इन बातों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्य सरकारों ने केन्द्र से प्रार्थना की तथा खाद्यान्न की वसूली के बारे में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों के अभ्यावेदन स्वीकार कर लिए हैं।

श्री जेवियर : अन्न की वसूली तथा वितरण के लिए प्रत्येक राज्य में जिला सप्लाई अधिकारी तथा उनके कर्मचारी, तालुक सप्लाई अधिकारी तथा उनके कर्मचारी तथा ग्राम अधिकारी हैं। राज्यों की राजधानियों में सिविल सप्लाई आयुक्त हैं। इन बातों को देखते हुए

क्या सरकार खाद्य निगम को अनावश्यक समझते हुए समाप्त करने का विचार रखती है तथा उस धन को अन्न की दूसरी योजनाओं में लगाने का विचार रखती है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या सरकार निजी व्यक्तियों की भान्ति राज्य सरकारों को विदेशों से अन्न आयात करने के लिए लाईसेंस देने को तैयार है ?

श्री जगजीवन राम : यह एक काल्पनिक प्रश्न है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह काल्पनिक नहीं है। इस मांग कई बार विभिन्न मुख्य मन्त्रियों ने की।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : मन्त्री ने अपने वक्तव्य के चौथे पैरे में कहा है कि देश के अधिक अन्न वाले तथा फालतू अन्न वाले राज्यों से अन्न की वसूली तेजी से की जायेगी। कमी वाले राज्य अपनी कमी के बारे में बढ़ा कर कहते हैं तथा फालतू अन्न वाले राज्य अपने अन्न को कम बताते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार उत्पादन के वास्तविक आंकड़ों को प्राप्त करने का प्रस्ताव करती है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इन सारे प्रश्नों पर मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में चर्चा हुई। प्रत्येक राज्य में भिन्न स्थिति है। हम एक दूसरे की कठिनाईयों को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : मन्त्री महोदय यह कह कर पीछा छुड़ा रहे हैं कि यह राज्य का विषय है। क्या केन्द्रीय सरकार ने एक राष्ट्रीय अन्न बजट के प्रश्न पर विचार किया है तथा खाद्य क्षेत्रों को समाप्त करके सारे देश का एक खाद्य क्षेत्र बनाने पर विचार किया है अथवा वे राज्यों के सामने झुकते जा रहे हैं ?

श्री जगजीवन राम : मैंने जो मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में हुआ उसके तथ्य बताये हैं तथा यह भी कि हमें अपने प्रयत्नों में मुख्य मन्त्रियों को साथ लेना होगा तथा यह जिम्मेदारी मिलकर निभानी होगी। सारे क्षेत्रों को समाप्त करने के प्रश्न पर विचार किया गया है परन्तु वर्तमान स्थिति में उनका बनाये रखना ही ठीक समझा है।

अध्यक्ष महोदय : कल से मैं पीछे बैठने वाले सदस्यों को ही बोलने की अनुमति दूंगा।

Shri R. Shastri : Is it a fact that at the Chief Ministers' and Food Ministers Conference it was suggested that in national food budget every person would at an average get 128 kilograms of food per head per year. If so why the States of Bihar and Kerala were given food at the rate of 110 kilograms per head per year and whether people in those states consume less than their counterparts in other states?

Shri Jagjivan Ram : The national food budget has not been accepted and so the figures about it need not be quoted here.

Shri Valmiki Choudhary : Will the Minister inform whether he is satisfied with the talks which he had with the State Food Ministers and Chief Ministers and if so why his statement is contradicting that ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : उस चर्चा के बाद जो मतैक्य हुआ उस पर यह नीति बनाई गई है।

Starvation Deaths

152. Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Mohan Swarup :
Shri D. N. Deb :
Shri P. K. Deo :
Shri K. P. Singh Deo :
Shri S. Supakar :
Shri Chintamani Panigrahi :
Shri Yashpal Singh :
Shri N. K. Sanghi :
Shri P. Gopalan :
Shri Surendra Nath Dwivedy :
Shri Hem Barua :
Shri Vishwa Natha Menon :
Shri K. M. Abraham :
Shri Uma Nath :
Shri P. P. Esthose :
Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri R. S. Vidyarthi :
Shri B. S. Sharma :
Shri Virendra Kumar Shah :
Shri S. M. Banerjee :
Shri Madhu Limaye :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri George Fernandes :
Shri Manibhai J. Patel :
Shri Sidheshwar Prasad :
Shri D. C. Sharma :
Shri Eswara Reddy :
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Jagan Nath Rao Joshi :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Shrda Nand :
Shri Bharat Singh :
Shri Ranjit Singh :
Shri Onkar Singh :
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Y. A. Prasad :
Shri Arjun Singh Bhadoria :
Shri D. N. Patodia :
Shri Meetha Lal :
Smt. Jyotsna Chanda :
Shri R. Barua :
Shri C. C. Desai :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri Nathu Ram Ahirwar :
Shri K. N. Pandey :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of persons reported to have died of starvation in the country from January to April, 1967, State-wise, giving the names of places ;

(b) whether any measures have been devised by Government to check such deaths ; and

(c) if so, the steps taken for their implementation ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Anna Sahib Shinde) : (a) to (c) : Statement is placed on the Table of the House.

Statement.

(a) All reports about starvation deaths whether appearing in newspapers or brought to the notice of the Government of India otherwise are referred by them to the State Governments for investigation and report. None of the reported starvation deaths has so far been confirmed by any of the State Governments.

(b) and (c) The State Governments have organised a large number of relief works in the affected areas in order to provide purchasing power for the people. For those unable to do hard manual work, light Manual schemes have also been organised. For old and infirm persons and others who cannot work to earn their livelihood, arrangements have been made to provide gratuitous relief in the form of cash and free supply of foodgrain and free kitchens are also being run by voluntary organisations to provide free food to such people. A large emergency feeding programme to cover vulnerable sections of the population namely children, expectant and nursing mothers has been organised by CARE. 23,500 tonnes of gift wheat and 12,000 tonnes of gift milk powder have so far been allotted to the affected States for gratuitous relief and for milk feeding programmes. 4,787 tonnes of wheat placed at the disposal of the Prime Minister's Drought Relief and 1,617 tonnes of wheat from Government stocks have been released to voluntary organisations for runnig free kitchens.

Government of India are extending necessary financial assistance to the State Governments for organising as many relief programmes as may be necessary. No ceiling has been laid for organising relief programmes. Allotment of allocations of foodgrains to the effected States has been increased to the extent possible in order to provide sufficient foodgrains in the fair price shops in the effected areas.

Shri Onkar La' Berwa : Sir, I have not got the Statement and as such it should be read over to the House.

अध्यक्ष महोदय : जिन सदस्यों को यह वक्तव्य नहीं मिला है । वे उसे टेबल ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं ।

श्री पीलु मोडी : मेरा सुझाव यह है कि दोपहर के भोजन के समय हम सभा की कार्यवाही स्थगित न करें ताकि प्रश्न काल के लिए दो घंटे मिल सकें ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

Shri Onkar Lal Berwa : From the statement it appears that Government does not trust the journalists and the non - Congress Governments but it trusts the congressmen of those States in regard to the news about starvation deaths. I am quoting the people who died as a result of starvation. Their number was 39 in Madhya Pradesh, 119 in Bihar, 65 in U. P. and 9 in Rajasthan. These figures were quoted in the State Assemblies. I want to know whether Government accepts these figures or not.

Shri Jagjivan Ram : About these matters we do not have an agency of our own. We accept the figures which the State Governments send to us. No State Government has so far confirmed about the reported deaths as mentioned by the hon. Member.

Shri Onkar Lal Berwa : You do not accept the version of cinema, the press and the State assemblies. What else do you accept then as true ?

Shri Jagjivan Ram : We ask the State Governments to investigate these facts and then accept the version of State Governments.

श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : सरकार केवल भूख से हुई मौत की चिन्ता करती है परन्तु जहां यह होने वाली हैं वहां ध्यान नहीं देती । क्या सरकार को पता है कि गुजरात राज्य

के पंच महल, छोटा उदयपुर तथा जूनागढ़ जिलों में ऐसी स्थिति है कि वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर भूख से मौतें हो। यदि हां तो उन क्षेत्रों में समय पर खाद्यान्न भेजने के बारे में सरकार क्या कर रही है ?

श्री जगजीवन राम : हां गुजरात के कुछ क्षेत्रों में वर्षा न होने के कारण सूखा की स्थिति है। मुख्य मंत्री ने हम से वहां के लिए कुछ खाद्यान्न देने के लिए कहा और मैं आदिवासियों में बांटने के लिए 1,000 टन गेहूं देने की अनुमति दे रहा हूं।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : भूखमरी के कारण मौत होने के समाचार कुछ मन्त्रियों के वक्तव्यों में छपे हैं। क्या सरकार ने इन वक्तव्यों की सच्चाई के बारे में जांच की है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हमने इस प्रकार के वक्तव्यों को विभिन्न राज्य सरकारों के पास भेजा परन्तु अभी तक किसी राज्य सरकार ने ऐसी सूचना नहीं दी जिससे यह पता लगे कि भूखमरी के कारण मौत हुई हैं।

मनीआर्डरों का भुगतान न किया जाना

अ०सू०प्र० संख्या 3. **श्री क० ना० तिवारी** :
श्री कार्तिक ओरओं :
श्री प्र०कु० घोष :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सारे देश में मनीआर्डरों का भुगतान न किये जाने के बारे में बहुत सी शिकायतें मिली थीं; और

(ख) यदि हां, तो कितने मनीआर्डरों का भुगतान कर दिया गया है और कितनों का अभी भुगतान किया जाना शेष है ?

संसद कार्य तथा संचार मंत्री (डा०रामसुभग सिंह) : (क) तथा (ख)—15 मार्च से 15 मई, 1967 तक मनीआर्डर और तार मनीआर्डरों की अदायगी न होने के बारे में मुझे 92 शिकायतें मिली थीं। इनमें से 32 की अदायगी पहले ही की जा चुकी है। शेष मनीआर्डरों और तार मनीआर्डरों की अदायगी की कार्रवाई की जा रही है। 1966 में 3,85,071 शिकायत मिली थीं। इनमें से वर्ष के अन्त में केवल 40,586 शिकायतें अनिर्णीत रह गई थीं।

Shri K. N. Tiwary : Whether enquiries about other complaints are being conducted and when are they likely to be decided and payment made ?

Dr. Ram Subhag Singh : Orders have been issued to make payments in respect of case pertaining to July last and which have not yet been paid.

Shri K. N. Tiwary : What was the total amount of money orders and the amounts paid out of that and also amount yet to be paid?

Dr. Ram Subhag Singh : In a year the number of money orders which we receive is about 6,20,00,000 involving at an average a sum of Rs. 4420 million. The complaints pertain to Rs. 3,45,500 which is 4 percent.

श्री कार्तिक ओरांओं : जो मनी आर्डर बिहार, छोटा नागपुर, रांची तथा पालामौ जिले के हैं उनकी अलग-अलग कितनी राशि है ?

डा० राम सुभग सिंह : यह सूचना मैं एकत्रित करके दूंगा ।

श्री प्र० कु० घोष : मनी आर्डर तथा पत्र और तारों के देने के बारे में कई बार शिकायतें आती हैं, उनके शीघ्र पहुंचाने के बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

डा० राम सुभग सिंह : उसके बारे में हम एक विशेष प्रयत्न कर रहे हैं और मेरे विचार में जुलाई के अन्त तक तीन मास में कोई भी बकाया नहीं रहेगा । पत्र तथा तार का अलग मामला है ।

श्री कन्डप्पन : विभाग के बढ़ जाने के बाद भी मनी आर्डर समय पर नहीं दिये जाते । क्या सरकार ने इस देरी के कारण जानने के तथा उन्हें हटाने के बारे में कोई कार्यवाही की है ?

डा० राम सुभग सिंह : हम इसके लिये विशेष प्रयत्न कर रहे हैं तथा जुलाई 1967 तक उन्हें समाप्त कर दिया जायेगा ।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : देश के हजारों निरक्षर लोगों को कुछ पेशेवर लोगों पर आश्रित रहना पड़ता है जो उनके मनीआर्डर बड़ी जल्दी में भरते हैं । इस स्थिति को सुधारने के लिए मन्त्री महोदय क्या कर रहे हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : यह सच है । इसके लिए मैं एक नई संहिता बनाने का प्रयत्न करूंगा और यदि कोई निरक्षर व्यक्ति है विशेषकर स्त्री तो उसे डाक खाने के कर्मचारी सहायता कर सकें ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मन्त्री महोदय के ध्यान में यह बात आई है कि मनी-आर्डरों की अदायगी में बहुत देर हो जाती है और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में । यह देर विभाग के व्यक्तियों द्वारा नहीं अपितु अन्य व्यक्तियों द्वारा होती है । इसलिए क्या सरकार गांवों में उचित डाकखाने खोलेगी ताकि मनीआर्डर समय पर दिये जा सकें ?

डा० राम सुभग सिंह : हम हिदायतें दे रहे हैं कि डाक खानों की यह जिम्मेदारी होगी कि यदि एक मास में मनीआर्डर की अदायगी नहीं हुई और उसकी शिकायत प्राप्त हुई तो वह डाकखाना दस दिन के अन्दर-अन्दर उसका उत्तर देगा और यदि यह उत्तर 10 दिन में नहीं दिया तो उस मनीआर्डर की अदायगी की जायेगी ।

Shri Nathu Ram Ahirwar : In view of the fact that the money orders are sent in extra cover how is it that they are lost ?

Dr. Ram Subhag Singh : Some times there is misappropriation. Hence we have launched this drive and will stop it.

श्री विश्वनाथन : जब किसी मनी आर्डर की अदायगी न हो तो क्या सरकार यह करने को तैयार है कि पहले उस व्यक्ति को अदायगी करे तथा बाद में जो व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार है उस पर मुकदमा चलाये और रुपया वसूल करे ?

डा० राम सुभग सिंह : हम हिदायत दे रहे हैं कि यदि अदायगी एक मास में नहीं होगी और उसके बारे में शिकायत प्राप्त होती है तो डाकखाना 10 दिन में एक रजिस्टर्ड पत्र भेजेगा और यदि 10 दिन में कोई उत्तर नहीं मिलता है तो उस मनीआर्डर की दोबारा अदायगी होगी।

Shri Sheo Narain : How much amount is still in balance and whether action has been taken against the defaulting officers and employees or not and whether any one of them has been suspended or dismissed ?

Dr. Ram Subhag Singh : We have issued orders of disciplinary action in many cases. As I stated in reply to main question 40,586 cases are pending. I can assure the hon. Member if any body's fault is proved there will be no difficulty in taking disciplinary action against him.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

सूखाग्रस्त क्षेत्रों से लोगों का प्रव्रजन

153. **श्री देवकीनन्दन पटोदिया :**
श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी
श्री रा० बरुआ :
श्री जी० एस० मिश्र :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले एक वर्ष में देश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग भोजन तथा जीविका की तलाश में निकटवर्ती क्षेत्रों में चले गये हैं,

(ख) यदि हां तो इस अवधि में प्रव्रजन करने वाले लोगों की कुल संख्या कितनी है और किन-किन स्थानों से यह प्रव्रजन हुआ है, और

(ग) क्या सरकार ने लोगों का प्रव्रजन रोकने और उनको पर्याप्त अनाज तथा अन्य साधन उपलब्ध कराने के लिए कोई कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : भारत सरकार को गत वर्ष सूखे के कारण बड़े पैमाने पर लोगों के दूसरे स्थानों पर चले जाने के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। 1965–66 और 1966–67 में सूखे से प्रभावित सभी राज्य सरकारों को इसके तथ्य मालूम करने के लिये कहा गया था। उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, मैसूर आन्ध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्यों ने सूचित किया है कि सूखे के कारण बड़े पैमाने पर लोग दूसरे स्थानों पर नहीं गये थे। बिहार, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों से जानकारी अभी प्राप्त होनी है और प्राप्त होने पर उसे सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) सामान्यतया लोग धन और खाद्य के अभाव में दूसरे स्थानों पर जाते हैं। सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में राज्य सरकारों ने प्रभावित जनसंख्या की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए पर्याप्त संख्या में सहायता कार्य खोले हैं। कुल उपलब्धि तथा अन्य राज्यों की आवश्यकताओं को देखते हुये सूखे से प्रभावित राज्यों को अधिकतम सम्भव सीमा तक खाद्यान्नों का आवंटन किया गया है। सूखे से प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों में बहुत बड़ी संख्या में उचित मूल्य की दुकानें चल रही हैं।

Super Bazar, New Delhi

154. Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri D. C. Sharma :
Shri P. K. Deo :
Shri K. P. Singh Deo :
Shri G. C. Naik :
Shri A Dipa :
Shri R. S. Vidyarthi :
Shri Sharda Nand :
Shri Bharat Singh :
Shri Ranjit Singh :
Shri Ram Kishan Gupta :
Shri S. C. Samanta :
Shri A. K. Kisku :
Shri S. N. Maiti :
Shri Tridib Kumar Chaudhuri :
Shri Yashpal Singh ;
Shri Mohan Swarup :
Shri Madhu Limaye :
Shri Ram Manohar Lohia :
Shri S. M. Joshi :
Shri George Fernandes :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Sidheshwar Prasad :
Shri K. N. Pandey :
Shri D. N. Deb :
Shri S. K. Tapuriah :
Shri D. N Patodia
Shri Mohammad Imam ;
Shri Gadilingana Gowd :
Smt. Sharda Mukerjee :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Super Bazar, New Delhi is running at a loss;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) the amount of loss suffered by each Department separately; and

(d) the steps taken or proposed to be taken in the matter ?

The Minister of state in the Ministry of food Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) The correct profit and loss account of a cooperative store can only be seen from its audited balance sheet after the close of the cooperative year i. e. June 30. Tentative financial statements of the Super Bazar, however, for the period ending 31st December 1966 which were placed before the Managing Committee revealed a deficit of Rs. 4.30 lakhs.

(b) The deficit is attributable to the following reasons :

(i) Initial developmental expenditure involved in setting up a big store at high speed.

(ii) High rent of the building.

(iii) Unsatisfactory designing of the building for purposes of a department store-necessitiating deployment of a large staff.

(iv) Delay in the installation of lifts-in the absence of which goods had to be carried up to the upper floors through manual labour.

(c) Account have not been maintained department-wise.

(d) Attempts are being made to reduce the sale-expense ratio by increasing turnover and to cut down administrative and other costs viz. on staff, advertisement, stationery, packaging material, etc. to the maximum extent possible. The Managing Committee of the Super Bazar has also appointed a sub-committee under the chairmanship of Dr. P. S. Lokanathan to examine the working of the store and to suggest imporvements. The report of the committee is likely to be available by August 1967.

Central Food Grains Assistance to U. P.

155. Shri Mohan Swarup ;
Shri S. M. Banerjee :
Shri Madhu Limaye :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri S. C. Samanta ;
Shri A. K. Kisku ;
Shri S. N. Maiti :
Shri Tridib Kumar Chaudhuri :
Shri Yashpal Singh :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri K. N. Pandey :
Shri N. K. Sanghi :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Uttar Pradesh have made a request to the Central Government to make more foodgrains available to the State for being supplied to Mirzapur and other drought-stricken areas;

(b) if so, the reaction of Government in this regard; and

(c) the other steps taken to relieve drought condition in Uttar Pradesh ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) and (b) : Monthly quota of 1,25,000 tonnes was made to U. P. for the months of February, March and April 1967 and the quantities despatched were as follows :

February 1967	95,000 tonnes
March 1967	1,45,000 tonnes
April 1967	1,12,600 tonnes

In view of the good rabi crop the quota has been reduced to 1,10,000 tonnes for the month of May. The Food Minister of U. P. recently met the Union Minister of Food & Agriculture and requested him to make some larger-allocation or at least to restore the quota to the previous level of 1,25,000 tonnes. Subject to the availability with the Government of India and the need to meet the minimal demands of other deficit States, the request of the U. P. Food Minister will be considered.

(c) ; A statement is laid on the Table of the House.

Statement

8,000 tonnes of gift wheat have been allotted to U.P. for free distribution. Out of this quantity, 1000 tonnes was released to the State Government with the suggestion that this may be used exclusively in Mirzapur district. 3,444 tonnes of gift milk powder have been allotted to the State for free feeding programmes for the benefit of children and expectant and nursing mothers. 70 tonnes of biscuits and 12 tonnes of dry raisins have also been allotted.

The Ministry of Health and Family Planning have allotted a substantial quantity of vitamin tablets, baby food, medicines, etc., to ward o.f or co.nba' diseases resulting from scarcity conditions.

Drinking water schemes estimated to cost Rs. 372 lakhs have been approved. The UNICEF have donated 4 rigs for the drilling of wells. The Ministry of Finance have sanctioned a loan of Rs. 90 Lakhs for relief operations. The Ministry of Food and Agriculture have sanctioned Rs. 628.52 lakhs as short-term loans for purchase of inputs like fertlizers, pesticides and seeds.

A number of voluntary organisations are running free kitchens in the State. To assist them, they have been given, so far, about 281 tonnes of wheat at economic prices. The Prime Minister's Drought Relief Fund has so far released 651 tonnes of wheat to voluntary organisations in U. P. for running free kitchens. The Department of Food have purchased from the Army 6 jeeps and 4 trucks and have placed them at the disposal of the U. P. Drought Relief Committee. A jeep had been made available to the Ramakrishna Mission and another one is being made available to them. The Government of Uttar Pradesh have been allotted 10 vehicles for relief operations from gifts received from abroad.

बिहार में अकाल की घोषणा

156. **श्री के० अनिरूद्धन :**
श्री वी० विश्वनाथ मेनन :
श्री के० एम० अब्राहम :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री उमानाथ :
श्री एस्थोस :
श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्य सरकार द्वारा बिहार के कुछ जिलों को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित किये जाने के पक्ष में नहीं थी; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : राज्य में किसी क्षेत्र को अकाल वाला क्षेत्र घोषित करना पूर्णतया राज्य सरकार के अधिकार में है और इस प्रकार की घोषणा करने से पूर्व उनके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे भारत सरकार से परामर्श करें। तथापि, बिहार सरकार ने

अनौपचारिक रूप से इस मामले में भारत सरकार से परामर्श किया था और उन्हें यह सलाह दी गयी थी कि राज्य और केन्द्रीय सरकारें संकट से निजात दिलाने के लिए प्रत्येक सम्भव कार्य कर रही हैं और इस अवस्था में अकाल की घोषणा करने का कोई लाभ नहीं होगा। उन्हें यह भी बताया गया कि दूसरी ओर यह खतरा था कि इस घोषणा से और अधिक कमी की भावना पैदा हो सकती थी जिससे खुले बाजार में खाद्यान्नों के भावों में वृद्धि और खाद्यान्नों को छिपा लेने की स्थिति पैदा हो सकती थी।

निर्वाचन अर्जियां

157. **श्री दामानी :** **श्री रणजीत सिंह :**
श्री विभूति मिश्र : **श्री यशपाल सिंह :**
श्री क० ना० तिवारी : **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :**
श्री श्रद्धाकार सूपकार : **श्री राने :**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : **श्री राम किशन गुप्त :**
श्री शरदा नन्द : **श्री मोहसिन :**
श्री भारत सिंह : **श्री सेझियान :**

क्या **विधि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं के लिए निर्वाचित हुए अभ्यर्थियों के विरुद्ध, हाल के साधारण निर्वाचनों के सम्बन्ध में क्रमशः कितनी निर्वाचन अर्जियां दायर की गई हैं;

(ख) प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय साधारण निर्वाचनों के पश्चात् दायर की गई निर्वाचन अर्जियों की तुलना में इनकी संख्या कितनी है; और

(ग) इनको निपटाने में कितना समय लगने की सम्भाव्यता है ?

विधि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री० दा० रा० चव्हाण) : (क) उच्च न्यायालयों के समक्ष 314 निर्वाचन अर्जियां फाइल की गई हैं, जिनमें से 268 विधान सभा निर्वाचनों और 46 लोक-सभा निर्वाचनों के सम्बन्ध में हैं। जम्मू कश्मीर विधान सभा के लिए निर्वाचनों के सम्बन्ध में 56 अर्जियां, जम्मू-कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार, निर्वाचन आयोग के समक्ष फाइल की गई हैं।

(ख) प्रथम, द्वितीय और तृतीय साधारण निर्वाचनों में फाइल की गई निर्वाचन अर्जियों की संख्या इस प्रकार है :—

	लोक सभा	विधान सभा	योग
1952......	39	286	325
1957......	59	413	472
1962......	46	298	344

(ग) उच्च न्यायालयों को, अपने समक्ष फाइल की गई अर्जियों को निपटाने में जो समय लगने की सम्भाव्यता है, उसके बारे में कोई प्राक्कलन देना सम्भव नहीं है।

अकाल संहिता

158. **श्री प्र० के० देव :**
श्री का० प्र० सिंह देव :
श्री धीरेन्द्रनाथ :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री हेमराज :
श्री श्रद्धाकार सूपकार :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अकाल संहिता का हाल में पुनरीक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : स्वतन्त्रता के पश्चात की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये सम्बन्धित राज्यों ने राज्य अकाल/अभाव संहिता/नियम पुस्तिकाओं के कुछ उपबन्धों में संशोधन किये हैं। पुरानी संहिताओं और गत वर्ष की दशा में मुख्य अन्तरों को स्पष्ट करने वाले दो विवरणों को 9 अगस्त 1966 और 7 अप्रेल 1967 को सभा पटल पर रखा गया था।

सड़क परिवहन कराधान जांच समिति का प्रतिवेदन

159. **श्री राम किशन गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :
डा० रानेन सेन :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री हीरजी भाई :
श्री ख० प्रधानी :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री ४ अप्रैल, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 478 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सड़क परिवहन कराधान जांच समिति के प्रतिवेदन पर इस बीच विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) कमीटी की अन्तरिम रिपोर्ट अभी विचाराधीन है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

आसाम में नदी स्टीमर सेवा

160. **श्री रा० बरुआ :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री मधु लिमये :
श्री स० मो० बनर्जी :

डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री हेम बरुआ :**
श्री जार्ज फरनेन्डीज : **श्री नाथपाई :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त : **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :**
श्री काशीनाथ पांडे :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम की रिवर स्टीम नैवीगेशन कम्पनी लिमिटेड तथा इण्डियन जनरल नेवीगेशन एण्ड रेलवे कम्पनी लिमिटेड जो स्टीमर सेवा चला रही है, ने प्रबन्ध नये एकक को सौंप दिया है,

(ख) क्या वर्तमान कर्मचारियों की सेवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की गई और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है,

(ग) क्या ब्रह्मपुत्र नदी पर एक के बाद एक बन्द होने वाले घाटों का बन्द होना रोक दिया जायेगा, और

(घ) सरकार इस महत्वपूर्ण जल परिवहन व्यवस्था को सभी प्रकार से नष्ट भ्रष्ट होने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (घ) : अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है । [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 429/67**)

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमान इन्जीनियर

161. **श्री मधु लिमये :** **श्री स० मो० बनर्जी :**
डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन, कलकत्ता के विमान इन्जीनियरों ने अप्रैल, 1967 में नियमानुसार तथा व्यवसाय अनुसार काम करने का तरीका अपनाया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इससे इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की सेवाओं में अव्यवस्था पैदा हो गई थी; और

(घ) क्या तब से प्रबन्धकों तथा इन्जीनियरों के बीच कोई समझौता हो गया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) (क) : जी हां ।

(ख) : वेतन-मानों, भत्तों तथा सेवा की अन्य शर्तों के पुनरीक्षण के बारे में आई० ए० सी० के प्रबन्धकों और अखिल भारतीय विमान इन्जीनियर संस्था (आल इण्डिया एयर-

क्राफ्ट इन्जीनियर्स एसोसियेशन) के बीच हुए दिनांक 26. 12. 66 के समझौते को क्रियान्वित करने में अभिकथित देर हो जाने के कारण आई० ए० सी०, कलकत्ता के विमान इन्जीनियरों ने 8 अप्रैल से 12 अप्रैल, 1967 तक "नियम-अनुसार" तथा "व्यवसाय-अनुसार" काम करने का तरीका अपनाया था।

(ग) : जी, हां।

(घ) : जी, हां। समझौते को क्रियान्वित कर दिया गया है।

कृषि में अनुसन्धान और शिक्षा

162. **श्री नि० रं० लास्कर :** **श्री मोहन स्वरूप :**
श्री लीलाधर कटकी : **श्री श्रीगोपाल साबू :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृषि में अनुसन्धान और शिक्षा सम्बन्धी स्नातकोत्तर केन्द्रों को सुदृढ़ बनाने के लिये कोई नीति निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) कृषि में सुधार लाने के लिये और क्या उपाय किये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : पूछी गई जानकारी का एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 430/67]**

राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्र

163. **श्री बेनी शंकर शर्मा :** **श्री पन्नालाल बारूपाल :**
श्री रा० कु० बिड़ला : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के उन सूखाग्रस्त क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां अकाल जैसी स्थिति है;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने स्थिति का मुकाबला करने के लिये केन्द्रीय सरकार से आवश्यक सहायता मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य. कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) अलवर, गंगानगर और भरतपुर जिलों को छोड़कर राजस्थान के अन्य सभी जिले कमी और सूखे से प्रभावित हुये हैं।

(ख) और (ग) : 1966-67 में राजस्थान सरकार को सहायता कार्यों के लिये अब तक कुल 11.50 करोड़ रु० की वित्तीय सहायता सुलभ की गयी है। उर्वरक, बीज तथा कीटनाशक दवाइयां जैसे इनपुट खरीदने के लिये 3.48 करोड़ रुपये का अल्प कालीन ऋण भी दिया गया था। पीने के पानी की कमी दूर करने के लिये राज्य सरकार को नलकूपों को बिजली से चलाने हेतु 45.91 लाख रुपये का एक त्वरित ऋण सहायता भी स्वीकार की गयी थी। राज्य में मौजूदा सूखे की स्थिति का सामना करने के लिये भारत सरकार ने मुफ्त वितरण के लिये 1500 मीटरी टन उपहार गेहूं अलाट किया है।

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन तथा एयर इण्डिया द्वारा संचालित आधुनिक परिवहन विमान

164. **डा० कर्णीसिंह** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन तथा एयर इण्डिया द्वारा संचालित आधुनिक परिवहन विमान, तूफान के समय उड़ते हुए बिजली गिरने के खतरे से पर्याप्त सुरक्षित हैं; और

(ख) भारत में प्रयोग किये जाने वाले उस विमान का नाम और किस्म क्या है, जो इस प्रकार से सुरक्षित नहीं है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) (क) : जी हां।

(ख) : भारत में परिचालित होने वाले सभी वायुयान समुचित रूप से सुरक्षित (बौंड) किये गये हैं।

विधायकों के लिये आचार संहिता

165. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री हेम बरुआ :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री राम किशन गुप्त :
श्री वी० कृष्णमूर्ति :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री मधु लिमये :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग के पास ऐसी कोई प्रस्थापना है कि विधायकों (राज्य तथा केन्द्रीय) के लिए आचार संहिता बनाई जाये जो उनके निर्वाचित हो जाने के बाद विपक्ष में शामिल होने के बारे में हो; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उड़ीसा में पर्यटन

166. **श्री श्रद्धाकार सूपकार :**
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में उड़ीसा में पर्यटन के स्थानों की ओर पर्यटक यातायात बढ़ाने के सम्बन्ध में कितना धन खर्च किया गया; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान उड़ीसा में वास्तुकला सौंदर्य वाले स्थानों की ओर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 431/67**]

रबी की फसल का उत्पादन

167. **श्री अब्दुल गनीदार :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री मधु लिमये :
श्री स० मो० बनर्जी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
डा० कर्णी सिंह :
श्रीमती निर्लेप कौर :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री पार्थासारथी :
श्री रा० कृ० बिड़ला :
श्री देवकीनंदन पटोदिया :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री दामानी :
श्री वी० कृष्णमूर्ति :
श्री धीरेश्वर कलिता :
डा० रानैन सेन :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं० सामंत :
श्री रा० बरुआ :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री हीरजी भाई :
श्री ख० प्रधानी :
श्री स्वैल :
श्री बैरो :
श्री कोलाई बिरुआ :
श्री किकर सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल की रबी की फसल के उत्पदान के बारे में राज्य सरकारों से कोई सूचनायें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो रबी की फसल के विभिन्न किस्मों के अनाजों के बारे में प्राप्त सूचनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फसल सामान्य उत्पादन स्तर से कम हुई है;

(घ) चालू वर्ष में प्रत्येक राज्य की अन्न सम्बन्धी आवश्यकता कितनी है;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार ने अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने वाले राज्यों को हिदायतें दी हैं कि वे कमी वाले राज्यों को अन्न सप्लाई करें; और

(च) यदि हां, तो इस बारे में अधिक अनाज़ वाले राज्यों की प्रतिक्रिया क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) अभी तक केवल किस्मों के बारे में रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। वर्तमान कृषि वर्ष की समाप्ति पर (अर्थात् जुलाई 1967 में) वास्तविक क्षेत्र तथा फसल कटाई सर्वेक्षणों की रिपोर्टें प्राप्त होंगी।

(ख) और (ग) : प्रारंभिक संकेतों के अनुसार गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष से अधिक होने की संभावना है जबकि चने की उपज में कमी होने के संकेत मिले हैं। जौ का उत्पादन पिछले वर्ष के समान रहने की संभावना है। हरियाणा, पंजाब व उत्तर प्रदेश में रबी की फसलों का उत्पादन सामान्य उत्पादन से अधिक होने की संभावना है। रबी की फसलों का उत्पादन राजस्थान, गुजरात व महाराष्ट्र में सामान्य स्तर पर रहेगा जबकि बिहार व मध्य प्रदेश में यह उत्पादन कम होने की संभावना है। प्रायः समस्त रबी वाले राज्यों में चने का उत्पादन सामान्य स्तर से कम रहने की आशा है।

(घ) राज्यों में खाद्यान्नों की आवश्यकता इन खाद्यान्नों के उत्पादन स्तर व मूल्यों, अन्य खाद्यों की उपलब्धि तथा उनके मूल्यों, जनता की क्रय शक्ति, खपत प्रतिमान, जन संख्या में वृद्धि तथा नागरीकरण आदि अनेक बातों पर निर्भर करती हैं। कुछ मदों के बारे में जानकारी उपलब्ध भी नहीं है, अतः वर्तमान वर्ष के लिए विभिन्न राज्यों की मांगों के विषय में ठीक से कुछ कहना संभव नहीं है।

(ङ) और (च) : अपनी मांग से अधिक अन्न उत्पन्न करने वाले राज्यों से खाद्यान्न या तो केन्द्रीय भण्डार के लिए प्राप्त किये जाते हैं या फालतू मात्रा केन्द्रीय सरकार द्वारा कमी के राज्यों को अलाट कर दी जाती है ताकि वह मात्रा सीधी उन राज्यों को पहुंच जाये। अधिक अन्न उत्पादन करने वाले राज्यों के साथ समय समय पर बैठकों में विचार विमर्श किया जाता है और उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपना फालतू अन्न (कुछ अभाव में रहकर भी) केन्द्र को उपलब्ध करें। कुछ अधिक उत्पादन वाले राज्यों ने 9 अप्रैल, 1967 को हुई मुख्य मन्त्रियों की बैठक में चालू वर्ष के दौरान में केन्द्रीय भण्डार को अन्न देने के बारे में कुछ विशिष्ट प्रस्ताव रखे थे।

पाकिस्तान द्वारा रोके गये जहाजों का वापस लौटाया जाना

168\. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** **श्री जगन्नाथराव जोशी :**
श्री हेम बरुआ : **श्री राम सिंह आयरवाल :**
श्री हुकमचन्द कछवाय :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान पाकिस्तान सरकार द्वारा रोके गये भारतीय जहाजों में से 178 पोत अब भी उसके कब्जे में हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें वापस लेने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० ग्रार० वी० राव) : (क) जी, हां। (ख) इन जलयानों को पाकिस्तान से मुक्त कराने के लिये राजनयिक सूत्रों के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है।

गुजरात में ग्रकाल की स्थिति

169. **श्री वीरेन्द्रकुमार शाह** :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ग्रोंकार सिंह :
श्री रामसिंह ग्रायरवाल :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य में ग्रकाल की स्थिति है;

(ख) राज्य में ग्रनाज की कमी को पूरा करने के कार्य के लिये सरकार ने कितनी धनराशि मंजूर की है;

(ग) गुजरात राज्य की खाद्यान्न की मासिक ग्रावश्यकता कितनी है ग्रौर उसके लिये खाद्यान्न की कितनी मात्रा निर्धारित की गयी है; ग्रौर

(घ) गुजरात सरकार की सहायता के लिये केन्द्रीय सरकार ने ग्रन्य क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ग्रन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) गुजरात राज्य के कुछेक गांवों में कमी की स्थिति है।

(ख) भारत सरकार ने सहायता कार्यों के लिए ग्रब तक 3.03 करोड़ रुपये स्वीकार किये हैं। कृषि ग्रादान (इनपुट) जैसे उर्वरक ग्रादि खरीदने के लिये 1.457 करोड़ रुपये की एक राशि भी दी गयी है।

(ग) गुजरात सरकार ने ग्रायातित गेहूं ग्रौर माइलो की मासिक ग्रावश्यकता ग्रनुमानत: 1,25,000 मीटरी टन बतायी थी। सीमित उपलब्धि ग्रौर बिहार ग्रौर उत्तर प्रदेश जैसे ग्रन्य सूखे से प्रभावित राज्यों की बढ़ी हुई मांग को देखते हुये गुजरात को 65,000 मीटरी टन गेहूं ग्रौर माइलों का ग्रावंटन किया जा रहा है।

(घ) राज्य सरकार को मौजूदा सूखा से प्रभावित बूढ़े ग्रौर दुर्बल व्यक्तियों में मुफ्त बांटने के लिये ग्रब तक 1000 मीटरी टन उपहार गेहूं का नियत भी किया गया है। दुग्ध चूर्ण की कुछ मात्राएं ग्रावंटित करने का प्रश्न विचाराधीन है।

Expenditure on Foodgrains Under PL 480

170. **Dr. Ram Manohar Lohia** :
Shri Madhu Limaye :
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Rabi Ray ;

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state ;

(a) the amount of expenditure incurred on foodgrains under PL 480 programme during 1966 and the amount realized from the public through sale;

(b) whether there was any difference between the import price and the sale price as also the cost per Kilo thereof to the buyer; and

(c) if so, the profit or loss as such ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) : A sum of Rs. 343.1 crores was spent by the Central Government during 1966 on purchase of 80.3 lakh tonnes of foodgrains under PL 480. The amount realized from the public through sale of PL 480 grain is not separately available as such grain is distributed along with other grain procured by the Central Government and as these stocks are distributed mostly through State Governments who issue the grain after adding their own incidental costs etc.

(b) There is a difference between the import price and the sale price of such grain. As against the import cost of wheat and milo of 45 P and 36 P per kilo prior to devaluation and 66 P and 52 P per kilo post devaluation, the issue prices ex Central stocks to State Governments and other recipients are as under :—

	Paise per kilo
Wheat	50 (upto 14.11.66)
	55 (from 15.11.66 onwards)
Milo	40 (upto 9.6.66)
	33 (from 10.6.66 to 14.11.66)
	40 (from 15.11.66 onwards)

The issue prices to the public fixed by the State Governments, however, varied from State to State and during different periods and ranged from 38 P to 91 P per kilo for wheat and from 40 P to 51 P per kilo for milo.

(c) The accounts for the year ending 31st March, 1967 have not yet been finalised. It is, however, estimated that during 1966-67, the Government of India would incur an expenditure of about Rs. 130 crores in subsidising the sale of grain from Central stocks.

पशुओं के चारे तथा भूसे का निर्यात

171. **श्री लीलाधर कटकी : श्री श्रद्धाकार सूपकार :**

श्री नि० रं० लास्कर : श्री श्रीगोपाल साबू :

क्या खाद्य तथा कृषि यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार को देश में पशुधन की वृद्धि के उद्देश्य से चारे और भूसे का निर्यात बन्द करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) देश में पशुधन की वृद्धि के लिए और कौन से उपाय किये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) पश्चिम बंगाल की सरकार से चारे व भूसे का निर्यात बन्द करने के बारे में एक सुझाव प्राप्त हुआ है।

(ख) मामला विचाराधीन है।

(ग) केन्द्रीय व राज्य सरकारों ने पशु विकास के लिए अनेक योजनायें शुरू की हैं। मुख्य ग्राम योजना, सघन पशु विकास परियोजनायें, पशु-चिकित्सा सहायता की उपलब्धि, रोगों से बचाव के लिए जीवाणु संबंधी दवाइयों का उत्पादन करना कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं। वैज्ञानिक ढंग से पशु प्रजनन के लिए अनेक पशु प्रजनन फार्मों की स्थापना की गई है।

कपास का उत्पादन

172. **श्री काशी नाथ पाण्डे :**
डा० राममनोहर लोहिया :
श्री मधु लिमये :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में विभिन्न किस्मों की कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ विशेष उपाय किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं तथा उन पर कितना धन व्यय हुआ है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) जी हां। केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं कपास उत्पादक महत्वपूर्ण राज्यों में माध्यम तथा लम्बे रेशे वाली किस्मों के उत्पादन को अधिकतम करने के लिए शुरू की गई हैं।

(ख) जानकारी देने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है।

[पुस्तकालय में **रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०** 432/67]

उर्वरकों के मूल्यों का पुनरीक्षण

173. **श्री वी० कृष्णमूर्ति :**
श्री हेम राज :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1 अप्रैल, 1967 से रासायनिक उर्वरकों के फुटकर मूल्यों में वृद्धि कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने उर्वरकों के मूल्य बढ़ाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार से विचार विमर्श किया था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय उर्वरक पूल द्वारा बेचे जाने वाले उर्वरकों के मूल्य देशीय या विदेशी कारखानों से उर्वरकों की प्राप्ति, परिवहन आदि के खर्च को ध्यान में रखते हुए निश्चित किए जाते हैं । अवमूल्यन के फलस्वरूप आयातित उर्वरकों के मूल्य 6–6–1966 से 57.5 प्रतिशत बढ़ गए । केन्द्रीय उर्वरक पूल द्वारा बेचे जाने वाले उर्वरकों के मूल्य 31–3–1967 तक पूर्व-अवमूल्यन ही रहे और इसके फलस्वरूप सैन्ट्रल पूल को लगभग 48 करोड़ रुपये की हानि हुई । 1967–68 में केन्द्रीय उर्वरक पूल को जो हानि हुई उसको कम करने के लिए केन्द्रीय पूल द्वारा बेचे जाने वाले उर्वरकों के मूल्यों में संशोधन करना आवश्यक हो गया । 1–4–67 से मूल्यों के बढ़ने के बाद भी पूल को लगभग 15 करोड़ रुपए की हानि रहेगी ।

(ग) जी नहीं ।

खाद्यान्नों के लिए प्रयुक्त कीटनाशक दवाइयों का मानव के स्वास्थ्य पर प्रभाव

174. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में अनाज और कृषि कार्यों के लिये विभिन्न प्रकार की कीटनाशक तथा कृमिनाशक दवाइयों के प्रयोग से होने वाले घातक तथा विषैले प्रभाव की जानकारी सरकार को है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन कीटनाशक तथा कृमिनाशक दवाइयों से मानव के स्वास्थ्य पर होने वाले समूचे विषैले प्रभाव की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त करने का है;

(ग) यदि हां, तो कब; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने 2–6–1964 को प्रो० एम० एस० थंकर की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी । समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिस पर विचार हो रहा है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध की सप्लाई

175. **श्री शारदा नन्द :**
श्री भारत सिंह :
श्री रणजीत सिंह :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री रामकिशन गुप्त :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना कार्ड होल्डरों को दूध की सप्लाई में दो वर्ष पहले की गई कटौती को समाप्त नहीं कर सकी है; **और**

(ख) यदि हां, तो सरकार ने कम से कम कार्ड होल्डरों को पर्याप्त मात्रा में दूध उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) गर्मियों के महीनों में दूध की कमी को पूरा करने के लिये दिल्ली दुग्ध योजना ने निम्न उपाय किये हैं:—

(एक) ग्रीष्म ऋतु में दूध के समाहार की मात्रा में सामान्य कमी को पूरा करने के लिये आयातित स्किम्म स्किम्ड दूग्ध चूर्ण का प्रबन्ध किया गया है।

(दो) मक्खन का भण्डार बनाया गया है जिसे कि पुन: दुग्ध तैयार करने के लिये काम में लाया जा सकता है।

(तीन) दिल्ली दुग्ध योजना को दूध का संभरण करने के लिये ठेकेदारों के साथ पक्के करार किये गये हैं। करार में यह दिया गया है कि शर्द ऋतु में दूध की 100 प्रतिशत मात्रा सप्लाई करनी होगी, वर्षा ऋतु में 75 प्रतिशत और ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश और हरियाणा के क्षेत्रों को क्रमश: 60 प्रतिशत और 50 प्रतिशत दूध की सप्लाई करनी होगी। करार के अनुसार दूध सप्लाई न करने पर ठेकेदारों को प्रति क्विंटल 5 रू० जुर्माना देना होगा।

(चार) कमी को ध्यान में रखते हुए दुग्ध योजना को पिछले वर्ष की अपेक्षा दूध का अधिक्रय मूल्य देना पड़ रहा है। दूध की सप्लाई के लिये ठेकेदारों को दिये जाने वाले कमीशन की दर में भी वृद्धि की गई है।

(पांच) दिल्ली प्रशासन द्वारा 17-5-67 से खोया, रबड़ी, पनीर तथा दुग्ध पदार्थों के आयात, निर्माण तथा बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

केरल राज्य को अनाज की सप्लाई

176. **श्री पी०सी० अदिचन :**
श्री पी० विश्वम्भरण :
श्री के०एम० अब्राहम :
श्री एस्थोस :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री मंगलाथुमाडीम :

श्री ई० के० नयानर : **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री ए० श्रीधरन : **श्री राम सिंह आयरवाल :**
श्री सी० जनार्दनन : **श्री यशवंत सिंह कुशवाह :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में राशन व्यवस्था सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पिछले तीन महीनों में राज्य सरकार ने केन्द्रीय कोटे से कुल कितना अनाज मांगा,

(ख) केन्द्रीय सरकार ने कितना अनाज दिया,

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्र से अपर्याप्त सप्लाई होने के कारण केरल में राशन व्यवस्था संकट में है, और

(घ) यदि हां, तो केरल को पर्याप्त मात्रा में अनाज की सप्लाई करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) केरल सरकार का अनोपचारिक राशन व्यवस्था के लिए अपेक्षित खाद्यान्नों का अनुमान ७० से ७५ हजार मीटरी टन चावल और १७ से २० हजार मीटरी टन गेहूं प्रति मास है।

(ख) गेहूं की आवश्कताएं पूर्ण रूप से पूरी की जा रही हैं लेकिन फरवरी से अप्रेल, १९६७ तक की अवधि में १.७८ लाख मीटरी टन चावल की मात्रा सप्लाई की जा सकी ।

(ग) देश में कुल मिलाकर चावल की कमी के कारण यह हमेशा सम्भव नहीं हुआ है कि राशन की दुकानों को चावल की पूरी सप्लाई की जाए ।

(घ) केरल में राशन व्यवस्था सम्बन्धी वायदे पूरे करने के लिये पर्याप्त मात्रा में चावल भेजने की सभी कोशिशें की जाती हैं । चावल की सप्लाई में होने वाली कमी को पूरा करने के लिए केरल में गेहूं की पर्याप्त मात्राएं पड़ी हैं ।

गत साधारण निर्वाचनों के दौरान मतदान के विरूद्ध शिकायतें

177. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत साधारण निर्वाचनों के दौरान मतदान के अनुचित संचालन के बारे में निर्वाचन आयोग को बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई थीं ;

(ख) इनमें से कितनी शिकायतों की मौके पर ही छानबीन की गई थी तथा उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) क्या निर्वाचन आयोग का वर्तमान व्यवस्थातन्त्र इन शिकायतों की तुरन्त जांच करने तथा इनको मतदान से पूर्व दूर करने के लिए यथायोग्य समझा जाता है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा०रा० चव्हाण) : (क) निर्वाचन आयोग को बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई थीं जो साधारणत: निम्नलिखित बातों के सम्बन्ध में थीं:—

(i) निर्वाचक नामावलियों में निर्वाचकों के नामों का लोप या नामों का अप्राधिकृत रूप से सम्मिलित किया जाना;

(ii) किसी स्थान विशेष में मतदान केन्द्रों का रखा जाना ;

(iii) सरकारी सेवकों का निर्वाचनों में भाग लेना और सरकारीतन्त्र का उपयोग ;

(iv) नामनिर्देशन-पत्रों का अनुचित प्रतिक्षेपण ;

(v) निर्वाचन प्रतीकों का दोषपूर्ण आवंटन ;

(vi) मतदान केन्द्र पर परिशांति भंग की आशका ;

(vii) मतदान को आरम्भ करने में विलम्ब या उसे अनुसूचित समय से पूर्व बन्द करना;

और इन में से किसी में भी मतदान के अनुचित संचालन के बारे में निर्देश नहीं था।

(ख) निर्वाचन आयोग के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह इन शिकायतों में से, जो साधारणतया अस्पष्ट हैं, हर एक की मौके पर जांच करे। जब कभी आवश्यक हुआ, मुख्य निर्वाचन आफिसरों से यह अपेक्षा कर ली गई कि वे शिकायत की जांच करें और उसकी रिपोर्ट दें ।

(ग) निर्वाचन आयोग का विद्यमान तन्त्र निर्वाचन-पूर्व शिकायतों से निपटने और निर्वाचन-पूर्व इंतजामों का पर्यवेक्षण करने के लिए यथायोग्य है । गत साधारण निर्वाचनों के अनुभव से यह स्पष्ट हो गया है कि दो मास की निर्वाचन कालावधि के दौरान आपूर्ण और अधिक प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए यह वांछनीय होगा कि इस तंत्र को प्रबल किया जाए ।

गेहूं के बीज की शीघ्र उपज वाली किस्म

179. **श्री एन० एस० शर्मा :**
श्री शारदा नन्द :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री रा० कृ० बिड़ला :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था गेहूँ के बीजों की शीघ्र उगने वाली किस्म उगाने में सफल हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इन बीजों को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं और किन-किन राज्यों में इन बीजों का प्रयोग किया जायेगा; और

(ग) इसके द्वारा खाद्य उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की आशा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) जी हां। भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था ने बाद की बोई गई परिस्थितियों में खेती के लिए मैक्सिको, सोनोरा 64 से एक लघु किस्म को चुना है। यह किस्म स्थान तथा बुआई के समय के अनुसार 90–120 दिनों में बड़ी हो जाती है। मूल किस्म का रंग लाल अनाज जैसा था किन्तु अब उसका रंग बदल दिया गया है और एक नई किस्म जिसका नाम शरबती सोनोरा है जिसमें 25 प्रतिशत प्रोटीन पहली किस्म की अपेक्षा अधिक होती है का विकास किया गया है।

(ख) सोनोरा 64 के बीज 1965 और 1966 में मैक्सिको से आयात किये गये थे और अब यह भारी मात्रा में देश में उपलब्ध है। राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम के अन्तर्गत इस किस्म के लाभ को मल्टीपल क्रोपिंग के लिए सारे देश में प्रदर्शित किए जाने का प्रस्ताव है।

नई किस्म शरबती सोनोरा के बीज जिनका विकास भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था में हुआ की भी रबी के दौरान उत्तरीय भारत में और खरीफ के दौरान नीलगिरी पहाड़ियों में वृद्धि की जा रही है। यह किस्म हाल ही में सैन्ट्रल वैरायटी रिलीज कमेटी द्वारा अनुमोदित की गई है।

(ग) इन शीघ्र उपज वाली किस्मों की कुल उपज का अनुमान लगाना कठिन है। इस समय केवल इतना ही कहा जा सकता है कि इन किस्मों से चावल–गेहूँ, गन्ना–गेहूँ, टमाटर - गेहूँ, कपास–गेहूँ आदि की फसल चक्रगति बनी रहती है। शीघ्र उगने वाली किस्म होने से इसको उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा में आसानी से उगाया जा सकता है।

केरल में छोटी बन्दरगाहों का विकास

180. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री जनार्दनन :
श्री पी० सी० अदिचन :
श्री ई० के० नयानर :
श्री उमानाथ :
श्री पी० गोपालन :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री पी० रामामूर्ति :
श्री के० एम० अब्राहम :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने चौथी योजना में राज्य में छोटी बन्दरगाहों के विकास के लिए कोई योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन सी बन्दरगाहों का विकास किया जायेगा;

(ग) उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) उसकी अनुमानित लागत क्या है और केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दिये जाने का विचार है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० ग्रार० वी० राव०) : (क) से (घ) : सभा पटल पर एक विवरण प्रस्तुत किया जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 433/67**]

भारत में चावल की स्थिति

769. **श्री राम कृष्ण गुप्त : खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चावल की अद्यतन स्थिति क्या है;

(ख) वर्ष 1965–66 की तुलना में यह कितनी अच्छी अथवा खराब है; और

(ग) वर्ष 1967–68 में कितना चावल बाहर से मंगाया जाएगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) और (ख) देश में चावल की अद्यतन स्थिति 1965–66 की अपेक्षा अधिक कठिन है ।

(ग) 1967–68 के बजट अनुमानों में लगभग 4 लाख मीटरी टन चावल का आयात करने की व्यवस्था की गयी है ।

विदेशों से खाद्य-उपहार

770. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1967 के दौरान ग्रीस से जो 11 टन बीज हीन किसमिश मिले थे, उनका नीलाम करके भारतीय खाद्य निगम ने कितनी राशि वसूल की;

(ख) किन-किन पार्टियों को उनका नीलाम किया गया ? जिन पार्टियों को उनका नीलाम किया गया उनके नाम क्या हैं;

(ग) बिहार के सूखाग्रस्त लोगों के लिए नीलाम से वसूल इस धन का प्रयोग किस ढंग में किया गया है; और

(घ) क्या इससे पहले भी इस प्रकार के खाद्य उपहारों का नीलाम किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) देश में कमी सम्बन्धी सहायता के लिये अगस्त, 1966 में ग्रीस से प्राप्त किशमिश के उपहार में से 11 मीटरी टन किशमिश की नीलामी भारतीय खाद्य निगम ने 18–4–1967 को थी । क्योंकि उच्चतम बोली सुरक्षित कीमत से कम थी इसीलिये नीलामी से कोई बिक्री नहीं की गयी थी ।

(ख) और (ग) : उत्तर के भाग (क) को देखते हुये प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) ग्रीस से उपहार रूप में प्राप्त किशमिश में से लगभग 241 मीटरी टन की एक मात्रा गत वर्ष कांडला पर नीलाम की गयी थी और इससे प्राप्त राशि कमी सहायता और ग्रामीण विकास निधि में जमा की जाएगी ।

मसूर की दाल की खेती

771. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश में कितनी एकड़ भूमि में मसूर की दाल की खेती होती है और मसूर की दाल पैदा करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं;

(ख) इसके प्रयोग से हुए बुरे प्रभाव को देखते हुए, जनता के हित के लिये, इस जहरीली दाल की खेती को रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं या उठाने का विचार है; और

(ग) जिन राज्यों ने इस दाल की खेती को समाप्त करने का निर्णय किया है उनके नाम क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे : (क) मसूर की खेती अधिकतर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब और हरियाना में और आसाम, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश के छोटे क्षेत्रों में होती है। मसूर की खेती के एकड़वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) यह कहना ठीक नहीं है कि मसूर की दाल विषैली है अत: सरकार उसकी खेती पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहती।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पैट्रोलियम मल्व

772. **श्री वीरेन्द्रकुमार शाह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "एस्सो" द्वारा किये गये अनुसन्धान के अन्तर्गत हमारे देश में पैट्रोलियम मल्व सम्बन्धी प्रयोगों का क्या परिणाम निकला है; और

(ख) क्या इन प्रयोगों के फलस्वरूप अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में खाद्य उत्पादन करने के बारे में इसका वाणिज्यिक प्रस्ताव है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) 1961 तथा 1962 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में विभिन्न मल्वों की उपयुक्तता के विषय में प्रयोग किये गये थे। स्ट्रा मल्व तथा पोलीथेन मल्व के साथ एस्सो कृषि मल्व (जिसे पैट्रोलियम मल्व भी कहते हैं) का परीक्षण किया गया था। कपास की फसल पर अमरीकन कम्पनी एस्सो द्वारा विकसित हुए पैट्रोलियम मल्व को तरल फुहार के रूप में प्रयोग किया गया था। कपास की पंक्तियों के दोनों तरफ पम्प की सहायता से 650 लिटर प्रति हैक्टर के हिसाब से उसका प्रयोग किया गया था। मई तथा जून के गर्मियों के मासों में परीक्षणों के विषय में प्रगति को रिकार्ड किया गया था।

स्ट्रा मल्व ने नमी को 25 प्रतिशत तथा पोलीथीन मल्व ने कमी को 39 प्रतिशत व पैट्रोलियम मल्व ने 14 प्रतिशत तक नमी को सुरक्षित रखा। उपज या उसकी किस्म पर कोई

कुप्रभाव नहीं देखा गया । इन परीक्षणों के अनुसार नमी के संरक्षण में पैट्रोल का सबसे कम प्रभाव देखा गया ।

(ख) उपरोक्त परिणामों को दृष्टि में रखते हुए तथा भारत में मूल्यों की वर्तमान स्थिति को दृष्टि में रखते हुए पैट्रोल मल्च का प्रयोग बड़े पैमाने पर करना ठीक नहीं समझा जा सकता ।

तूतिकोरिन बन्दरगाह परियोजना

773. **श्री सेझियान :** **श्री अंबाजागन :**

क्या **परिवहन तथा नौवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तूतिकोरिन बन्दरगाह परियोजना में क्या प्रगति हुई है;

(ख) 1966–67 के दौरान क्या क्या काम कब-कब करने की योजना बनाई गई हैं;

(ग) परियोजना की कुल अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) अब तक कितना धन खर्च किया गया है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) प्रगति इस प्रकार है.—

तट के कार्य : समस्त प्रारंभिक कार्य जैसे क्षेत्र जांच, भूमि प्राप्ति पहुंच मार्ग, आन्तरिक सड़कें, खदान की सड़कें, खदान की रेलवे साइडिंग, निवास स्थानों की पहली और दूसरी अवस्था, अस्थायी आफिस, पानी सप्लाई की पहली अवस्था, नाली, बिजली, नीचे स्थानों को भरना इत्यादि पूरे हो गये हैं ।

तट से अलग के कार्य

(1) **उत्तर पनकट दीवार का निर्माण :** पांच मीटरों तक पनकट दीवार पर निर्माण कार्य पूरा हो गया है । रीच में कोड पत्थरों के डालने का काम पूरा हो गया है और आरमर पत्थर डालने का काम प्रगति पर है ।

(2) **दक्षिण पनकट दीवार का निर्माण :** तीन मीटरों तक पनकट दीवार के निर्माण का काम पूरा हो गया है । 3 मीटर से पांच मीटर तक रीच का काम प्रगति पर है ।

(3) **पहुंच भुजा :** चार्ट डेटम से 3 मीटर गहराई तक पहुंचभुजा की पूर्णप्राप्ति का कार्य प्रगति पर है ।

(ख) पनकट दीवार, सड़क, रेल पहुंच, तथा अन्य प्रारम्भिक कार्यों के निर्माण से संबद्ध कार्य और निर्माण उपस्कर की खरीद के लिये 1966–67 के बजट प्राक्कलन में 193.60 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ।

(ग) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, जो सरकार के विचाराधीन है, तूतीकोरिन पतन परियोजना में 25 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है ।

(घ) 5.22 करोड़ रुपये ।

डमडम का टर्मिनल हवाई अड्डा

775. **डा० रानेन सेन :** **श्री मु० कु० तापड़िया :**
श्री जी० एम० सिंह : **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डमडम के टर्मिनल हवाई अड्डे का विकास करने में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) उसका विकास करने में कितना समय लगेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) और (ख) : डमडम हवाइ अड्डे पर एक नये इंटरनेशनल टर्मीनल कॉम्प्लेक्स का दो भागों में निर्माण किया जा रहा है। पहले भाग में एक इण्टरनेशनल टर्मीनल ब्लॉक का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण–कार्य के 1968 के प्रारम्भ में पूरा हो जाने की आशा है, यद्यपि बिल्डिंग के पूर्ण रूप से काम में लाये जाने में कुछ और महीने लग जायेंगे। दूसरे भाग में एक कंट्रोल टावर बनाया जा रहा है। ब्लॉक के नींव–स्तंभों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है तथा ऊपरी इमारत के निर्माण का काम हाल ही में दे दिया गया है। इसके तीन साल में पूरा हो जाने की संभावना है।

राष्ट्रीय राजपथ

776. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने राजपथ हैं तथा उनके नाम क्या हैं; और

(ख) बिहार में ऐसे कितने राजपथ हैं तथा उनके नाम क्या हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) देश में 44 राष्ट्रीय मुख्य मार्ग हैं। राष्ट्रीय मुख्य मार्ग के नम्बरों और ब्योरे के सम्बन्ध में एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 434/67**]

(ख) बिहार में तीन राष्ट्रीय मुख्य मार्ग हैं अर्थात, सं० 28 ए, 30 और 33 और 4 राष्ट्रीय मुख्य मार्गों के भाग हैं, अर्थात, सं० 2, 28, 31, और 32।

भारतीय लाख अनुसंधान संस्था

777. **श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय लाख अनुसंधान संस्था लामकुम, रांची के कर्मचारियों ने अपने संघ के द्वारा अपनी स्थायी शिकायतों का अभ्यावेदन सितम्बर, 1966 में संस्था के निदेशक को दिया था; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है और क्या उक्त अभ्यावेदन में उठायी गई बातों पर विचार करने के लिए निदेशक, संघ के किसी नेता से मिले हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) यद्यपि यूनियन को स्वीकृति प्रदान नहीं है फिर भी यूनियन के प्रतिवेदन में शामिल कुछ समस्याओं का सरकार द्वारा की गई सामान्य कार्यवाही द्वारा समाधान कर दिया गया है । जिन समस्याओं का समाधान किया गया है उनमें आकस्मिक रूप से कार्य करने वालों का वेतन 1.75 रुपए से बढ़ाकर 2.25 रुपए प्रति दिन करना व मासिक रूप से कार्य करने वाले संस्थान के मज़दूरों को नियमित करके उनका वेतनमान 70–1–80 दक्षतावरोध–1–85 करना आदि शामिल हैं । निदेशक ने यूनियन के किसी नेता से भेट नहीं की है परन्तु यूनियन द्वारा प्रतिवेदन में जिन समस्याओं को उठाया गया था उनके बारे में निदेशक ने श्रम अधीक्षक रांची को स्पष्टीकरण दे दिया गया ।

रिवर स्टीम नेविगेशन कम्पनी

778. **श्री शिवपूजन शास्त्री :** **श्री मधु लिमये :**

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिवर स्टीम नेविगेशन कम्पनी, आसाम ने (मई, 1967 के प्रथम सप्ताह) तालाबन्दी घोषित कर दी है;

(ख) क्या यह घोषित तालाबन्दी अवैध है; और

(ग) सरकार ने इस तालाबन्दी को समाप्त करने तथा कम्पनी तथा कर्मचारियों के विवाद को हल करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Enquiry Committees' Report on Hindustan Shipyard, Ltd. Visakhapatnam

779. **Shri Kameshwar Singh :**
Shri J. H. Patel :
Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether Government have received the Report of the Enquiry Committee headed by Rear Admiral S. M. Nanda to look into the conditions of the Hindustan Shipyard, Viskhapatnam;

(b) if so, the main features thereof and the action taken on its recommendation; and

(c) if the reply to part (a) above be in the negative, the time by which the report is likely to be submitted to Government ?

The Minister of Transport and Shipping : (Dr. V.K.R.V. Rao) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) It is understood that the draft of the Report is ready and is pending finalization. As in the meanwhile, the Chairman of the Committee has been posted on operational duties, a new Chairman is being appointed and it is expected that the Report will be ready within three months of the new Chairman taking over his duties.

Delhi Milk Scheme Depot Managers

780. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some Depot Managers of the Delhi Milk Scheme were relieved of their services during the April, 1967;

(b) if so, the number thereof and the reasons therefor; and

(c) the action to ensure that the Depot-Managers/Salesmen of the Scheme deal properly with the customers ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b) : Services of 15 Depot Managers and 13 Depot Assistants were terminated during the month of April, 1967 for serious complaints such as change of seals on milk bottles, failure to issue milk to token holders, cash sale of milk bottles to non-token holders and non maintenance of 'tickler' form for checking misuse of tokens etc.,

(c) Intensive action is being taken to reduce complaints against working of the Scheme. Inspection of the milk depots has been intensified. The entire inspecting staff is reporting directly to the Chairman so that supervision of the depots may be tightened up. The Depot Staff have been given strict instructions that every card/token-holder must without fail be given his quota of milk. Sale of milk to non-card/token holders has been strictly prohibited. Tickler forms are used at the depots in order to ensure that card/token holders may not draw more than their due quota. Drastic action including termination of service is taken in cases of breach of these instructions.

केरल में कृषि विश्वविद्यालय

781. श्री अदिचन : श्री एस्थोस :
श्री विश्वम्भरन : श्री अब्राहम :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, समुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) अभी तक केरल सरकार से कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है। भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् की वार्षिक सामान्य बैठक में केरल के कृषि मन्त्री ने केरल में

एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के पक्ष में मत प्रकट किया था परन्तु अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नाइट्रोजन उर्वरकों का वितरण

782. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि केवल सहकारी समितियों के माध्यम से नाइट्रोजन उर्वरकों के वितरण की व्यवस्था से इसकी बिक्री बढ़ाने के प्रयत्न अपर्याप्त रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप किसान इस किस्म का उर्वरक खरीदने में कम रुचि रखते हैं; और

(ख) क्या सरकार सुपर फासफेट की भाँति नाइट्रोजन उर्वरकों को व्यापारियों द्वारा बेचने पर विचार करेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) यह कहना सच नहीं है कि बिक्री बढ़ाने के अपर्याप्त प्रयत्न के कारण नाइट्रोजन उर्वरकों के लिए किसान कम दिलचस्पी रखते हैं । राज्यों में जहां सहकारी समितियों को वितरण सौंपा हुआ है नाइट्रोजन उर्वरकों की मांग बढ़ती जा रही है ।

(ख) किसानों की आवश्यकतानुसार उर्वरकों की भारी मात्रा को शायद सहकारी समितियां सम्भाल नहीं सकेंगी इसलिए राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि जरूरत के मुताबिक गैर-सरकारी व्यापारियों को नियुक्त किया जाए । नए कारखानेजिनको 31-12-1967 तक लाइसैन्स दिये जायेंगे सहकारी समितियों तथा गैर सरकारी व्यापारियों में से किसी को भी अपनी वितरण एजेन्सी चुन सकते हैं । ऐसी ही स्वतन्त्रता नाइट्रोजन उर्वरकों के वर्तमान उत्पादकों को भी दी गई है । इन कारखानों द्वारा की गई सीधी बिक्री 1–10–67 से 50 प्रतिशत और 1–10–68 से 70 प्रतिशत बढ़ जाएगी ।

मध्य प्रदेश और गुजरात में नलकूपों के लिये सर्वेक्षण

783. **श्री हुकम चन्द कछवाय** :
श्री राम सिंह आयरवाल :
श्री नीतिराज सिंह :
श्री जी० सी० दीक्षित :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रयोगात्माक नलकूप संगठन ने मध्य प्रदेश और गुजरात में प्रयोगात्मक नलकूप खोद कर भूमिगत जल के सम्बन्ध में कुछ सर्वेक्षण किया है;

(ख) प्रत्येक राज्य में कितने प्रयोगात्मक नलकूप खोदे गये;

(ग) इन नलकूपों में से कितने नलकूप इस कारण मफल रहे क्योंकि वहां पर नीचे की भूमि में जल काफी मात्रा में उपलब्ध था और कितने नलकूपों में नीचे की भूमि में काफी मात्रा में जल उपलब्ध नहीं था, इसके राज्य-वार आंकड़े क्या हैं;

(घ) क्या प्रयोगात्माक नलकूपों के कार्य के आधार पर प्रत्येक राज्य में नलकूपों द्वारा विकास किये जाने के लिए कुछ क्षेत्र चुने गये हैं और उनकी सिफारिश की गई है;

(ङ) इन राज्यों के विभिन्न भागों में विद्यमान नलकूपों से कितने क्षेत्र में सिंचाई की जाती है; और

(च) इन चुने हुए क्षेत्रों में कितने क्षेत्र की सिंचाई नलकूपों द्वारा की जा सकती है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) : जानकारी नीचे दी जाती है:—

राज्य का नाम	**खोदे गए समन्वेषी बोर की संख्या**	**सफल समन्वेषी बोर की संख्या**
मध्य प्रदेश	56	31
गुजरात	89	22

खराब पानी के कारण 25 समन्वेषी बोर तथा 67 समन्वेषी बोर क्रमशः मध्य प्रदेश में तथा गुजरात में बन्द कर दिए गए थे ।

(घ) कृपया अनुबन्ध देखिए [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 435/67**]

(ङ) राज्यों से जो नवीनतम जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार 1965-66 के दौरान जो क्षेत्र राजकीय नलकूपों द्वारा सींचा गया वह निम्नलिखित हैं:—

मध्य प्रदेश	8,371 एकड़
गुजरात	70,475 एकड़

(च) उपरोक्त (घ) में दिए गए अनुबन्ध को कृपया देखें ।

पर्यटन निधि

784. **श्री रामपुरे** :
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री एन० के० सांघी :
श्री वाई० ए० प्रसाद :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये भारतीय ट्रैवल एजेंट संस्था ने केन्द्रीय सरकार से नौवहन विकास निधि की भांति ही एक पर्यटन निधि कायम करने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या सरकार ने इस अनुरोध पर विचार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) : जी, हां। पर्यटन की वृद्धि के लिए एक पर्यटन विकास निधि कायम करने के लिए भारत के "ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन" की ओर से एक सुझाव प्राप्त हुआ था। इस पर विचार किया जा रहा है।

कलकत्ता बन्दरगाह पर डाक व तार विभाग का वर्कशाप

785. **श्री एस० एन० मैती :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता बन्दरगाह पर माल रखने की जो जगह उपलब्ध है उसका प्रयोग डाक व तार विभाग के वर्कशाप के लिये करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में भारतीय जहाजरानी निगम की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं। पुरानी स्टील डम्प स्थान पर डाक व तार विभाग ने एक भूमि के टुकड़े को कलकत्ता पोर्ट कमिश्नर से नियमित पट्टे पर लिया है। यह तारघर के सामान के लिये स्टोरयार्ड के रूप में व्यवहृत किया जाता है। वह विभाग इस भूमि पर एक वर्कशाप बनाना चाहता था किन्तु कमिश्नरों ने इसकी स्वीकृति नहीं दी।

(ख) भारत के शिपिंग कारपोरेशन से इसके बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है।

Super Bazar, New Delhi

786. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of complaints received so far regarding the inferior quality and high prices of commodities sold at Super Bazar, New Delhi; and

(b) the action taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde). (a) and (b) : The Government of India received only four complaints about the Super Bazar charging prices which were higher than the market prices. Two of these complaints related to medicines and two to pressure cookers. All these complaints were looked into and it was found that in only one case in respects of some medicinal capsules the Super Bazar salesman had by mistake over-charged the complainant. The Super Bazar undertook to refund the excess amount charged. In the other cases no overcharging could be established because the prices were in conformity with the prices determined by the manufacturers and even less.

No complaints were received regarding inferior quality of goods sold by Super Bazar.

Super Bazar, New Delhi

787. Shri Ram Gopal Shalwale : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Super Bazar, New Delhi has taken a loan of Rs. 80 lakhs in order to run its bunsiness;

(b) if so, the amount of interest which will be paid on this loan;

(c) the percentage of profit that would accrue from the articles on which this amount has been invested; and

(d) the steps taken to make the Super Bazar, self-reliant ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) The Super Bazar has a cash credit arrangement of Rs. 80 lakhs with the Syndicate Bank Ltd. The actual drawal against this limit has not so far exceeded Rs. 53 lakhs.

(b) The rate of interest on the credit obtained from the Syndicate Bank Ltd. is 9 percent per annum. The incidence of interest on the cost structure would, however, be much less depending upon the number of times these funds are rotated in business.

(c) The gross average margin on articles sold in the Super Bazar is about 9 percent.

(d) The opening of a third branch of the Super Bazar will complete the first phase of its organisation. It is expected that it would be able to show a small surplus, thereafter.

केरल में चावल और गेहूं के राज सहायता से निर्धारित मूल्य

788. **श्री ई० के० नायर :**
श्री उमानाथ :
श्री पी० गोपालन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने 1966 में केरल में चावल और गेहूं का राज-सहायता से निर्धारित मूल्य बढ़ाया था, और

(ख) यदि हां, तो यह मूल्य कितनी बार बढ़ाया गया तथा प्रत्येक बार कितनी वृद्धि की गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) केन्द्रीय भण्डारों से केरल सहित सभी राज्य सरकारों को दिये जाने वाले चावल और आयातित गेहूं के निर्गम मूल्यों में 1966 में वृद्धि की गयी थी। इस पर भी कोर्स चावल और गेहूं के मूल्यों में उपदात की राशि शामिल हैं।

(ख) केवल एक बार आयातित गेहूं के निर्गम मूल्य में नवम्बर, 1966 से बढ़ोतरी की गयी थी। चावल के बारे में यह वृद्धि दो बार अर्थात 1966 के वर्ष में जून और

दिसम्बर में की गयी थी। सभी राज्यों में आयातित गेहूं के मूल्यों में रु० 50.00 से रु० 55.00 प्रति क्विटल के बीच वृद्धि की गयी थी। कोर्स चावल के बारे में केरल में निर्गम मूल्य में यह वृद्धि जून, 1966 से 66 रुपये से 69 रुपये और दिसम्बर, 1966 से 69 रुपये से 80 रुपये प्रति क्विटल के बीच थी।

बिहार में अकाल की घोषणा

789. श्री मोहन स्वरूप :
श्री राम सेवक यादव :
श्री मधु लिमये :
श्री मोलाहू प्रसाद :
श्री जार्ज फरनेंडीज :
श्री रबी राय :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री बलराज मधोक :
श्री चन्द्र शेखर सिंह :
डा० रानेन सेन :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री महाराजसिंह भारती :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री कमला मिश्र मधुकर :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री बी० एस० शर्मा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रामसिंह आयरवाल :
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री श्रीगोपाल साबू :
श्री स्वैल :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ए० के० किस्कू :
श्री एस० एन० मैती :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री पार्थासार्थी :
श्री आर० डी० रेड्डी :
श्री शिव चन्द्र झा :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री डी० एन० पटोदिया :
श्री मुहम्मद इमाम :
श्री मु० कु० तापड़िया :
श्री गार्डिलिंगन गौड़ :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री वाई० ए० प्रसाद :
श्री प्र० के० देव :
श्री रा० बरुआ :
श्री एन० के० सांघी :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री ए० अनिरुद्धन :
श्री अब्राहम :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री उमानाथ :
श्री एस्थोस :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने एक तिहाई राज्य को अकाल-पीड़ित क्षेत्र घोषित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो अकाल पीड़ित घोषित किए गए क्षेत्रों का व्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस घोषणा से उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : बिहार सरकार द्वारा घोषित अकाल क्षेत्र बताने वाला एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी०** 436/67]

(ग) और (घ) : भारत सरकार बिहार सरकार की सहायता करने के लिये प्रत्येक सम्भव प्रयत्न कर रही है। सूखे से उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के लिये राज्य सरकार ने बहुत बड़े पैमाने पर सहायता उपाय किये हैं। भारत सरकार द्वारा बिहार सरकार को अब तक दी गयी सहायता संलग्न विवरण में दी गयी है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी०** 437/67]

Offer of Agricultural Exports from Japan

790. Shri Mohan Swarup :
Shri N. K. Sanghi :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Manibhai J. Patel :
Shri D. C. Sharma :
Shri Bibhuti Mishra :
Smt. Tarkeshwari Sinha :
Shri H. P. Chatterjee :
Shri Datiatraya Kunte :
Shri S.C. Samanta
Shri Yashpal Singh :
Shri Y. A. Prasad :
Shri P. Parthasarathy :
Shri K. N. Tiwary :
Shri R. D. Reddy :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Japanese Organisation for Industrial, Spiritual, Religious, and Cultural advancement has offered to place the services of 500 Japanese Agricultural experts at the disposal of Government in order to make it possible to attain self-sufficiency in regard to agriculture; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Anna Sahib Shinde) : (a) and (b) : No offer of any specific number of experts has been received from the Japanese organisation called OISCA. On their general offer of assistance, they have been asked to submit specific and detailed schemes of agricultural production.

Modernisation of I.A.C.

791. Shri Mohan Swarup :
Shri Manibhai J. Patel :
Shri B. S. Sharma :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the steps taken to modernise the Indian Airlines Corporation;

(b) whether it is a fact that the Corporation is running at a loss at present;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) the steps taken to obviate such loss in future ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) : The Indian Airlines Corporation has been taking steps to modernise their fleet and workshops to the extent possible. The limiting factor has been the shortage of foreign exchange. They introduced Viscounts in 1957, Friendships in 1961 and Caravelles in 1964. The Corporation have in their fleet 6 Caravelles, 14 Viscounts and 13 Friendships. One more Caravelle is on order which is expected to be received in October, 1967. An order for 9 HS-748 (Avro-748) aircraft has been placed on Hindustan Aeronautics Ltd., Kanpur. Three of these are expected to be received during the year 1967-68.

(b) and (c) : The revised estimates for the year 1966-67 show a loss of Rs.460.55 lakhs and the budget estimates for 1967-68 show a loss of Rs. 349·76 lakhs. The loss is mainly due to the :-

(i) effect of devaluation;

(ii) loss of two Caravelles resulting in shortage of capacity and decline in the earnings of the Corporation and

(iii) increase in expenditure due to wage revisions.

(d) : (i) The Corporation is losing heavily on operation of Dakotas and Skymasters. Modernisation and expansion of their fleet is likely to result in increased earnings and reduction in costs; and

(ii) The Corporation is keeping a close watch on expenditure and are effecting economies, consistent with safety of operation, wherever possible.

Payment of Road Tax in Delhi

792. **Shri Mohan Swarup** :
Shri Manibhai J. Patel :

Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased te state :

(a) whether Government are aware that people in Delhi experience great inconvenience in depositing road tax at Central Secretariat, Janpath and Office of the Transport Director in old Delhi;

(b) if so, whether Government propose to open some more Centres for this purpose; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V.K.R.V. Rao) : (a) Govt. have received information that some inconvenience is being felt in this regard on occasions.

(b) A proposal to open more centres is under the consideration of the Delhi Administration.

(c) Does not arise.

Committee on Cow Slaughter

793. **Shri Ram Gopal Shalwale** :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Balraj Madhok :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Ram Kishan Gupta :
Shri Sidheshwar Prasad :
Shri Kanwar Lal Gupta :
Dr. Karni Singh :
Smt. Nirlep Kaur :
Shri Shiv Kumar Shastri :

Shri O. P. Tyagi : Shri R. Barua :
Shri D. N. Patodia : Shri C. C. Desai :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 234 on the 4th April, 1967 regarding ban on Cow Slaughter and state :

(a) whether the Committee to go into the question of imposing a ban on cow slaughter has since been set up;

(b) if so, the personnel and terms of reference of the Committee; and

(c) the progress made so far by the Committee ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri AnnaSahib Shinde) : (a) No.

(b) A delegation of the Sarvadaliya Goraksha Mahabhiyan Samiti said, in discussions with Minister of Food and Agriculture on 21st May, 1967 that the Samiti would send the names of their representatives by the 29th of this month. But Sarvadaliya Goraksha Mahabhiyan Samiti has not given names of their representatives upto 29th May, 1967. The information of the Committee and the terms of reference will be announced thereafter.

(c) Does not arise.

राज्यों में राशन व्यवस्था

794. **श्री एस० आर० दमानी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई राज्यों ने अभी तक राशन व्यवस्था लागू नहीं की; और

(ख) यदि हां, तो क्या सम्बन्धित राज्यों ने ऐसा न करने का निर्णय खुद लिया है अथवा केन्द्रीय सरकार ने उन्हें ऐसी सलाह दी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) इस सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है।

कृषि के क्षेत्र में रूस के साथ करार

795. **श्री प्र० के० देव :** **श्री डी० एन० देव :**
श्री क० प्र० सिंह देव : **डा० रानेन सेन :**

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि के क्षेत्र में सहयोग करने के बारे में रूस और भारत की सरकारों के बीच कोई करार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस करार का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) (क) और (ख) : रूस और भारत की सरकारों के बीच कृषि उपयोगी उपकरणों तथा मशीनों की सप्लाई के सम्बन्ध में 25-11-1966 को एक करार किया गया था। इस समझौते के अधीन वर्ष 1966-68 के दौरान रूस की सरकार भारत के लोगों और भारत सरकार को कृषि में काम आने वाले औजार तथा मशीनें उपहार के रूप में देगी, जिनके लिए हमें केवल वहन-शुल्क ही देना होगा और जिनके आधार पर बीज उगाने वाले 5 सरकारी कृषि-फार्म खोले जायेंगे जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल 3 हजार से 4 हजार एकड़ होगा। इन उपकरणों तथा मशीनों में अन्य मशीनों और उपकरणों के साथ साथ ट्रेक्टर, बुलडोज़र, सिंचाई के लिये नालियां खोदने वाली मशीनें, भूमि खुरचने वाली मशीनें, खेंचू मशीनें, ग्रेडर, समतल करने वाली मशीनें, केटर पिलर ट्रेक्टर, अनाज और खाद बोने वाले वैरने, अनाज साफ करने वाले यंत्र, बीज संवारने वाले यंत्र, अनाज ढोने वाले यंत्र कटाई करने वाले यंत्र, कपास लगाने वाले यंत्र आदि सम्मिलित हैं। इन सबका अनुमानित मूल्य लगभग 155 लाख रुपये होगा।

भारत में फार्म प्रदर्शन के लिए इसराइल सरकार को सुविधायें

796. **श्री प्र० क० देव :**
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री डी० एन० देव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इसराइल की सरकार ने इस देश में नवीनतम फार्म प्रदर्शन के लिए सुविधायें देने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत और पाकिस्तान के बीच हवाई सेवा को पुनः चालू करना

797. **श्री राम किशन गुप्त :**
श्री रामपुरे :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री न० कु० सांघी :
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वाई० ए० प्रसाद :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री** 21 मार्च, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 19 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दोनों देशों के बीच पुनः हवाई सेवा चालू करने के बारे में पाकिस्तान के प्रस्ताव पर इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) और (ख) : मौखिक प्रश्न संख्या 19 के उत्तर में 22 मई, 1967 को विदेश मंत्री द्वारा इस सदन में दिये गये विवरण को देखा जाय। मामले पर विचार किया जा रहा है।

दिल्ली को खाद्यान्नों की सप्लाई

798. **श्री राम किशन गुप्त** : **श्री बलराज मधोक** : **श्री कंवर लाल गुप्त** : **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुख्य मंत्रियों के इस निर्णय के फलस्वरूप कि उत्तरी खाद्य जोन को विभाजित कर प्रत्येक राज्य का पृथक जोन बना लिया जाये, राजधानी को खाद्यान्नों की सप्लाई में अव्यवस्था पैदा हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो राजधानी की आवश्यकताओं की पूर्ति के निमित्त वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) (क) : जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पर्यटक सप्ताह

799. **श्री नि० रं० लास्कर** : **श्री लीलाधर कटकी** : **श्री श्रद्धाकार सूपकार** : **श्री श्रीगोपाल साबू** :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन पर्यटकों को जो मार्च, 1967 में पर्यटन सप्ताह के दौरान भारत आए थे सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध की गई थी;

(ख) क्या इस पर्यटक सप्ताह के सम्बन्ध में सरकार द्वारा किये गये व्यय तथा उसको प्राप्त हुई विदेशी मुद्रा की आय का अनुमान लगाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) : इस वर्ष मार्च में आयोजित 'पर्यटन सप्ताह' केवल दिल्ली में मनाया गया। इस सप्ताह के दौरान जो पर्यटक दिल्ली में विद्यमान थे उन्हें निम्नलिखित विशेष सुविधाएं प्रदान की गयीं:—

1. पर्यटन विभाग द्वारा पालम हवाई अड्डे पर विशेष स्वागत कार्य-क्रमों का आयोजन किया गया।

2. दिल्ली के महापौर ने 19 मार्च को उस दिन दिल्ली में विद्यमान पर्यटकों के लिये एक स्वागत–समारोह आयोजित किया।

3. इण्डिया इन्टरनेशनल सैन्टर द्वारा एक अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन सन्ध्या का आयोजन किया गया जिसमें उन्होंने आपस में एक दूसरे से व्यक्तिगत स्तर पर सम्पर्क स्थापित करने की योजना के अनुसार सैन्टर के सदस्यों के साथ मिलने के लिए एक बड़ी संख्या में पर्यटकों को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया।

4. विभिन्न होटलों में, वहां ठहरे हुए विदेशी यात्रियों के हित के लिये, वृत्त-चित्रों (डॉक्युमेंटरी) तथा यात्रा–फिल्मों के प्रदर्शन आयोजित किये गये।

5. अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन सप्ताह मनाने के लिये विशेष सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन किया गया।

6. लोक कला मंच ने, जो कि एक स्वैच्छिक संगठन है, पैरेड ग्राउण्ड पर एक पर्यटक होली मेला मना कर इस 'सप्ताह' में भाग लिया। इस मेले में पर्यटक बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए।

7. सैंट्रल कोटेज इण्डस्ट्रीज एम्पोरियम, हैंडलूम हाऊस, तथा अन्य अनुमोदित दूकानदारों ने विशेष–बिक्रियों का आयोजन किया तथा विदेशी यात्रियों को 10% की रियायत दी।

ये सुविधाएं इस प्रकार की अन्य रियायतों के अतिरिक्त थीं, जैसे विज़ा शुल्क का हटाना, विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों द्वारा विज़ा का तत्काल जारी करना, अस्थायी अवतरण अनुज्ञा–पत्रों (टेम्पोरेरी लैंडिंग परमिटों) की वैधता की अवधि को 72 घंटे से बढ़ा कर 7 दिन करना, तथा पर्यटक सामान नियमों को और अधिक उदार बनाना, इत्यादि, जिनकी कि भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष के एक अंग के रूप में घोषणा कर दी थी।

(ख) मार्च, 1967, में आयोजित पर्यटन सप्ताह से सम्बद्ध उत्सव–समारोहों पर लगभग 17,000/–रुपये का व्यय किया गया। सरकार द्वारा पर्यटन सप्ताह में उपार्जित विदेशी मुद्रा के आंकड़े उपलब्ध नहीं, क्योंकि इनका अन्दाजा समस्त वर्ष के लिये कैलेंडर वर्ष के अन्त में लगाया जाता है।

(ग) : निम्नलिखित मदों पर धन व्यय किया गया:

(i) अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन पोस्टर प्रदर्शनी।

(ii) इस सप्ताह से सम्बन्धित प्रचार सामग्री का उत्पादन।

(iii) विज्ञान भवन में उद्घाटकीय समारोह की व्यवस्था।

(iv) हवाई अड्डे पर पर्यटकों के स्वागत के लिये मालाओं की खरीद।

(v) विदेशों में फोटोग्राफी द्वारा प्रचार।

फालतू अनाज वाले राज्यों द्वारा कमी वाले राज्यों को अनाज की सप्लाई

800. **श्री वी० एस० शर्मा :**
डा० कर्णी सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री किकर सिंह :
श्री स्वैल :
श्री कोलाई विरुग्रा :
श्री रा० कृ० बिड़ला :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों ने जहां आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा होता है कमी वाले राज्यों को अनाज देने से इन्कार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने कमी वाले राज्यों के लिये फालतू अनाज प्राप्त करने के हेतु उन राज्यों से बातचीत की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) (क) : जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

पर्यटक कार

801. **डा० कर्णी सिंह :**
श्रीमती निर्लेप कौर :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) होटलों तथा पर्यटन संगठनों को पर्यटन-कारों की बिक्री के बारे में क्या नियम हैं;

(ख) क्या अधिकारी तथा विभाग के मालिक इन कारों का प्रयोग कर सकते हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनके प्रयोग के सम्बन्ध में क्या नियम हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णीसिंह); (क) : सैकण्ड हैण्ड आयातित कारें 'स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन' द्वारा पर्यटक-टैक्सियों के रूप में चलाये जाने के लिये बेची जाती हैं । कारों का पर्यटन विभाग द्वारा मान्यता-प्राप्त पर्यटक-कार परिचालकों, शिकार के साज-समान आयोजकों, यात्रा अभिकर्त्ताओं को नियतन के लिये कसौटी निर्धारित करने में किसी पर्यटन-केन्द्र विशेष में कारों की इष्टतम (आप्टिमम) आवश्यकता, तथा नियतन-भागियों के विदेशी मुद्रा-उपार्जनों, को ध्यान में रखा जाता है । अब तक होटलों को कोई कारों का नियतन नहीं किया गया है, परन्तु 'पर्यटन विकास परिषद' ने सिफ़ारिश की है कि उन केन्द्रों पर जहां कोई मान्यता, प्राप्त पर्यटक-कार परिचालक अथवा यात्रा-अभिकर्ता नहीं

हैं, वहां अपवाद के रूप में होटलों को भी इस प्रकार की कारों के नियतन पर विचार किया जाये। पर्यटकों के उपयोग के लिए, पर्यटन विभाग की सिफारिश पर, स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन द्वारा राज्य सरकारों को भी वे कारें बेची जाती हैं। नियतन-भागियों, द्वारा स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के माध्यम से खरीदी गयी सैकण्ड-हैण्ड आयातित कारें स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन से खरीद की तारीख से तीन साल तक उपयोग में आने, तथा 1,60,000 किलोमीटर चल चुकने के बाद बेची जा सकती हैं।

कुछ नयी कारें 'एयर इण्डिया' के माध्यम से आयात की गई थीं और भारत पर्यटन विकास निगम, राज्य सरकारों तथा पर्यटक-कार-परिचालकों को पर्यटकों के उपयोग के लिये बेच दी गई थीं। ये कारें 1,60,000 किलोमीटर चल चुकने, तथा चार वर्ष तक उपयोग में आने, के बाद केवल स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन को ही बेची जा सकती हैं।

(ख) और (ग) : जब इन कारों की पर्यटकों के लिये आवश्यकता नहीं होती तो कोई भी सद्ग्राहक इनकी सामान्य किराये की दरें दे कर इनका उपयोग कर सकता है।

मध्य आकार के फार्मों पर मशीनों से खेती करना

802. **डा० कर्णी सिंह :**
श्रीमती निर्लेप कौर :
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई फसलें पैदा करने के लिए मध्यम आकार के फार्मों पर मशीनों से खेती कराने के सम्बन्ध में रूसी विशेषज्ञों की सिफारिशों पर विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार और राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) (क) : रूस के एक उप मन्त्री के नेतृत्व में वैज्ञानिकों के एक दल ने स्वयं ही भारतीय कृषि कार्यक्रमों (और विशेषकर कृषि अनुसन्धान) के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत का दौरा किया था। उन्होंने कई फसलें पैदा करने के लिए मध्यम आकार के फार्मों पर मशीनों से खेती करने के बारे में कोई सिफारिशें नहीं भेजी हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषि उत्पादन के लिये नया तरीका

803. **डा० कर्णी सिंह :**
श्रीमती निर्लेप कौर :
श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि उत्पादन के लिए जो नया तरीका निकाला गया है उस का ब्यौरा क्या है;

(ख) अधिक पैदावार देने वाले नये किस्मों के गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का बोने के लिए प्रत्येक राज्य में कौन से क्षेत्र चुने गये हैं;

(ग) किन-किन किस्मों के अनाज का उपयोग किया जायेगा तथा इससे कितना उत्पादन बढ़ने का अनुमान है; और

(घ) क्या इस योजना को सफल बनाने के लिये सिंचाई और उर्वरकों की सप्लाई की व्यवस्था मजबूत की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) (क) से (घ) : एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०** 438/67]

Palam Airport

804. Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Swell :
Shri S. K. Tapuriah :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether there is a proposal to modernise the Palam Airport;

(b) if so, the broad outlines thereof; and

(c) the other airports in the country which are proposed to be modernised ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The main runway at Palam is suitable for all types of commercial aircraft operating there at present. The terminal facilities, however, required considerable improvement for better passenger handling. Certain additions and alterations have already been carried out as phase I at a cost of Rs. 8 lakhs and the second phase of work costing Rs. 32 lakhs will be shortly undertaken. The feasibility of a new International Terminal Complex south of the main runway is being examined.

(c) The international airports at Madras and Bombay are proposed to be modernised as well. A new international block is already nearing completion at Dum Dum.

Rameswaram–Talaimannar Ferry Service

805. Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Shipping Board has taken over ferry service between Rameswaram and Talaimannar (Ceylon) from the Railways;

(b) whether it is also a fact that even now employees engaged in the said ferry service are getting pay and allowances at scales in force in the Railways;

(c) whether the employees have made certain demands; and

(d) if so, the details thereof and the action taken to meet the same ?

The Minister of Transport and Shipping : (Dr. V.K.R.V. Rao) : (a) Shipping Corporation of India Ltd., has taken over the ferry service between Rameswaram and Talaimannar from the Southern Railways.

(b) Yes. The employees have been given time till 1st Oct., 1967 to exercise their option to opt for the terms and conditions applicable in the Shipping Corporation of India.

(c) No.

(d) Does not arise.

Prices of Imported Wheat

806. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the prices of imported wheat have been raised with effect from May, 1967;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the extent of rise in prices ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri AnnaSaheb Shinde) : (a) No, Sir.

(b) and (c) : Do not arise.

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पुनर्गठन

807. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् का पुनर्गठन कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : पूछी गई जानकारी का एक विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 439/67**]

दिल्ली–श्रीनगर जैट विमान सेवा

808. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली और श्रीनगर के बीच जैट विमान सेवा आरम्भ करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो यह सेवा किस अवधि के लिए चालू रहेगी; और

(ग) इस सेवा की आवृत्ति (फ्रीक्वेंसी) क्या होगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) और (ख) : इस वर्ष अक्तूबर में दिल्ली और श्रीनगर के बीच एक कारवेल विमान सेवा आरंभ करने का प्रस्ताव है ।

(ग) : पर्यटन के मौसम में यह विमान सेवा प्रतिदिन चलायी जायेगी ।

हेलीकोप्टर सेवा

809. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी कोई योजना विचाराधीन है जिसके द्वारा मुख्य शहरों जैसे चंडीगढ़, अम्बाला, लुधियाना, जालन्धर और जम्मू को हैलीकोप्टर की सेवा द्वारा परस्पर मिलाया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) (क) : जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

इण्डियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन की दिल्ली पठानकोट सेवा को पुनः चालू करना

810. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन दिल्ली और पठानकोट के बीच विमान-सेवा पुनः चालू करने के सम्बन्ध में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो यह सेवा कब तक चालू की जा रही है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : आई० ए० सी० द्वारा पठानकोट से होकर विमान सेवाएं पुनः चालू करने की व्यवहार्यता की जांच की जा रही है ।

शीघ्र तैयार होने वाली फसलें

811. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री मधु लिमये :
श्री स० मो० बनर्जी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दो मुख्य फसलों के बीच शीघ्र तैयार होने वाली फसलों को उगाने तथा लोकप्रिय बनाने की योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इन योजनाओं पर कितना अतिरिक्त व्यय होगा और इस योजना के अन्तर्गत अनुमानतः कितना क्षेत्र आयेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : सूखे से उत्पन्न हुई देश की वर्तमान कठिन खाद्य स्थिति को देखते हुए निर्णय किया गया था कि रबी की खड़ी फसलों तथा अगली खरीफ फसलों की बुवाई के मध्य की अवधि में शीघ्र तैयार होने वाली फसलों को उगाने की संभावनाओं का पता लगाया जाये। रागी, धान, मक्का आदि की कुछ ऐसी किस्में हैं जो 70–90 दिन की अल्प अवधि में सफलता पूर्वक उगाई जा सकती हैं। अतः राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया कि ऐसी किस्मों का पता लगाया जाये और उनकी बुवाई ऐसे क्षेत्रों में की जाये जहां सिंचाई की सुविधायें निश्चित रूप से उपलब्ध हो सकें। इसके लिए एक कार्यक्रम तैयार करने तथा बीजों व उर्वरकों की सप्लाई की व्यवस्था में सहायता देने के लिए भारत सरकार के तकनीकी विशेषज्ञों ने भी कुछ राज्यों का भ्रमण किया है।

(ग) इस कार्यक्रम के कारण भारत सरकार पर अनुदान के रूप में कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। कृषकों को सप्लाई किये जाने वाले आदानों के लिए अल्पकालीन ऋणों से रुपया प्राप्त होगा।

अब तक प्राप्त हुई सूचना से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, मद्रास, पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 10 लाख एकड़ भूमि पर बुवाई होगी।

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन में डकोटा विमानों के स्थान पर दूसरे विमान

812. **श्री गिरिराज शरण सिंह : श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : श्री मीठा लाल :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के विभिन्न वायुमार्गों में इस समय चलने वाले आई० ए० सी० के पुराने डकोटा विमानों के स्थान पर दूसरे विमान चलाने की सरकार ने कोई योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो इन पुराने विमानों के स्थान पर नये विमान कब तक आ जायेंगे; और

(ग) पुराने डकोटा विमानों के बजाय कौन सा दूसरा विमान चलाया जा रहा है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) : जी, हां।

(ख) और (ग) : 1967 के मध्य तक, आठ को छोड़ कर अन्य सब डकोटा विमान फॉकर फ्रेण्डशिप तथा एच० एस० 748 (एवरो–748) वायुयानों द्वारा, बदल दिये जायेंगे। अवशिष्ट आठ डेकोटाओं को बदलने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है

राज्यों को सूखे की स्थिति का सामना करने के लिये सहायता

813. **श्री श्रद्धाकार सूपकार : श्री डी० एन० पटोदिया :**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : श्री रा० बरूआ :

श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री राम सिंह आयरवाल :
डा० कर्णी सिंह :
श्रीमती निर्लेप कौर :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने इस वर्ष सूखे की स्थिति का सामना करने के लिये सहायता के रूप में विभिन्न राज्यों को अब तक कितना धन तथा अनाज दिया है, और

(ख) 15 मई, 1967 तक राज्यों ने सूखे का सामना करने के लिये सहायता के रूप में कितना धन खर्च किया है (इस खर्च में केन्द्र द्वारा दी गई धन राशि भी सम्मिलित होनी चाहिये) ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) कमी से प्रभावित राज्यों को दी गयी वित्तीय सहायता के ब्यौरे और खाद्यान्नों का आवंटन निम्न प्रकार हैं:—

1–वित्तीय सहायता **(दस लाख रुपयों में)**

	1966–67	1967–68	जोड़
बिहार	439.90	82.50	522.40
गुजरात	44.87	—	44.87
मध्य प्रदेश	209.34	6.75	216.09
राजस्थान	154.38	—	154.38
उत्तर प्रदेश	62.85	9.00	71.85

2–आयातित खाद्यान्नों का आवंटन

(आंकड़े हजार मीटरी टन में)

	अक्तूबर, 66 से मई, 1967 तक की अवधि में आवंटित मात्रा
बिहार	1291.5
गुजरात	476
मध्यप्रदेश	298
राजस्थान	303
उत्तर प्रदेश	786

उपर्युक्त आवंटनों में गेहूं की निम्नलिखित मात्राएं भी शामिल है जो कि राज्यों को सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में बूढ़े और दुर्बल व्यक्तियों में निःशुल्क सहायता के रूप में मुफ्त बांटने के लिए दी गयी थी:—

बिहार	11,000 मीटरी टन
गुजरात	1,000 ,,
मध्य प्रदेश	2,000 ,,
राजस्थान	1,500 ,,
उत्तर प्रदेश	8,000 ,,

बिहार और उत्तर प्रदेश में स्वैच्छिक संगठनों को इन राज्यों में मुफ्त भण्डारे चलाने के लिए गेहूं की निम्नलिखित मात्राएं दी गयी है :—

	इक्नामिक्स कीमत पर दी गयी गेहूं की मात्रा ।	प्रधान मंत्री सूखा सहायता निधि से दी गयी मुफ्त गेहूं की मात्रा
बिहार :	1,335.85 मीटरी टन	4,135 मीटरी टन
उत्तर प्रदेश :	281.5 ,,	651 ,,

दैवी विपदा जैसे सूखा आदि से सम्बन्धित सहायता कार्यों पर होने वाला खर्च सहायता के निर्धारित प्रतिमान के अनुसार केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच बांटा जाता है। आरम्भ में यह खर्च स्वयं राज्य सरकारें करती हैं यद्यपि राज्य सरकारों को सामान्यतया वित्तीय सहायता खर्च के लेखे प्राप्त होने से पहले ही दी जाती है। बिहार सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने 1966–67 में 10,07,24,126 रुपये और अप्रैल, 1967 के तीसरे सप्ताह तक 3,92,16,674 रुपये खर्च किए हैं। अन्य राज्य सरकारों द्वारा किए गए खर्च के आंकड़े अभी तक उनसे प्राप्त नहीं हुए हैं।

उर्वरक का लदान

814. **श्री सेझियान :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय बन्दरगाहों पर बड़ी मात्रा में उर्वरकों के लदान का है; और

(ख) यदि हां, तो इससे कितनी विदेशी मुद्रा की बचत की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) अमोनियम सल्फेट का आयात सन् 1962 से पर्याप्त मात्रा में किया जा रहा है। ऐसा प्रस्ताव है कि 1967 में 700,000 टोन्ज अमोनियम सल्फेट आयात किया जाए।

(ख) 1966–67 में अमरीका से सल्फेट आफ अमोनिया जो प्राप्त किया गया उससे 15 डालर प्रति टोन बचत का अनुमान है।

सहकारी क्षेत्र में पटसन का कारखाना स्थापित करना

815. **डा० रानेन सेन :**

श्री धीरेश्वर कलिता :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार ने राज्य में सहकारी क्षेत्र में पटसन का कारखाना स्थापित करने के लिए केन्द्र से सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार ने किस प्रकार की और कितनी सहायता की मांग की है; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी, हाँ ।

(ख) आसाम राज्य की सरकार ने निम्नलिखित मदों के सम्बन्ध में केन्द्र से सहायता मांगी है :

(एक) आसाम को-ओपरेटिव जूट मिल लिमिटेड, नवगोंग, द्वारा स्थापित किये जाने वाले पटसन मिल संयंत्र के लिये औद्योगिक (विकास और विनियम) अधिनियम 1951 के अधीन लाइसेंस की मंजूरी ।

(दो) सोसाइटी के हिस्से खरीदने के लिये वित्तीय सहायता ।

(तीन) मशीनरी के आयात के लिये विदेशी मुद्रा का नियत किया जाना ।

(चार) भारत के औद्योगिक वित्त निगम से 89 लाख रुपये का ऋण ।

(ग) राज्य सरकार/सोसाइटी के आवेदन पर निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :

(एक) प्रतिवर्ष 6910 टन जूट के माल के उत्पादन की क्षमता वाले प्रस्तावित मिल की स्थापना के लिये 26 मई 1962 को लाइसेंस जारी किया गया ।

(दो) जूट मिल को स्थापित करने वाली सोसाइटी से पूँजीगत हिस्से खरीदने के लिये आसाम राज्य की सरकार को 28·5 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है ।

(तीन) सोसाइटी को ब्रिटेन से मशीनरी मंगाने के लिये 34 लाख रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा दी गई है ।

(चार) 89 लाख रुपये के दीर्घ कालिक ऋण के आवेदन पर औद्योगिक वित्त निगम द्वारा अभी विचार किया जा रहा है ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा अनाज का समाहार

816. **श्री पी० राममूर्ति :**
श्री अ० क० गोपालन :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम ने दिसम्बर 1966 से फरवरी, 1967 के बीच की अवधि में कुल कितने अनाज का समाहार किया;

(ख) क्या सरकार ने इस अवधि में निगम द्वारा किये गये काम के बारे में अनुमान लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) भारतीय खाद्य निगम ने दिसम्बर, 1966 से फरवरी, 1967 तक की अवधि में लगभग 5·9 लाख मीटरी टन खाद्यान्न खरीदे हैं ।

(ख) और (ग) सरकार ने इस अल्प अवधि के लिये निगम के कार्य-चालन का कोई विशेष आंकन नहीं किया है।

मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) जिले में दुर्भिक्ष की स्थिति

817. **श्री के० पी० सिंह देव :**

श्री डी० एन० देव :

क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले चार वर्षों से उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में लगभग दुर्भिक्ष की स्थिति है; और

(ख) यदि हां, तो इन वर्षों में खाद्यान्न की कमी दूर करने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में बहुत घनी आबादी है और सामान्य वर्षों में भी खाद्यान्नों की उपलब्धि बहुत ज्यादा नहीं होती है। तथापि, मिर्जापुर जिले में किसी विशेष कमी की स्थिति के बारे में सितम्बर-अक्तूबर, 1966 से पूर्व हमें कोई सूचना नहीं दी गयी थी। केवल अक्तूबर, 1966 के बाद मिर्जापुर तथा अन्य पूर्वी जिलों में जरूरतें पूरी न होने के कारण गम्भीर कमी की स्थिति पैदा हो गयी थी।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को मिर्जापुर तथा अन्य पूर्वी जिलों में कमी की स्थिति का मुकाबला करने के लिये निम्नलिखित सहायता प्रदान की है :—

(1) आयातित खाद्यान्नों का केन्द्रीय आवंटन अक्तूबर के 40,000 मीटरी टन से बढ़कर फरवरी, मार्च और अप्रैल, 1967 के प्रत्येक महीने में लगभग 125,000 मीटरी टन कर दिया गया है।

(2) सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में बूढ़े और दुर्बल व्यक्तियों में मुफ्त बांटने के लिये राज्य सरकार को 8,000 मीटरी टन उपहार गेहूँ का नियतन किया गया है।

(3) दूध फीडिंग केन्द्रों के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को 3,444 मीटरी टन दुग्ध चूर्ण नियत किया गया है।

(4) राज्य सरकार को सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के लिए 70 मीटरी टन बिस्कुट, 20 मीटरी टन शुष्क मुनक्का और पर्याप्त मात्रा में विटामिन की गोलियां, बेबी फूड आदि दिये गये हैं।

इसके अलावा, सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में कुछेक स्वैच्छिक संगठनों ने मुफ्त भण्डारे भी चलाये हैं। मिर्जापुर में ऐसे भण्डारों की संख्या 63 है। इस उद्देश्य के लिए इन संगठनों को 281·5 मीटरी टन गेहूँ सरकारी इक्नामिक्स कीमत पर और प्रधान मन्त्री सूखा सहायता निधि से 651 मीटरी टन गेहूँ मुफ्त दिया गया है।

कोलम्बो योजना के अधीन आस्ट्रेलिया को द्विसदस्यीय दल का खाद्य सम्बन्धी अध्ययन के लिए दौरा

818. **श्री मणीभाई जे० पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य सम्बन्धी अध्ययन की कोलम्बो योजना के अन्तर्गत दो व्यक्तियों का एक दल विशेष दर्शकों के रूप में हाल ही में आस्ट्रेलिया गया था;

(ख) यदि हां, तो उस दल के सदस्यों के नाम क्या थे और यह दल किस उद्देश्य विशेष से आस्ट्रेलिया गया था; और

(ग) उनके दौरे का क्या परिणाम निकला ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिंदे) : (क) से (ग) : भारत सरकार ने आस्ट्रेलिया का दौरा करने के लिए कोई खाद्य अध्ययन दल नियुक्त नहीं किया है । तथापि, आस्ट्रेलिया सरकार ने कोलम्बो योजना के अन्तर्गत दो विशेष दर्शक एवार्ड दिये थे जिससे श्री सतवंत सिंह, व्यावहारिक कृषक जो कि भारतीय खाद्य निगम के एक निदेशक भी हैं, और सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी उस देश का दौरा कर वहां की कृषि विपणन प्रथाओं का अध्ययन कर सकें । सरकारी उम्मीदवार के स्थान पर निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री एन० पी० सेन को चुना गया था । उनके अवलोकन सरकार को अभी तक प्राप्त नहीं हुये हैं ।

विशाखपत्तनम् पत्तन

819. **श्री मणीभाई जे० पटेल** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे माल के आयात की सुविधा के लिए हाल में विशाखपत्तनम् बन्दरगाह पर कोई विशेष व्यवस्था की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस व्यवस्था के बाद इस पत्तन की क्षमता कितनी हो गई है; और

(ग) इस व्यवस्था पर कुल कितना खर्च आया है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य का संकेत मैसर्स कारोमंडल फरटिलाइजर लि० द्वारा फरटाइजरों के उत्पादन के लिये तीन से चार लाख टन वार्षिक की राशि के कच्चे माल के आयात के धरने उठाने के लिये अभी हाल ही में किये गये विशेष प्रबन्ध से है । यदि ऐसा है तो उत्तर हां में है । इस प्रयोजन के लिए अभी हाल ही में एक फरटिलाजर बर्थ बनाई गई है ।

(ख) फरटिलाइजर बर्थ के काम में लाये जाने से पत्तन की धरने उठाने की क्षमता लगभग 10·7 मिलियन टन से बढ़ कर 11 मिलियन टन वार्षिक हो जायेगी ।

(ग) बर्थ, जलसप्लाई, बिजली और निकर्षण के निर्माण पर अभी तक 42·60 लाख रुपये का व्यय किया गया है। शेष निकर्षण कार्य पर तथा अन्य सहायक कार्यों में लगभग 6 लाख रुपये का और व्यय किये जाने की आशा है।

छोटी सिंचाई योजना

820. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये पिछले पांच वर्षों में, वर्ष-वार, प्रत्येक राज्य को कुल कितनी राशि दी गई;

(ख) उक्त अवधि में प्रत्येक राज्य ने कुल कितनी राशि का उपयोग किया;

(ग) उक्त अवधि में इस राशि से प्रत्येक राज्य में कुल कितने नल-कूप खोदे गये; और

(घ) चौथी योजना अवधि के शेष वर्षों में इस कार्य के लिए प्रत्येक राज्य को कुल कितनी राशि देने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) तथा (ख) : 1958–59 से राज्यों को केन्द्रीय आर्थिक सहायता देने के लिए संशोधित पद्धति बनाई गई जिसके अनुसार केन्द्रीय आर्थिक सहायता "कृषि उत्पादन, लघु सिंचाई तथा भूमि विकास आदि" विकास के शीर्षकों के अन्तर्गत दी जाती है। योजनावार स्वीकृति देना 1958–59 के बाद बन्द कर दी गई। अतः केन्द्रीय सरकार ने 1962–63 तथा 1963–64 के दौरान लघु सिंचाई योजनाओं को अलग से कितनी राशि स्वीकृत की यह बताना सम्भव नहीं है। फिर भी वित्तीय वर्ष 1964–65 से केन्द्रीय आर्थिक सहायता अलग से शीर्षक लघु सिंचाई के लिए स्वीकृत की गई है। 1962–63 तथा 1963–64 के दौरान कृषि उत्पादन, लघु सिंचाई तथा भूमि विकास आदि के लिए और 1964–65 से 1966–67 के दौरान लघु सिंचाई के लिए जो केन्द्रीय सहायता नियतन की गई उसको प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०** 440/67]। 1965–66 तथा 1966–67 के लिए सहायता अस्थायी है।

(ग) लघु सिंचाई कार्यक्रम में विभिन्न योजनाएं हैं और नलकूप उनमें से एक है। नलकूपों के सम्बन्ध में जो जानकारी उपलब्ध है वह एक विवरण में प्रदर्शित की गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०** 440/67]।

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि के शेष वर्षों के लिए आकार तथा नापतोल को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

सोहना कस्बे का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

821. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के सहयोग से हरियाना सरकार का विचार सोहना का जहां पर हरियाना में गरम चश्में हैं, एक पर्यटन-केन्द्र के रूप में विकास करने का है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि प्रत्येक वर्ष इस स्थान को देखने के लिए अनेक भारतीय तथा विदेशी पर्यटक यहां आते हैं ;

(घ) क्या अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष के कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत के पर्यटन स्थानों में सोहना का नाम भी सम्मिलित कर लिया गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य सरकार से योजना के ब्यौरे की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ग) सोहना जाने वाले यात्रियों की संख्या के बारे में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । लेकिन सुविधाओं के अभाव के कारण यह स्थान इस समय पर्यटन स्थलों की सूची में सम्मिलित नहीं है ।

(घ) और (ङ) : जी, नहीं; क्योंकि अभी तक सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की गयी है ।

भारत में प्रमुख राजपथ

822. **श्री सेक्वीरा** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में प्रमुख राजपथ कौन कौन से हैं ;

(ख) इनमें से प्रत्येक सड़क पर एक गाड़ी में अधिक से अधिक कितने टन माल (जी० बी० डब्लू) ले जाने की अनुमति है; और

(ग) क्या अधिक माल ले जाने की अनुमति दी जाने वाली है और यदि हां, तो किन किन राजपथों पर तथा कब से ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग) : भारत सरकार प्रधानत: राष्ट्रीय मुख्यमार्ग घोषित सड़कों के लिए जिम्मेदार है । राष्ट्रीय मुख्य मार्गों के अलावा राज्य की अन्य सड़कों के लिए सम्बद्ध राज्य सरकार की जिम्मेदारी है । राष्ट्रीय मुख्य मार्ग तंत्र में शामिल सड़कों की एक सूची संलग्न है । इन मुख्य मार्गों पर चलने वाली मोटर गाड़ियों के लिए भार की परिसीमा में एक रूपता नहीं है क्योंकि इन सड़कों के विभिन्न भागों और इन पर के पुल व पुलियों की भार वाहन शक्ति में बड़ी भिन्नता है । यह परिसीमा सड़कों और पुलों की दशा के अनुसार अलग अलग सड़कों में अलग अलग हैं और अलग अलग राज्यों में भी भिन्न भिन्न हैं क्योंकि राष्ट्रीय मुख्य मार्गों और अन्य सड़कों के ऊपर चलने वाली मोटर गाड़ियों पर भार की परिसीमा लगाना राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है । हाल ही में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल के मुख्य इंजीनियरों के पास प्रस्ताव रखा गया कि दिल्ली–बम्बई और दिल्ली–कलकत्ता रास्तों में मोटर गाड़ियों में कुल भार की समान

परिसीमा 15 टन रखी जाय। भार की इस बढ़ी हुई परिसीमा को सड़क की पर्यटी और सड़क के ऊपर की संरचना के आवश्यकतानुसार मजबूत और सुधार किये जाते ही लागू किया जाएगा।

जल सम्भरण के लिए जलभृतों (ऐक्विफर्ज) का प्रयोग

823. **श्री म० ला० सौंधी :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खाद्य उत्पादन के लिए जल का संभरण सुनिश्चित करने के लिए जलभृतों के लाभों से परिचित हैं;

(ख) क्या सरकार ने जलभृतों को पुनः भरने और उनके प्रबन्ध पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन की कार्यवाही के वृत्तान्त और उसकी सिफारिशों का अध्ययन किया है;

(ग) क्या सरकार ने तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिए उन देशों के साथ पत्र-व्यवहार किया है, जिन्होंने जलभृतों के सम्बन्ध में अनुसन्धान परियोजना चालू की हुई है; और

(घ) क्या बड़े पैमाने पर जलभृतों का प्रयोग करने के लिए सरकार ने कोई योजना बनाई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) जी हां। खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय के अधीन का काम करने वाली समन्वेषी नलकूप संस्था जनवरी, 1955 से देश के विभिन्न भागों में जल के विषय में खोज कर रही है ताकि ऐसे क्षेत्रों का पता लगाया जा सके जहाँ सिंचाई के लिए नलकूप खोदे जा सकते हैं।

(ख) जी हां। समन्वेषी नलकूप संस्था के एक अधिकारी ने इन्टरनेशनल कान्फ्रेंस आन आर्टिफिशल रिसर्च एण्ड ऐक्विफर्ज मैनेजमेंट की बैठक में भाग लिया था जो मार्च 1967 में हेफा (इस्राइल) में हुई थी।

(ग) जी हाँ। पत्र-व्यवहार, भ्रमण तथा अन्तर्राष्ट्रीय सेमीनार गोष्ठियों में भाग लेकर दूसरे ऐसे देशों से सम्बन्ध स्थापित रखा जा रहा है जिन्होंने भूमिगत जल के विषय में प्रगति की हुई है।

(घ) जी हाँ। नलकूप संस्था चतुर्थ योजना की अवधि में देश के विभिन्न भागों में अपना कार्य जारी रखेगी। इसके अतिरिक्त चौथी योजना की अवधि में राज्यों द्वारा क्रियान्वित करने के लिए भूमिगत जल के सर्वेक्षण व अन्वेषण की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्वीकार की गई है। यह योजना समन्वेषी नलकूप संस्था के कार्यों के सम्पर्क रूप में आती और इसके अन्तर्गत केवल 250 फुट की गहराई तक ड्रिलिंग किया जायेगा।

मैसूर राज्य में बाजरे का सरपल्स स्टाक

824. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1961 से अब तक मैसूर राज्य में प्रति वर्ष कितना बाजरा उगाया गया;

(ख) क्या मैसूर राज्य में बाजरे का फालतू स्टाक पड़ा हुआ है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार मैसूर से फालतू बाजरे को गुजरात भेजने का प्रस्ताव करेगी जहां बाजरे की भारी मांग है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) 1960–61 से मैसूर राज्य में बाजरे की निम्नलिखित पैदावार हुई है :

1960–61	61–62	62–63	63–64	64–65	65–66
129	100	120	154	113	85

(आंकड़े हजार मीटरी टन में)

(ख) और (ग) राज्य सरकार ने कुछ अधिशेष स्टाक की घोषणा की है और यह स्टाक गुजरात सहित कमी वाले राज्यों को अलाट किया गया है। मैसूर राज्य के पास और अधिशेष स्टाक के बारे में अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। यदि मैसूर सरकार द्वारा कोई और अधिशेष स्टाक दिया गया तो गुजरात को सारी मात्रा या उसका कुछ भाग देने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

Cultivation of Sugar-Cane

825. Shri Rabi Ray :
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Madhu Limaye :
Shri Mohan Prasad :
Shri Maharaj Singh Bharti :
Shri George Fernandes :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that cultivation of sugarcane is not possible this year due to the non-availability of water; and

(b) if so, whether his Ministry had asked for any special measures to be adopted by the Ministry of Irrigation and Power ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation. (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Weather conditions in the current year have not been favourable and the sowings are reported to have been affected on account of inadequate rains in the major sugarcane growing areas, particularly Bihar and East Uttar Pradesh.

(b) No, Sir. Central assistance is being given for minor irrigation schemes which cover sugarcane crop also.

खाद्यान्न के मूल्य

826. श्री पी० गोपालन :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री अब्राहम :
श्री एस्थोस :
श्री उमानाथ :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कुछ समाचार पत्रों में छपी इस आलोचना की ओर

दिलाया गया है कि भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्न के मूल्य कम करने में असफल रहा है, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : **(क) और (ख)** समाचार पत्रों में ऐसी कोई विशिष्ट आलोचना नहीं देखी गयी है । भारतीय खाद्य निगम को अब तक केवल सरकार की ओर से अधिप्राप्ति का काम सौंपा गया है और किसी भी हालत में बड़े पैमाने पर खुले बाजार में खाद्यान्नों की खरीदारी और बिक्री का काम नहीं सौंपा गया है । अत: यह आशा करना जल्दबाजी होगी कि भारतीय खाद्य निगम के कार्यों से खुले बाजार के भावों पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा है ।

उड़ीसा में नारियल का उत्पादन

827. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा राज्य में नारियल के उत्पादन का वार्षिक क्ष्य क्या है;

(ख) क्या तीसरी **पंचवर्षीय** योजना में भी उड़ीसा के लिए इस प्रकार का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था और यदि हां, तो क्या;

(ग) क्या यह लक्ष्य पूरा हो गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में नारियल का वास्तविक उत्पादन कितना था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) से (घ) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

उड़ीसा द्वारा बिहार को धान का सम्भरण

828. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उड़ीसा सरकार बिहार सरकार तथा पश्चिम बंगाल सरकार को क्रमश: 10,000 टन तथा 20,000 टन धान सीधे भेजने के लिए सहमत हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो वह किन मूल्यों पर सप्लाई कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) उड़ीसा सरकार बीज के लिए बिहार को 20,000 मीटरी टन धान

देना मान गयी है। पश्चिमी बंगाल को धान सप्लाई करने का कोई प्रस्ताव नहीं है यद्यपि उड़ीसा केन्द्रीय आवंटन के अनुसार पश्चिमी बंगाल को चावल सप्लाई कर रहा है।

(ख) उड़ीसा सरकार बिहार से धान की ली जाने वाली दरों के बारे में अभी विचार कर रही है।

1966–67 में उड़ीसा में फसलों को हुई क्षति

829. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री ए० दीपा : **श्री जी० सी० नायक :**
श्री प्र० के० देव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966–67 के फसली वर्ष में सूखे के कारण उड़ीसा में फसलों को हुई क्षति के बारे में सरकार को उड़ीसा सरकार से कोई रिपोर्ट मिली है;

(ख) यदि हां, तो फसलों को कितनी क्षति हुई है;

(ग) क्या सूखे की स्थिति का मुकाबला करने के लिए राज्य सरकार ने कोई सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता मांगी गई थी और अब तक क्या सहायता दी गई है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार ने 1966–67 की समस्त फसलों के बारे में कोई विवरण नहीं भेजा है। राज्य सरकार ने धान की केवल कुछ पछेती किस्मों के बारे में जानकारी भेजी है परन्तु यहां भी उसने वे आधारिक आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये हैं जिनकी तुलना में कमी उत्पन्न हुई है। 1966–67 की फसलों की हानि के बारे में अनुमान लगाना संभव नहीं है केवल इतना ही अनुमान है कि भारत सरकार को उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1964–65 के अधिकतम उत्पादन से उत्पादन 14.1 प्रतिशत कम है।

(ग) जी हाँ!

(घ) राज्य सरकार को 1966–67 की अवधि में 1059.62 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई थी। इसमें से 259.62 लाख रुपये की राशि 1965–66 के दुर्भिक्ष को दृष्टि में रखते हुए 1965–66 तथा 1966–67 के लिए राहत कार्यों के लिए दी गई थी। 1965–66 में 45 लाख रुपये का ऋण भी दिया गया था। जहां तक चालू वर्ष के दौरान में उनके 2.22 करोड़ रुपये के ऋण सम्बन्धी प्रस्ताव का सम्बन्ध है, वित्त मन्त्रालय ने राज्य सरकार से सूखे की स्थिति व प्रस्तावित राहत सम्बन्धी कार्यों के विषय में जानकारी भेजने के लिए प्रार्थना की है। योजना आयोग, वित्त मन्त्रालय तथा उड़ीसा सरकार के अधिकारियों के बीच हुए विचार विमर्श के दौरान में उड़ीसा सरकार के लिए राहत कार्यों के विषय में सहायता देने के विषय में स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी।

केरल में कोवालम का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

830. **श्री पी० विश्वम्भरन :**
श्री उमानाथ :
श्री अनिरुद्धन :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री अब्राहम :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री एसथोस :

क्या **पर्यटन तथा असनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में कोवालम का पर्यटन केन्द्र के रूप में केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत विकास किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित विकास का स्वरूप क्या है और इस पर कुल कितना व्यय होने का अनुमान है;

(ग) सरकार इसकी लागत का कितने प्रतिशत व्यय करेगी; और

(घ) इस योजना के कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) ; पर्यटक यातायात खासकर विशेष चार्टरों से आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कोवालम का एक समुद्र-तटीय 'बिहार-स्थल' (सी-साइड रिजॉर्ट) के रूप में विकास किया जायेगा। इस योजना में 'महल-सम्पत्ति' का अभिग्रहण एवं उसे नया रूप देना, 14 कमरों के ब्लॉक और एक 50 कमरों के 'तीन स्टार' होटल का निर्माण, पुराने और नये स्नानागारों को नया रूप देना, मण्डप पथों (पैवेलियन पाथ्स) का बनाना और सम्पूर्ण आरामगाह को एक प्राकृतिक दृश्य का रूप देना, नौकाओं तथा अन्य जलीय मनोरंजन सुविधाओं की व्यवस्था करना सम्मिलित हैं। प्रस्तावित व्यय 103.50 लाख रुपये का होगा जिसमें से 95 लाख रुपये का व्यय केन्द्रीय सरकार वहन करेगी। उम्मीद है सारी स्कीम चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूर्ण हो जायेगी।

भारतीय खाद्य निगम

831. **श्री काशीनाथ पाण्डे :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में भारतीय खाद्य निगम बनाये रखने की आवश्यकता पर आपत्ति की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हवाई सेवाओं को रोकना अथवा देरी करना

832. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के एक विमान चालक ने एक परिचारिका से झगड़ा हो जाने के कारण 12 अप्रैल, 1967 की मध्यान्ह–पश्चात् को मद्रास में कारपोरेशन के एक 'केरावल' हवाई जहाज की उड़ान रोक दी;

(ख) पायलटों और परिचारिकाओं के परस्पर झगड़े के फलस्वरूप होने वाली इस प्रकार की बाधाओं तथा देरी को रोकने के लिये कारपोरेशन ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या विमान चालकों, परिचारिकाओं तथा अन्य कर्मचारियों के लिये उड़ान के समय कोई आचार-संहिता बनाई गयी है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) कामण्डर और विमान परिचारिका के बीच गलत-फहमी होने के कारण मद्रास में उड़ान लगभग पन्द्रह मिनट तक रुकी रही।

(ख) मामले की जांच की जा रही है और कारपोरेशन द्वारा आवश्यक प्रतीकारात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(ग) उड़ान इंजीनियर, दिक्चालक (नेवीगेटर), केबिन परिचारक और पर्सर कैप्टेन की कमान के अधीन होते हैं और इस प्रकार उन्हें कैप्टेन के न्यायसंगत आदेशों का पालन करना होता है।

जयन्ती शिपिंग कम्पनी

833. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० तेजा और जयन्ती शिपिंग कम्पनी द्वारा गबन की गई 16.90 लाख रुपये की भविष्य निधि की राशि का लाभ कर्मचारियों को दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं,

(घ) क्या कर्मचारियों के वेतन में से काटी गई 1.20 लाख रुपये की आयकर की राशि भी, जिसका डा० तेजा ने गबन कर लिया था, आयकर विभाग को दे दी गई है अथवा क्या आयकर पुनः कर्मचारियों से वसूल किया गया है;

(ङ) यदि यह राशि दे दी गई है, तो कब; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा०वी०के०आर०वी० राव) : (क) और (ख) : जयन्ती शिपिंग कम्पनी के मौजूदा प्रबन्धकों ने आरक्षित निधि संचय को आरक्षित निधि के

ट्रस्टियों के नाम में जमा करा दिया है और उन्होंने इस निधि को बम्बई के स्टेट बैंक आफ इण्डिया में लगा दिया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) और (ङ) : पिछले प्रबन्धकों ने आयकर देयता की अदायगी कर्मचारियों के वेतन से काट कर दिल्ली के अधिकारियों को 30-3-1966 को कर दी थी और 10-6-1966 को सरकार द्वारा प्रबन्ध हाथ में लिये जाने के समय कुछ भी बाकी नहीं था ।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बलियापट्टम नदी पर सड़क का पुल

834. **श्री श्रीकान्तन नायर :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री पी० राममूर्ति :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल सरकार ने बलियापट्टम नदी के ऊपर सड़क का एक स्वतंत्र पुल बनाने का कार्य "अन्तर्राज्यीय तथा आर्थिक महत्व की सड़कों" की योजना में सम्मिलित करने तथा उसके लिये धन नियतन करने के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है,

(ग) क्या सरकार को पता है कि गर्डरों को सुदृढ़ करने के लिये रेल–एवं–सड़क पुल एक वर्ष से अधिक समय के लिये बन्द किया जायेगा, और

(घ) यदि हाँ, तो सड़क परिवहन के इस क्षेत्र में जनता को अनुभव होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) जी हां । चौथी योजना में इस काम के लिए सहायता अनुदान देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) और (घ) : जी हां । गिरदारों को सशक्त करने के प्रस्ताव से एक वर्ष या अधिक समय तक पुल के सड़क यातायात को हटाना जरूरी होगा । यातायात को अलग हटाने के लिए राज्य सरकार से घाट–सेवा फिर से खोलने के लिये कहा गया है ।

नींडकारा पुल

835. **श्री श्रीकांतन नायर :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या नींडकारा पुल के कुओं की परीक्षणात्मक भराई (टैस्ट लोडिंग) का कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कंकरीट भरने का काम करने के आदेश दिये गये हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस पुल से सम्बन्धित कितने डिजाइन ब्योरे सरकार के पास विचाराधीन पड़े हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० बी० के० आर० बी० राव) : (क) से (ग) : स्तम्भ संख्या पी–2 के नीचे एक कूप का भार परीक्षण पूरा हो गया है, किन्तु इस एक परीक्षण का परिणाम निश्चयात्मक नहीं समझा जाता है । अत: विभिन्न कूपों के बन्दोबस्त में संभाव्य विभिन्नता निर्धारण करने के लिए एक और कूप के भार परीक्षण का आदेश दे दिया गया है । अभी कंकरीट करने के कार्य के लिये आज्ञा नहीं दी गई है क्योंकि यह भार परीक्षण के परिणामों से निकाले गये निष्कर्ष पर निर्भर करेगा ।

(घ) बेयरिंग, पियर कैप, सुपर स्ट्रक्चर तथा डेकिंग में उध्वधिर वक्र की डिजाइनें भारत सरकार के पास पड़ी हैं । इन डिजाइनों में, किये जा रहे भार परीक्षण के परिणामों के प्रकाश में, परिवर्तन की आवश्यकता पड़ सकती है ।

दिल्ली में शीतागार

836. **श्री शारदा नंद :** **श्री भारत सिंह :**
श्री जे० बी० सिंह : **श्री रणजीत सिंह :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृत्रिम रूप से कमी पैदा करने तथा मूल्य वृद्धि करने की दृष्टि से व्यापारी, फलों तथा सब्जियों को जमा करने के लिये दिल्ली में शीतागारों का दुरूपयोग कर रहे हैं, और

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यापारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिंदे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पर्यटन केंद्र के रूप में इजूमलाई (केरल) का विकास

837. **श्री अ० कं० गोपालन :**
श्री पी० राममूर्ति :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात की संभाव्यता का पता लगाने के लिये कि कन्नानूर जिले में इज़ूमलाई का एक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास किया जा सकता है, कोई अधिकारी वहां गया था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या सरकार इस प्रस्ताव को चौथी योजना में शामिल करने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) और (ख) : जी नहीं। इस विभाग का कोई अधिकारी इजूमलाई, जिला कन्नानूर, की पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास की सभावना की पड़ताल करने के उद्देश्य से वहां नहीं गया।

(ग) और (घ) : चौथी योजना में इजुमलाई में पर्यटन सुविधाओं के विकास का कोई प्रस्ताव नहीं। परन्तु इजुमलाई से कुछ ही दूरी पर स्थित कन्नानूर में एक पर्यटक बंगले का निर्माण पर्यटन सम्बन्धी चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है, जिसका व्यय-भार केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में वहन किया जायेगा।

बीज फार्म

838. **श्री एस० एन० मैटी :**
श्री स० चं० सामंत :
श्री विभूति मिश्र :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री देवकीनंद पटोदिया :
श्री राम किशन गुप्त :
श्री रा० बरुआ :
श्री सी० सी० देसाई :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत संघ की सहायता से भारत मे पांच बीज फार्म स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि केरल ने मांग की है कि एक ऐसा बीज फार्म केरल में स्थापित हो;

(ग) इस प्रकार के फार्म की मुख्य बातें क्या होंगी;

(घ) सोवियत सरकार का दायित्व क्या होगा;

(ङ) क्या सोवियत संघ से कोई समझौता हो गया है और उस पर हस्ताक्षर हो गये हैं; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिंदे) : (क), (ग) और (घ) से (च) : चौथी योजना की अवधि में अनेक राजकीय फार्मों की स्थापना करने का प्रस्ताव है। रूसी सरकार के साथ तय हुए एक करार के अनुसार रूसी सरकार पांच राजकीय फार्मों के लिए मशीनों को उपहार के रूप में देगी। इन फार्मों का उद्देश्य यह है कि उन्नत किस्मों के बीजों को उगाकर सप्लाई किया जाये।

(ख) केरल सरकार ने केरल में एक ऐसे फार्म की स्थापना करने के लिए प्रार्थना की है।

बिहार राज्य के लिये खाद्यान्नों की सप्लाई

839. **श्री इंद्रजीत गुप्त :** **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री बेनी शंकर शर्मा : **श्री शिव चंद्र झा :**

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में कुछ क्षेत्रों को अकालग्रस्त घोषित कर दिये जाने के बाद भी केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को न्यूनतम आवश्यक मात्रा में खाद्यान्न नहीं भेज रही है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र से यह प्रार्थना की थी कि उसे अन्य राज्यों से मोटा अनाज सीधे खरीदने की अनुमति दी जाये; और

(ग) क्या यह अनुमति नहीं दी गई और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिंदे) : (क) सरकार के पास वितरण के लिये जितना खाद्यान्न उपलब्ध है और अन्य राज्यों की न्यूनतम मांगे पूरी करने की आवश्यकता को ध्यान में रख कर बिहार को अधिक से अधिक सम्भव खाद्यान्नों की सप्लाई की जा रही है ।

(ख) और (ग) बिहार सरकार ने जब कभी भी केन्द्रीय सरकार के सामने अन्य राज्यों से अनाज की कुछ मात्राएं खरीदने के लिये विशिष्ट प्रस्ताव रखे उन्हें आवश्यक अनुमति दी गयी थी ।

ओबराय इंटरकॉन्टिनैन्टल होटल, नई दिल्ली

840. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की कुछ रिपोर्ट मिली है कि ओबराय इन्टर-कॉन्टिनेन्टल होटल, नई दिल्ली में भारतीयों तथा विदेशियों के बीच भेद-भाव बरता जाता है;

(ख) क्या यह सच है कि इस होटल के कुछ भागों में भारतीयों को जाने की आज्ञा नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Rationing of Maida, Suji Etc.

841. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the poor people are undergoing hardships as a result of short supply of ration to them;

(b) whether it is a fact that bread, cake and biscuit factories and rice and flour mills waste 10 percent of grains in the form of bran at the time of making Suji;

(c) whether Government propose to bring maida, suji, cake, bread and other products prepared from foodgrains under rationing with a view to allow the people to draw rationed items in larger quantity;

(d) if so, when; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agricluture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Short supply is very occasional. It is true that whenever rationed articles cannot be supplied to the full extent of the quantum fixed, hardship is caused to the people.

(b) The percentage of wheat bran separated in the process of producing maida and suji by roller flour mills varies from 20 to 22 per cent.

This bran is not wasted but is used as animal food. Suji is not produced by rice mills. Bread, cake and biscuit makers do not separate any bran from maida and suji which they use as such for their products.

(c) to (e) It is not proposed to bring cake, bread and such other cooked products under rationing. Inclusion of maida and suji under rationing is done as and when it becomes necessary to do so for the purpose of ensuring equitable distribution of these products. The total consumption of maida and suji is so small as compared to that of wheat grains and Atta that their inclusion under rationing would not ibso **facto** enable Government to increase the quantum of ration substantially.

Seizure of Foodgrains

842. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Y. S. Kuchwah :
Shri Onkar Singh :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of traders arrested in different States in the country since the 1st March, 1967;

(b) the quantity of foodgrains seized from them; and

(c) the number of traders against whom prosecutions are in progress and the number of persons acquitted ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) to (c) : Information is being collected from the State Governments/Union territories and would be placed on the Table of the Sabha as soon as it is received.

Ban on Khoya Preparations in Delhi

843. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Onkar Singh :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that milk is brought to Delhi under the Delhi Milk Supply Scheme from towns of Faridabad, Palwal and Hodel, in Haryana;

(b) if so the total amount of milk brought daily from these places; and

(c) whether Government contemplates to ban the preparation of Khoya in Delhi to meet the milk shortage ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Small quantity of milk is being collected by the Delhi Milk Scheme at Palwal and Hodel. No milk is being collected at Faridabad.

(b) Quantity of milk procured from these places was as follows on 22.5.1967:

Palwal :	22.04 Quintals.
Hodel :	2.43 Quintals.

(c) Delhi Milk Products Order 1967, prohibiting manufacture, import, sale, service or supply of certain milk products in the Union Territory of Delhi upto 31st August, 1967 has been enforced w.e.f. 17th May, 1967.

Famine Areas in Bihar

844. Shri Bibhuti Mishra :
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that he had invited the Deputy Chief Minister of Bihar to Delhi round about the 29th April, 1967 to hold talks regarding the declaration of certain areas of Bihar as famine-stricken by Government of that State; and

(b) if so, the details of the talks held ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Famine in Bihar

845. Shri Bibhuti Mishra :
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Council of Ministers of Bihar have declared certain Districts as famine-stricken areas;

(b) if so, whether the Central Government have independently, through its own administrative machinery, collected place-wise and District-wise statistics in respect of 17 Districts of Bihar regarding the total agricultural produce obtained in each crop during the year 1965, 1966 and in 1967 upto 22nd May; and

(c) if so, the conditions prevalent in different areas of District Champaran and in this District as a whole ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

सुपर बाजार, नई दिल्ली

846. **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री के० एन० मधुकर :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली के सुपर बाजार में काम करने वाले प्रबन्धक अधिकारियों तथा अन्य वर्गों के कर्मचारियों को कितना कितना वेतन मिलता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिंदे) : नई दिल्ली के सुपर बाजार में काम करने वाले प्रबन्धक अधिकारियों तथा अन्य वर्गों के कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन की दरें साथ जुड़े विवरण में दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया–देखिये एल० टी० संख्या** 441/67]

राष्ट्रीय समुद्री दिवस

847. **श्री उमानाथ** :
श्री के० रामानी :

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय समुद्री दिवस गत चार वर्षों से सारे देश में मनाया जा रहा हैं,

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन समारोहों पर कुल कितनी राशि खर्च की है, और

(ग) राज्य सरकारों ने कुल कितनी राशि खर्च की है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) पिछले चार वर्षों से देश के समस्त बड़े पत्तनों में और कुछ मध्यवर्ती तथा छोटे पत्तनों में और नई दिल्ली में पिछले तीन वर्षों से राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता रहा है।

(ख) भारत के विभिन्न स्थानों में राष्ट्रीय समुद्री दिवस के समारोह का प्रबन्ध केन्द्रीय राष्ट्रीय समुद्री दिवस समारोह समिति, बंबई द्वारा किया जाता है और समारोह का समस्त व्यय समिति द्वारा विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त चन्दों द्वारा किया जाता है। यदि आव-श्यकता समझी जाती है तो भारत सरकार तदर्थ सहायता अनुदान देती है। पिछले चार वर्षों में भारत सरकार द्वारा दी हुई सहायता का व्योरा नीचे दिया जाता है।

वर्ष	सहायता अनुदान की राशि
1964	20,200 रु०
1965	10,000 रु०
1966	शून्य
1967	2000 रु०

(ग) इस समारोह में राज्य सरकारें कोई सीधा व्यय नहीं करती हैं।

Ballot Papers sent by Post by the Armed Forces personnel

848. Shri Kanwar Lal Gupta : Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the ballot paper sent by post by the Armed Forces Personnel during the last General Elections were opened by the Censor Department; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri D. R. Chavan) : (a) No such complaint has been received.

(b) Does not arise.

Allocation For Gosamvardhan and Animal Husbandry

849. Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri O. P. Tyagi :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the amount allocated for Gosamvardhan and Animal Husbandry in the First Second and Third Five Year Plans;

(b) the amount utilised; and

(c) the number of gosadans and cow-milk production centres opened so far and the number of cows kept in them and the expenditure incurred thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) to (c) : A statement giving the required information is attached. **[Placed in Library, See No. LT–442/67]**

सूखे से पीड़ित व्यक्तियों के लिये निर्धारित धन का दुरुपयोग

850. **श्री देवकीनंदन पटोदिया :**
श्री रा० बरूग्रा :
श्री जी० एस० मिश्र :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि कमी वाले राज्यों में सूखे से पीड़ित व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के लिये निर्धारित राशियों का दुरुपयोग किया जा रहा है अथवा इसका उपयोग अन्य कार्यों के लिये किया जा रहा है,

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्य सरकारों से तथ्यों की जानकारी प्राप्त की है, और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने तदुपरान्त इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है जिससे सहायता कार्यों के लिये निर्धारित धनराशि उन्हीं कार्यों के लिये ही खर्च की जाय ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिंदे) : (क) जी नहीं। सरकार को ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ख) और (ग) : क्योंकि सहायता योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता का समायोजन राज्य सरकारों द्वारा दिये गये खर्च के लेखा परीक्षित आंकड़ों के आधार पर किया जाता है, इसीलिये लेखा परीक्षा के दौरान यदि कोई अनियमितताएं ध्यान में लायी जाएंगी तो केन्द्रीय सहायता का भुगतान करते समय उन पर विधिवत ध्यान रखा जाएगा।

अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष

851. **श्री स्वैल :**
श्री किंकर सिंह :
श्री कर्णी सिंह :
श्री रा० कृ० बिड़ला :
श्री कोलाई बिरुआ :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री इंद्रजीत मल्होत्रा :
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री देवकीनंद पटोदिया :
श्री मीठा लाल :
श्री सी० सी० देसाई :
श्री रा० बरुआ :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री** 28 मार्च, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 85 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष अब तक कितना सफल रहा है;

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष के अन्तर्गत कितने पर्यटक अब तक भारत आये हैं और वे किन किन देशों से आये हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) (क) : अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष के दो घोषित उद्देश्य (1) विदेशों में भारत-पर्यटन को प्रोत्साहित करना, तथा (2) देश में पर्यटन के महत्व की चेतना उत्पन्न करना, है। वीजा शुल्क को समाप्त करना, भारतीय दूतावासों द्वारा वीजा का तत्काल जारी करना, अस्थायी अवतरण परमिटों की अवधि को 72 घण्टे से बढ़ाकर 7 दिन करना, पर्यटक सामान नियमों को और अधिक उदार बनाना, जैसी रियायतों तथा अन्य सुविधाओं और विदेशों में स्थित पर्यटक कार्यालयों, भारतीय दूतावासों, तथा एयर इण्डिया के कार्यालयों द्वारा किये गये प्रयत्नों के परिणाम सम्भवत: 1967 के अन्त तक जाने जा सकेंगे, जबकि इस वर्ष देश में आने वाले पर्यटकों की पिछले वर्ष आये पर्यटकों से तुलना करना सम्भव हो सकेगा। भारत में विभिन्न स्थानों पर भारतीय त्यौहारों के अवसरों पर अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन सप्ताहों के मनाने से भारतीय त्यौहारों के प्रचार में और देश में पर्यटन के महत्व की चेतना उत्पन्न करने में मदद मिल रही है।

(ख) : प्रारंभिक अनुमान के अनुसार और अब तक उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर जनवरी से मार्च, 1967 तक की अवधि में कुल लगभग 40,800 विदेशी पर्यटक भारत आये। 1966 में जनवरी से मार्च तक 38,286 पर्यटक आये थे। जनवरी से मार्च, 1967 तक के आंकड़ों का राष्ट्रिकतानुसार विश्लेषण अभी उपलब्ध नहीं है।

(ग) सम्पूर्ण वर्ष में पर्यटन से होने वाले विदेशी मुद्रा के अर्जन का अनुमान कैलेण्डर वर्ष के अन्त में लगाया जाता है। इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष के पहले तीन महीनों में में अर्जित विदेशी मुद्रा के आंकड़े देना संभव नहीं है।

खंड विकास अधिकारियों के पद की समाप्ति

852. **श्री स्वैल :**
डा० कर्णी सिंह :
श्रीमती निर्लेप कौर :
श्री किकर सिंह :
श्री बैरो :
श्री रा० कृ० बिड़ला ।
श्री कोलाई बिरुआ :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री विभूति मिश्र :
श्री कमल नयन तिवारी :
श्री ए० थोस :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री मधु लिमये :
श्री स० मो० बनर्जी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री स० चं० सामंत :
श्री एस० एन० मैती :
श्री ए० के० किस्कू :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री रा० बरुआ :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को उनके राज्यों में खण्ड विकास अधिकारियों के पद को समाप्त करने के लिये कोई निदेश दिये हैं :

(ख) यदि हां, तो उस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) किन राज्यों में खण्ड विकास अधिकारियों के पद को समाप्त कर दिया गया है अथवा करने का विचार है तथा इसके कारण क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) मध्य प्रदेश में खण्ड विकास अधिकारियों के पदों को 1 जनवरी 1966 से समाप्त कर दिया गया है। ऐसा समझा जाता है कि सरकार ने यह निर्णय इस आधार पर किया है कि चूंकि विकास खंडों में होने वाला अधिकतर काम खेती के क्षेत्र से सम्बद्ध है, इसलिये स्वयं कृषि विभाग अपने अधिकारियों के माध्यम से इस काम की देखभाल कर सकता है।

केन्द्रीय सरकार को किसी भी राज्य सरकार से खंड विकास अधिकारियों के पदों की समाप्ति के सम्बन्ध में कोई निश्चित प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

चुनावों के दौरान हेलिकॉप्टरों का प्रयोग

853. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री मधु लिमये :
श्री जे० एच० पटेल :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई नगर में फरवरी, 1967 के चुनाव अभियान के दौरान नियमों तथा सुरक्षा विनियमों का उल्लंघन करते हुए एक हेलीकोप्टर विमान के प्रयोग के बारे में सरकार को कोई शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो वे शिकायतें क्या हैं ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) : जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

अमरीका से खाद्य सहायता

855. **श्री दी० चं० शर्मा :** **श्री हुकम चंद कछवाय :**
श्री राम सिंह आयरवाल : **श्री इंदुलाल याज्ञिक :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन आरोपों पर विचार किया गया है कि सरकार ने संयुक्त राज्य अमरीका से पी० एल० 480 करार के अन्तर्गत खाद्य सहायता तथा अन्य सहायता प्राप्त करने के लिये बहुत ही अपमानजनक शर्तें स्वीकार की हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिंदे) : (क) भारत सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका से पी० एल० 480 के अधीन खाद्यान्न और अन्य सहायता प्राप्त करने के लिये कोई अपमानजनक शर्तें स्वीकार नहीं की हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

Installation or Tubewells in Bihar, U. P. and Madras

856. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of tube wells installed in Bihar, Uttar Pradesh and Madras respectively before 1958 and the number of those installed thereafter till 1966;

(b) the acreage of land under irrigation in each State separately;

(c) the number of tube wells in each State which are not being used for want of repairs; and

(d) the amount spent on new tubewells and on the repairs of old tubewells respectively in these States during the last three Plans ?

The Minister of State in the Minister of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) to (d) : The required information is being collected from the Governments of Bihar, Uttar Pradesh and Madras and would be laid on the Table of the Sabha, as soon as it is collected.

Prices of Foodgrains

857. Shri Sidheshwar Prasad; Shri S. M. Banerjee : Shri Madhu Limaye : Shri Hukam Chand Kachwai : Shri Ram Singh Ayarwal : Shri Mohsin : Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the steps taken so far to bring down the prices of foodgrains of all kinds; and

(b) the effect thereof on prices in each State separately ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) :

(a) A statement is given below :

Statement

Prices of foodgrains can be brought down in the long run only by a substantial increase in indigenous production for which Government have taken various measures. In order to meet the situation arising out of shortage of foodgrains, which has resulted in the rise in prices, Government have gradually extended the system of public distribution. The system now covers over 23 crores of population and Central Government supplies large quantities for distribution at subsidised prices. The other important steps taken to bring down the prices of foodgrains include intensification of procurement, large imports, regulatory measures on trade, control on bank advances. etc.

(b) It is difficult to isolate the effects of Government steps on the market prices in Sany tate.

Elections to Parliament and Vidhan Sabhas

858. Shri Sidheswar Prasad : Will the Minister of Law be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that suggestions have been received for holding elections to Parliament and Vidhan Sabhas during different periods;

(b) if so, the basis thereof; and

(c) the reaction of the Election Commission in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri D. R. Chavan) : (a) Yes, Sir.

(b) The reason given in support of the suggestion was that it will create and maintain healthy democracy and two party system in the country.

(c) The Election Commission did not agree to the suggestion for the reasons stated at page 44 of Chapter VII of the Report on the Third General Elections in India 1962 as under :—

"The Legislative Assemblies of Kerala and Orissa had been elected only in February 1960 and June 1961, respectively, and consequently in 1962, general elections were not due in these two States so far as their Legislative Assemblies were concerned. The fact that two States have thus fallen out of step and will in future have to hold their Assembly elections one or two years before the parliamentary general election in the country raises the interesting question whether this is not a desirable state of affairs. It could be urged that by dissociating the two general elections and holding them separately in each State, electors would have a better opportunity of appreciating the different issues involved. Theoretically this is no doubt a valid argument. Practical consideration of national economy and administrative convenience, however, ma e it distinctly preferable to hold the two general elections simultaneously all over the country. Whether it be for Parliament or for the State Assembly, a general election necessarily involves the wholesale diversion of administrative effort to that task for about six weeks; and of course, it costs the national exchequer almost twice as much to hold the two elections separately as to hold them simultaneously. It is obviously desirable that this duplication of effort and expense should, if possible, be avoided."

पटना के समीप गंगा नदी पर पुल

859. **श्री विश्वनाथ राय :** **श्री राम किशन गुप्त :**
श्री विभूति मिश्र : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना के निकट गंगा नदी पर पुल बनाने की योजना अन्तिम रूप से तैयार हो चुकी है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव०) : (क) और (ख) : जी नहीं। प्रस्तावित पुल राज्य सड़क पर पड़ता है। अतः इस योजना से मुख्यतः बिहार राज्य संबद्ध है। एक उपयुक्त स्थान न मिलने के कारण जिससे पटना नगर सुरक्षित रहे इसे अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका। समस्या के सुलझाने के लिये अभी हाल ही में राज्य-सरकार ने एक फर्म मे० जे० जी० वाइट इन्जीनियरिंग कारपोरेशन आफ न्यूयार्क से अभी तक सुझाये स्थानों के अध्ययन के लिये और उपयुक्त स्थान की सिफारिश के लिये एक समझौता किया है।

Prices of Rationed Commodities in Delhi

861. Shri Ram Charan : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the prices of rationed commodities have been raised many a times after rationing was introduced in Delhi;

(b) if so, the number of times the prices were raised and the commodities affected thereby; and

(c) the impact of this increase on the prices of other commodities sold in the market ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) and (b) : The selling prices of rationed food commodities viz. rice, wheat and wholemeal atta were raised only twice in Delhi since the introduction of rationing; once, consequent upon the general revision in the issue prices of foodgrains supplied to different State Governments from Central stocks and secondly, on a revision made in the retailers' margin of profit.

As regards sugar, the price was raised in March 1966 but it was reduced in October 1966. It was, however, again raised in February, 1967. The margin of profit to the retailers' was also raised once in case of sugar.

(c) There has been no significant increase in the prices of other commodities in Delhi.

Tour of Drought - Affected Areas

862. Shri Ram Charan : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state ;

(a) the number of Officers and employees of his Ministry who went on tours of the drought-stricken areas of Uttar Pradesh and Bihar from the Ist September, 1966 to 31st March, 1967; and

(b) the total expenditure incurred thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation. (Shri Annasaheb Shinde) : (a) 75 (Seventy-five).

(b) Rs. 35,134.45 (Rupees thirty-five thousand one hundred thirty-four and paise forty-five only)

उड़ीसा से चावल का निर्यात

863. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा ने जो अन्य राज्यों को 1966–67 में 75,000 टन चावल देने का वचन दिया था उसमें से उसने अब तक कितना चावल दूसरे राज्यों को दिया है ;

(ख) पश्चिम बंगाल, बिहार तथा केन्द्रीय पूल को इसमें से कितना चावल दिया गया है;

(ग) भारतीय खाद्य निगम के द्वारा अन्य राज्यों को कितना चावल भेजा गया; और

(घ) 20 मई, 1967 तक खाद्य निगम के द्वारा तथा राज्य सरकार द्वारा उड़ीसा में कितना चावल खरीदा गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 71,739 मीटरी टन चावल की एक मात्रा का निर्यात किया गया था। (बिहार को बीज प्रयोजन के लिए निर्यात की गयी 3,200 मीटरी टन धान को छोड़कर)

(ख) 71,739 मीटरी टन चावल की सारी मात्रा पश्चिमी बंगाल को भेजी गयी थी ।

(ग) चावल और धान की सारी मात्रा भारतीय खाद्य निगम द्वारा भेजी गयी थी ।

(घ) भारतीय खाद्य निगम ने चावल और धान की कोई मात्रा अधिप्राप्त नहीं की हैं। उड़ीसा सरकार ने 20-5-1967 तक 1,81,400 मीटरी टन चावल (अनुमानतः) अधिप्राप्त किया था ।

उड़ीसा में चावल वसूली का मूल्य

864. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 में भारतीय खाद्य निगम ने उड़ीसा में विभिन्न किस्म के चावल तथा धान को खरीदने का प्रति बोरा मूल्य क्या निर्धारित किया था;

(ख) उसने पश्चिम बंगाल को ये धान तथा चावल किस्म वार किस मूल्य पर दिये;

(ग) उड़ीसा सरकार ने चावल किस मूल्य पर खरीदे थे;

(घ) उड़ीसा सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को किस मूल्य पर चावल दिये;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार ने 1966-67 में खाद्यान्नों की वसूली के लिये उड़ीसा सरकार को कोई ऋण दिया था; और

(च) यदि हां, तो कितना धन दिया गया था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भारतीय खाद्य निगम ने उड़ीसा में चावल व धान का अधिप्राप्ति मूल्य निर्धारित नहीं किया है। राज्य सरकार ने चावल के मूल्य के सम्बन्ध में भारतीय खाद्य निगम से जो कहा है और जो केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है, वे इस प्रकार हैं:—

	31-3-67 तक	रुपये प्रति क्विंटल (1-4-67 से)
साधारण	75.52	78.52
बढ़िया	79.78	82.84
बहुत बढ़िया 2	84.65	87.71
बहुत बढ़िया 1	87.27	90.33
बहुत बढ़िया-1 (विशेष)	88.87	91.93

(ख) भारत सरकार के अनुदेशानुसार तथा उसके द्वारा निर्धारित निगम मूल्यों पर भारतीय खाद्य निगम पश्चिम बंगाल को चावल देता है। निगम मूल्य इस प्रकार हैं:—

	रुपये प्रति क्विंटल
मोटा (पश्चिमी बंगाल के लिए)	72.00
मध्यम दर्जे का	84.00
बढ़िया	94.00
बहुत बढ़िया–2	100.00
बहुत बढ़िया–1	110.00

(ग) से (च) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

केरल में धान की वसूली का भाव

865. **श्री अब्राहम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केरल में धान की वसूली के भाव को बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो किसानों को होने वाली हानि को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री [श्री अन्ना-साहिब शिन्दे] : (क) और (ख) राज्य सरकार से जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

त्रिवेन्द्रम और एरनाकुलम् हवाई अड्डे

866. **श्री एल्थोस** : **श्री मंगलाथुमाडोम** :

श्री अब्राहम : **श्री श्रीधरन** :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम तथा एरनाकुलम् के हवाई अड्डों के विस्तार का कोई प्रस्ताव है ताकि वहां पर बड़े विमान उतर सकें;

(ख) क्या पर्यटन विकास की अत्यधिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) त्रिवेन्द्रम के धावन–पथ को पहले ही 6000 फुट तक बढ़ा दिया गया है। जब धावन–पथ को सशक्त करने का कार्य जो इस समय चालू है और पूरा होने ही वाला है, समाप्त हो जायेगा तो यह धावन–पथ वाइकाउण्ट परिचालनों के लिए उपयुक्त हो जायेगा।

कोचीन हवाई अड्डे पर नागर विमानन विभाग का एक सिविल एनक्लेव है। कोचीन के लिए एरनाकुलम् के निकट एक अलग सिविल हवाई अड्डा बनाने के प्रश्न की जांच की जा रही है।

खाद्यान्नों के आयात पर व्यय

867. **श्री नीतिराजसिंह चौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्न का आयात प्रारम्भ करने की तारीख से लेकर अब तक विदेशों से खाद्यान्न ख़रीदने पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई है, और

(ख) खाद्यान्न की नियमित खरीद कब बन्द होने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) 1946 से 1966 के अन्त तक की अवधि में अन्य देशों से खरीदे गये खाद्यान्नों पर कुल 3326.09 करोड़ रुपये (लागत और भाड़ा) खर्च हुये थे।

(ख) यह भारत सरकार का घोषित उद्देश्य है कि हम 1971 तक खाद्यान्नों की दृष्टि से आत्म निर्भर हो जाएंगे। आशा तो यह है कि इसके बाद खाद्यान्नों का आयात करना आवश्यक नहीं होगा।

खाद्यान्नों का आयात

868. **श्री नीतिराजसिंह चौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966 के दौरान कितनी मात्रा में खाद्यान्नों का आयात किया गया तथा बंदरगाह पर उसका मूल्य कितना था;

(ख) इन खाद्यान्नों को बन्दरगाह से अनाज की दुकानों पर ले जाने पर बोरियों में भरने, गोदामों में रखने, भंडार भरने, बीमा रेल भाड़ा हरजाना ले जाने के व्यय सहित कुल कितना खर्च हुआ; और

(ग) लाने ले जाने तथा भंडार करने में कितना खाद्यान्न नष्ट हुआ तथा उसकी कीमत कितनी थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) 1966 में आयात किये गये खाद्यान्नों की कुल मात्रा 103.58 लाख मीटरी टन थी और उसका लागत तथा भाड़ा मूल्य 523.31 करोड़ रुपये है।

(ख) 1966 में 48.92 करोड़ रुपये खर्च हुये हैं।

(ग) मार्ग तथा संचयन में होने वाली हानि का अन्दाज़ा वित्तीय वर्ष न कि पंचांग वर्ष के आधार पर लगाया जाता है। हानि का इस प्रकार जो अन्दाजा लगाया जाता है वह न केवल वर्ष विशेष में आयात किये गये खाद्यान्नों के बारे में होता है बल्कि उन खाद्यान्नों जो कि पहले आयात किये गये होते हैं और केन्द्रीय संचयन गोदामों में रखे होते हैं, के बारे

में भी होता है । 1966–67 में मार्ग में हुई हानि अनुमानतः 18,213 मीटरी टन जिसका मूल्य 122.15 लाख रुपये और संचयन में हानि 3,210 मीटरी टन जिसका मूल्य 24.5 लाख रुपये है ।

कुमाली (केरल) में हवाई अड्डा

869. **श्री अब्राहम** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन केन्द्र टेक्काडी के महत्व को ध्यान में रखते हुए कुमाली (केरल) में एक हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) अब तक निरीक्षित कुछ स्थान अनुपयुक्त पाये गये हैं । निरीक्षण के लिए केरल सरकार से अन्य उपयुक्त स्थान सुझाने का अनुरोध किया गया है ।

कालीकट हवाई अड्डा

870. **श्री अब्राहम** :
श्री एस्थोस :
श्री श्रीधरन
श्री अ० क० गोपालन :
श्री चक्रपाणी :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री राममूर्ति :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि कालीकट (केरल) में एक हवाई अड्डा बनाने की मंजूरी दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(ग) उस निर्माण के लिये क्या कार्यवाही की गई है ।

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) :(क) और (ख) कालीकट में हवाई अड्डे के निर्माण के प्राक्कलनों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ग) यहां हवाई अड्डे के लिए स्थान का चुनाव किया जा चुका है तथा इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन यहां की यातायात संभावनाओं का अध्ययन प्रारम्भ कर रहा है । यहां हवाई अड्डा बनाया जाय या नहीं इस विषय में निर्णय अध्ययन के परिणाम उपलब्ध होने के उपरान्त किया जायेगा ।

एर्नाकुलम–टीकाय–पीरमाडे राष्ट्रीय राजपथ

871. **श्री अब्राहम** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एर्नाकुलम–टीकाय–पीरमाडे राष्ट्रीय राजपथ पर पंजार के स्थान पर बन्द किये गये निर्माण-कार्य को पुनः चालू करने की मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब आरम्भ किया जायेगा; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग) केरल राज्य में टीकायपीरमाडे को जोड़ने वाली सड़क राज्य सड़क है और वह राष्ट्रीय मुख्य मार्ग नहीं है। इस मामले में सूचना एकत्रित की जा रही है और समय पर सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

Jayanti Shipping Co.

872. Shri Mrityunjay Prasad : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) the value and type of shares held by Dr. Dharma Teja, Shrimati Dharama Teja and other near relatives of Dr. Dharma Teja in the Jayanti Shipping Co., Ltd.;

(b) the number of shares for which Dr. Dharma Teja and his relatives paid in cash and the value and types of shares which were given to them free in lieu of their Services;

(c) whether the permission of Government was taken for the promoters' shares given to Dr. Dharma Teja free of charge in lieu of his services; and

(d) the monthly salary and allowances paid to Dr. Dharma Teja and other free of cost facilities provided ?

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) The Jayanti Shipping Company shares are of only one type namely Equity Shares of the face value of Rs. 100 each. The value of these shares held in the names of Dr. Teja and his near relatives as ascertained from the records of the Company are as follows :—

	No. of Equity shares of Rs. 100 each	Total Face value of the shares
(1) Dr. J. D. Teja	212472	Rs. 2,12,47,200
(2) Mrs. Ranjit Teja	Nil	Nil
(3) Mr. G. Narayana (Nephew of Dr. Teja)	3	Rs. 300
(4) Mr. J. S. Rousseau (Brother of Dr. Teja)	1	Rs. 100

(b) The records of the Company available to the new management do not show that any shares were issued to Dr. Teja or his relatives in lieu of services rendered by them.

The question whether and the extent to which Dr. Teja and his relatives paid in cash or in kind for the shares issued to them is now under detailed investigation. This investigation has been undertaken because there is reason to doubt whether the requisite payment was made. However, this matter involves certain legal issues also. The result of the present investigation is likely to be known within about three months.

(c) In view of the reply to part (b) of the question, the question does not arise,

(d) No monthly salary, allowances or free of cost facilities in the nature of remuneration were allowed to Dr. Teja. The travelling and hotel bills etc. of Dr. Teja were, however paid by the Company from time to time and these bills are under scrutiny.

शिलांग–जवाई–बदरपुर सड़क

873. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शिलांग–जवाई–बदरपुर सड़क को राष्ट्रीय राजपथ घोषित करने का है;

(ख) इस सड़क के निर्माण पर अब तक कितना धन खर्च किया गया है तथा इसको पूरा करने के लिये कितना धन खर्च किया जायेगा; और

(ग) क्या यह सच है कि इस सड़क के विभिन्न प्रक्रमों पर आसाम के लोक निर्माण विभाग द्वारा खर्च किये गये धनराशि की मंजूरी अभी तक नहीं दी गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) शिलांग–जोवई–बदरपुर सड़क शिलांग–अगरताल सड़क का भाग है जो राज्य सड़क है और अंशतः त्रिपुरा में और अंशत: आसाम में है। समय समय पर इस सड़क को राष्ट्रींय मार्ग घोषित करने के प्रस्ताव किये गये हैं। इन प्रस्तावों को वित्तीय सीमाओं के कारण स्वीकार करना संभव नहीं हुआ है। किन्तु यातायात की जरूरतों की पूर्ति के लिये भारत सरकार आसाम में जोवई (पासी) से बदरपुर तक की सड़क में गायब टुकड़ों के विकास में सहायता कर रही है। इस काम में 2.22 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है। इसमें से 31 मार्च, 1966 तक 1.50 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं और 1966–67 के लिये 6 लाख रुपये आवंटित कर लिये गये हैं। 66 लाख रुपये के शेष से इस सड़क के काम के पूरे हो जाने की आशा हैं।

(ग) इस सड़क की विभिन्न मदों पर खर्च की गई राशि के बारे में राज्य सरकार ने इस मंत्रालय को कोई सूचना नहीं दी है। उन्होंने आसाम में शिलांग से चुराईवारी तक समस्त सड़क के अतिरिक्त सुधार का अनुमान भेजा है। इसकी स्वीकृति इस प्रश्न पर निर्भर करती है कि क्या अन्य राज्यों में भी ऐसे सुधार कार्य जरूरी समझे गये हैं और किफायत की मौजूदा जरूरतों में क्या ये रोके नहीं जा सकते। इस मामले की परीक्षा की जा रही है।

काश्मीर जाने वाले पर्यटकों के लिये सुविधायें

874. **श्रीमती ज्योत्सना चंदा :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष काश्मीर की यात्रा करने वाले पर्यटकों को क्या क्या विशेष सुविधायें दी जा रही हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : इस मौसम में काश्मीर की यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है:—

(क) कुद, बटोटे, बानिहाल, पहलगाम, श्रीनगर, गुलमर्ग और युसमर्ग में अतिरिक्त आवास व्यवस्था। इस प्रकार उपलब्ध आवास पिछले वर्ष की अपेक्षा तीस प्रतिशत अधिक होगा।

(ख) पठानकोट-श्रीनगर मार्ग पर परिवहन सुविधाएं लगभग दुगनी की जा रही हैं।

(ग) गुलमर्ग, वैष्णवदेवी, पाटनीटोप और सनासर में जल व्यवस्था को पर्याप्त रूप से बढ़ा दिया गया हैं।

(घ) यात्रियों के मनोरंजन की व्यवस्था के लिए डल झील स्थित चारचिनारी टापू का विकास किया जा चुका हैं। अब चारचिनारी में कैफेटीरिया, सूर्य-स्नान *(सनबेदिंग)*, 'तरंग-विहार' (सर्फ-राइडिंग) तैराकी और अन्य जल-क्रीड़ाएं जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी।

(ङ) इस वर्ष सितम्बर तक मौजूदा होटल-आवास व्यवस्था में सम्भवतः 150 कमरों की वृद्धि हो जायेगी।

(च) श्रीनगर में एक सर्व-ऋतु "स्कैटिंग रिंक" का निर्माण तुरन्त आरंभ किया जा रहा है।

उपर्युक्त-सुविधाएं, प्रत्येक वर्ष दिये जाने वाले अप्रैल से अक्टूबर तक की अवधि के लिए वैध "रेल तथा सड़क" के रियायती टिकटों, और बढ़े हुए यातायात को संभालने के लिए इण्डियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन द्वारा चलायी गयी अतिरिक्त अनुसूचित तथा अनुसूचित विमान सेवाओं की सामान्य सुविधाओं, के अलावा हैं।

दिल्ली परिवहन के जाली टिकटों की बिक्री

875. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जाली टिकट बेच कर दिल्ली परिवहन को कई लाख रुपये का धोखा दिया गया; और

(ख) क्या कोई गिरफ्तारी की गई है तथा क्या इस गिरोह का कोई सुराग मिला है, जो कई वर्षों से ऐसा कर रहा था ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० बी० के० आर० वी० राव) : *(क)* इस बारे में शिकायत मिली है किन्तु सी० बी० आई० द्वारा जांच किये जाने पर ऐसी सामग्री नहीं मिली जो आरोपों को पुष्ट करती।

(ख) *(क)* में दिये हुये उत्तर के कारण प्रश्न नहीं उठता।

डम-डम हवाई अड्डे से इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की उड़ानों की समय-सारिणी

876. **श्री स्वैल** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, 1967 में डमडम हवाई अड्डे पर खड़े इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के बहुत से विमानों में अत्यधिक मात्रा में यांत्रिक खराबी के कारण उड़ानों के समय में काफी गड़बड़ी हुई और बहुत से यात्रियों को असुविधा हुई;

(ख) क्या सरकार ने इन खराबियों के कारणों की जांच करवाई है; और

(ग) यदि हां, तो इस समस्या के समाधान के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) : अप्रेल, 1967 के दौरान कलकत्ता से होकर जाने वाली विमान सेवाओं पर निर्धारित समय पर की जाने वाली 589 रवानगियों के मुकाबले 30 मिनट या अधिक समय की यांत्रिक कारणों से होने वाली 29 देरियां हुई और इस प्रकार 95% विमान सेवाएं निर्धारित समय पर चलीं ।

(ख) : खराबियों की जांच की जा रही है ।

(ग) यांत्रिक खराबियो के कारणों की जांच सुस्थापित प्रक्रिया के अनुसार की जाती हैं और प्रत्येक मामले में जांच पूरी होने पर इस प्रकार की खराबियों को दूर करने या उनकी आवृत्ति को न्यूनतम करने के लिए उपयुक्त उपचारी कार्यवाही की जाती है ।

शिलांग के निकट हवाई अड्डा

877. **श्री स्वैल** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिलांग के निकट एक हवाई अड्डा बन कर तैयार हो गया है और भारतीय वायु सेना ने उस हवाई अड्डे पर अपने विमान सफलतापूर्वक उतारे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि गैर-सरकारी विमान कम्पनियां कलकत्ता और शिलांग के बीच विमान सेवा आरम्भ करने के लिये तैयार हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस हवाई अड्डे को प्रयोग में लाने तथा इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की विमान सेवा को शिलांग तक बढ़ाने का है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) : भारतीय वायु सेना ने 15. 7. 66 को आसाम सरकार से एक अच्छे मौसम में प्रयुक्त होने वाली हवाई पट्टी ले ली थी । इसका वायु सेना की आपातिक परिचालन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये विकास किया गया है ।

(ख) : अभी तक प्राइवेट परिचालक से, कलकत्ता और शिलांग के बीच विमान सेवाओं के परिचालन के लिये कोई निश्चित आवेदन पत्र नहीं प्राप्त हुआ ।

(ग) : इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की अपनी विमान सेवाओं को शिलांग तक बढ़ाने की कोई योजना नहीं, क्योंकि वहां कोई उपयुक्त हवाई अड्डा नहीं है ।

मिज़ो हिल ज़िले में विधान सभा के निर्वाचन

878. **श्री स्वैल** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिज़ो हिल ज़िले में विधान सभा के सभी निर्वाचन पूरे हो गये हैं;

(ख) ये निर्वाचन किन-किन तारीखों को हुए; और

(ग) इस निर्वाचन में कितने प्रतिशत मतदाताओं ने भाग लिया ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) उनमें से एक में कोई अभ्यर्थी न थे और अन्य दो में से हर एक में एक-एक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी था जो 21 जनवरी, 1967 को निर्वाचित घोषित कर दिया गया था। परिणामत:, विधान सभा निर्वाचनों के लिए इस ज़िले में कोई मतदान नहीं हुआ।

Assessment of Food Situation

879. **Shri S. C. Samanta :**
Shri A. K. Kisku :
Shri S. N. Maiti :
Shri Tridib Kumar Chadhuri :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have appointed any Committee to assess the food situation in the country this year; and

(b) if so, the main recommendations thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

अनाज का समाहार

880. **श्री राने :**
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री हीरजी भाई :
श्री ख० प्रधानी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966–67 की फसल में कितना अनाज विभिन्न राज्यों द्वारा अप्रैल, 1967 के अन्त तक वसूल किया गया और उसके राज्यवार आंकड़े क्या है;

(ख) वर्ष 1965–66 की तुलना में यह वसूली कितनी कम या अधिक थी; और

(ग) भारतीय खाद्य निगम ने राज्यों की सहायता से कितने अनाज की वसूली की ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) : एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 443/67]**

पंजाब से हिमाचल प्रदेश को वस्तुओं को निर्बाध ले जाया जाना

881. **श्री हेम राज** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने खाद्यान्नों के अतिरिक्त गुड़, चीनी, दालें, रूई और अन्य वस्तुओं को भी पंजाब से हिमाचल प्रदेश में निर्बाध रूप से ले जाने पर रोक लगा दी है और सीमा पर जांच के लिये चौकियां बिठा दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच इस प्रकार की रोकों को हटाने के लिये केन्द्रीय सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) पंजाब से हिमाचल प्रदेश को मुक्त संचलन पर लगाए गये प्रतिबन्धों के बारे में स्थिति इस प्रकार है:—

चावल : केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये उत्तरी अन्तर क्षेत्रीय चावल (संचलन नियन्त्रण) आदेश, 1967 के अधीन पंजाब राज्य से चावल के संचलन पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

गेहूं : केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अन्तर क्षेत्रीय गेहूं और गेहूं उत्पाद (सचलन नियन्त्रण) आदेश, 1967 जिसमें हाल में ही संशोधन किया गया है, के अधीन पंजाब से गेहूं के संचलन पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

मक्का : केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए उत्तरी अन्तर क्षेत्रीय मक्का (संचलन नियन्त्रण) आदेश, 1967 के अधीन पंजाब से मक्का के संचलन पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

ज्वार और बाजरा : पंजाब सरकार ने अपने पंजाब कोर्स अनाज (निर्यात नियंत्रण) आदेश, 1966 शीर्षक के आदेश के अधीन ज्वार और बाजरे के संचलन पर प्रतिबन्ध लगा दिए हैं।

गुड़ : कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

चीनी : केन्द्रीय सरकार ने चीनी के अन्तर्राज्यीय संचलन पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।

दालें : चने की दाल को छोड़कर दालों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। चने की दाल का संचलन उत्तरी अन्तर क्षेत्रीय चना (संचलन नियन्त्रण) आदेश, 1967 के अधीन नियन्त्रित है।

कपास : पंजाब सरकार ने कपास के संचलन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया है।

(ख) पंजाब सरकार द्वारा अपनी सीमाओं पर स्थापित की गयी जांच चौकियां उन वस्तुओं के संचलन को विनियमित करने के लिए बनाई गयी है जिनके लिए निर्यात परमिट लेने की आवश्यकता होती है।

हिमाचल प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों की पंजाब में कृषि भूमि

882. **श्री हेम राज** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश के रहने वाले भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों को उनकी युद्ध सेवाओं के लिए पंजाब में कृषि योग्य भूमि मिली है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन भूमि स्वामियों को अपनी उपज कांगड़े जिले में अपने स्थायी निवास स्थानों में ले जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है जिससे उनमें असन्तोष पैदा हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें अपने निजी उपयोग के लिए अपनी उपज पंजाब से कांगड़ा ले जाने की अनुमति देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) से (ग) : सम्बन्धित राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा खरीदा गया गेहूं तथा चावल

883. **श्री हेमराज** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय स्टाक के लिये विभिन्न राज्यों में कितना गेहूं तथा चावल खरीदा, और

(ख) विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने अपने स्टाक जमा करने के लिये कितना कितना गेहूं तथा चावल खरीदा है अथवा वसूली में इकट्ठा किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : 1966–67 के फसल वर्ष में अब तक (क) केन्द्रीय स्टाक और (ख) राज्य सरकारों के अपने सुरक्षित स्टाक के लिए अधिप्राप्त किये गये गेहूं, चावल, और धान की मात्रा बताने वाला एक विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०** 4^4/67]

रासायनिक खाद

884. **श्री याज्ञिक** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अनेक पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने कृषि भूमि पर रासायनिक खादों के, जिनको भारत में बड़े पैमाने पर बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है, प्रयोग से होने वाले घातक परिणामों के बारे में बताया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) भारत सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। फिर भी यह बात सभी देशों में वैज्ञानिक रूप से स्पष्ट है कि यदि उर्वरकों को उपयुक्त रूप से प्रयोग में लाया जाए तो उनसे उपज को भारी लाभ होता है।

खाद्यान्नों का आयात

885. **श्री याज्ञिक :**
श्री रामचरण :
श्री रा० कृ० बिड़ला :
श्री देवकी नन्दन पटोदिया :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री दामानी :
श्री कृष्णमूर्ति :
डा० रानेन सेन :
श्री ज्योतिमय बसु :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सं० चं० सामन्त :
श्री रा० बरूआ :
श्री रामचन्द्र उलका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री हीरजी भाई :
श्री ख० प्रधानी :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री क० लकप्पा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1971 तक अनाज में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकार ने आगामी कुछ वर्षों में खाद्यान्नों का आयात उत्तरोत्तर घटाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो आगामी कुछ वर्षों के लिए आयात घटाने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ग) क्या सरकार 1971 के बाद भी सामान्य व्यापार के रूप में कुछ देशों से थोड़ी मात्रा में खाद्यान्नों का आयात करती रहेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) यह मानते हुये कि मानसून सामान्य रहेगी और चौथी पंचवर्षीय योजना में खाद्य उत्पादन सम्बन्धी निर्धारित लक्ष्य पूरे हो जाएंगे, 1968 से 1971 के वर्षों में निम्नलिखित मात्रा में खाद्यान्न आयात करने की आवश्यकता पड़ेगी :—

(लाख मीटरी टन)

वर्ष	अपेक्षित आयात		
	चालू खपत के लिये	बफर स्टाक तैयार करने के लिये	जोड़
1968	70	10	80
1969	50	10	60
1970	20	10	30
1971		10	10

(ग) यह संगत समय पर सम्बन्धित देशों के साथ व्यापार प्रबन्धों के तरीके पर निर्भर करेगा।

कार्बनिक खाद

886. **श्री याज्ञिक** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मनुष्यों और पशुओं के मल, मूत्र और गोबर तथा बेकार फेंकी जाने वाली घास पत्तियों आदि से बनी हुई कम्पोस्ट खाद तथा कार्बनिक खाद की महान उपयोगिता का पता है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने कोई ऐसा कार्यक्रम तैयार किया है, जिसके अन्तर्गत देहातों में इस समय बेकार जाने वाली कार्बनिक खाद को इकट्ठा करके उसका उपयोग किया जा सके; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने पहले ही देहातों में कूड़ा करकट की खाद उत्पादन के लिए स्थानीय खाद साधनों के विकास तथा उपयोगिता के लिए योजनाएं चलाई हुई हैं जो सभी राज्यों संघ क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही हैं।

ये योजनाएं दूसरी पंचवर्षीय योजना से धीरे-धीरे उन्नति कर रही हैं। दूसरी योजना (1960–61) के अन्त में कूड़ा करकट की खाद का उत्पादन 66.00 मिलियन टन था, तीसरी योजना के अन्त तक 119.58 मिलियन टोन्ज था। चौथी योजना के दौरान 1970–71 के अन्त तक कूड़ा करकट की खाद उत्पादन का लक्ष्य 165.90 मिलियन टोन्ज रखा गया है। पूर्वानुमानित प्राप्ति 1966–67 वर्ष के लिए 133.42 मिलियन टोन्ज है और 1967–68 वर्ष के लिए 141.88 मिलियन टोन्ज है।

कुमारकोम का एक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

887. **श्री अब्राहम** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुमारकोम, कोट्टयम से कोई ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें कुमारकोम का एक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास करने के लिये प्रार्थना की गई हो; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) कुमारकाम का एक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास करने के लिए एक सुझाव प्राप्त हुआ है।

(ख) सीमित साधनों की स्थिति को दृष्टि में रखते हुए पेरियार वन्य पशु शरण स्थान, वेकोम में और कोट्टयम में पर्यटक सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। इसलिए कुमारकोम का, जो पेरियार से 50 मील और कोट्टयम से 7 मील की दूरी पर है विकास करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कलकत्ता पत्तन शुल्कों में वृद्धि

888. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता पत्तन शुल्कों में हाल में की गयी वृद्धि का प्रभाव निर्यातों की अपेक्षा आयातों पर काफी अधिक पड़ेगा; और

(ख) यदि हाँ, तो इससे देश में निर्माण लागत तथा वस्तुओं के मूल्यों में कितनी वृद्धि होने की संभावना है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) : अभी हाल ही में सामानों पर कलकत्ता पत्तन प्रभार में जो वृद्धि की गई है केवल आयात पर ही की गई है और ऐसा करने में पोर्ट कमिश्नरों ने उनके द्वारा की गई सेवाओं की लागत का और यातायात के विभिन्न मद कितना वहन कर सकते हैं इसका ध्यान रखा है। पत्तन प्रभार उन कई तत्वों में से केवल एक है जो उत्पादन लागत या विभिन्न माल के बिक्री मूल्य पर प्रभाव डालते हैं। अधिकांश माल की लागत संरचना में वह विशेष महत्व का नहीं होता है। जहां तक खाद्यान्न, नमक और पेट्रोलियम का सम्बन्ध है इन पर पत्तन प्रभार में वृद्धि क्रमशः 2.07 रु० 1.50 रु० और 3.55 रु० प्रति टन आती है।

राज्यों में चावल के मूल्य

889. **श्री राने** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास को छोड़ कर अन्य राज्यों में उचित मूल्य वाली दुकानों पर चावल के मूल्य क्या हैं; और

(ख) वह मूल्य मद्रास में एक रूपया प्रति तोल चावल के मूल्य की तुलना में कितना कम व अधिक है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०** 445/67]

(ख) जम्मू और कश्मीर को छोड़ कर, जबकि वहां वे अपेक्षाकृत कम हैं, ये सभी मूल्य अपेक्षाकृत ऊंचे हैं।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल का समाहार

890. **श्री को० सूर्यनारायण** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम ने विभिन्न राज्यों से कितनी मात्रा में तथा किस किस किस्म के चावल का समाहारक किया है; और

(ख) विभिन्न किस्मों के चावल के क्या क्या दाम विक्रेताओं को दिये गये तथा उपभोक्ताओं के लिए क्या क्या दाम निर्धारित किये गये ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) 1–11–1966 से 30–4–1967 तक लगभग 9.2 लाख मीटरी टन।

(ख) निगम ने विभिन्न राज्यों में विभिन्न किस्मों के चावल जिस भाव पर खरीदे हैं, वे संलग्न विवरण में दिये गये हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०** 446/67] निगम परचून में उपभोक्ताओं को चावल नहीं बेचता है। चावल के परचून भाव सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किये जाते हैं और ये भाव आन्तरिक खरीदारी सहित सभी स्रोतों से प्राप्त चावल की लागत पर आधारित होते हैं। भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदे गये विभिन्न किस्मों के चावल के अलग से खुदरा भाव बताना कठिन है।

जिस भूमि पर खेती नहीं होती उसे कृषि योग्य बनाने के लिए अनुदान

891. **श्री रणधीर सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में खाद्य उत्पादन को बढ़ाने तथा किसानों को विशेष प्रोत्साहन देने के लिए उनको ऐसी भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए जिस पर कृषि नहीं होती, प्रति एकड़ विशेष अनुदान देने के सम्बन्ध में इंगलैंड में बने कानून के ढंग पर कोई कृषि अधिनियम बनाने का है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि हां, तो किस तिथि से ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) ब्रिटेन में बने कानून के ढंग का अधिनियम, जिसके अधीन किसानों को कृषि के अयोग्य भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये अनुदान देने की व्यवस्था होती है, बनाने के प्रश्न पर अभी विचार नहीं किया गया है। फिर भी केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें मुख्यतः भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को बसाने के लिए बेकार भूमि को खेती योग्य बनाने के लिये सहायता दे रही है। इस योजना के अधीन अधिक से अधिक 300 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सहायता दी गई है जिसमें केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों का आधा-आधा भाग है। इसके अतिरिक्त भूमि को सीढ़ीनुमा खेतों में बदलने तथा उसे कृषि योग्य बनाने के लिये राज्य सरकारें सहायता देती हैं जिसका 25 से 50 प्रतिशत राज सहायता के रूप में दिया जाता है तथा शेष को कई वर्षों में आसान किस्तों में वसूल किया जाता है। भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये किसानों को कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा भी सहायता दी जाती है। लगभग 13 लाख एकड़ भूमि के विकास के लिए योजनाएं बनाई गई हैं जिनके लिये 30 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। चौथी योजना में कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा घोषित योजनाओं के अतिरिक्त 25 लाख एकड़ भूमि को कृषि योग्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

बूचड़खाना

892. **श्री रणबीर सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली राज्य की सीमा के निकट जी० टी० रोड पर 17वें मील पर जनता केन्द्रीय सरकार की वित्तीय सहायता से तथा उसके संरक्षण में एसैक्स फार्म्स (प्राइवेट) लिमिटेड के नाम से एक बूचड़खाना बनाया जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्थानीय ग्राम पंचायतों, खण्ड समिति, जिला परिषद् और सब-डिवीजन प्रशासन ने इस बूचड़खाने के बनाये जाने का विरोध किया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सभी राजनीतिक दलों तथा सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं ने इसका इस आधार पर कड़ा विरोध किया है कि इससे स्थानीय जनता की भावना को चोट पहुंचती है; और

(घ) यदि हां, तो इस बूचड़खाने के बनाये जाने के निर्णय को रद्द करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) से (घ) : भारत सरकार की ओर से इस परियोजना को वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस बारे में दिल्ली प्रशासन व दिल्ली नगर निगम से पूछताछ की गई थी जिन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हरियाणा सरकार से जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय पार्क

893. **श्री स्वैल** :

श्री वेदव्रत बरुआ :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं, उनके नाम क्या हैं तथा वे कहां कहां पर हैं;

(ख) सरकार द्वारा किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय पार्क घोषित करने तथा उसको सहायता देने की क्या कसौटियां हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि विश्व विख्यात तथा दुर्लभ एक सींग वाले गैंडे के निवास स्थान काजीरंगा को अभी तक राष्ट्रीय पार्क घोषित नहीं किया गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) देश में 3 राष्ट्रीय पार्क हैं जिनके नाम निम्नलिखित हैं :—

1. कारबेट नेशनल पार्क, उत्तर प्रदेश
2. कान्हा नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश
3. शिवपुरी नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश

(ख) राष्ट्रीय पार्क की परिभाषा निम्न प्रकार है :—

"जो विधान सभा द्वारा बनाए गए नियम से वन्य प्राणियों की रक्षा के लिए और राष्ट्रीय महत्व के सौन्दर्य व प्राकृतिक ऐतिहासिक वस्तुओं के लिए भावी पीढ़ियों को अनूठा मनोरंजन व आनन्द प्रदान करने के लिए स्थानीय वातावरण को दृष्टि में रखते हुए खोला गया हो ।"

वन्य प्राणी राज्य सरकारों का विषय है और राष्ट्रीय पार्क बनाने के लिये संबंधित राज्य सरकारों की विधान सभायें ही कानून बनाती हैं ।

स्टेट सैक्टर में राष्ट्रीय पार्कों का समावेश 'प्रकृति संरक्षण' योजना के अन्तर्गत हो सकता है और चौथी योजना में समस्त स्टेट योजनाओं की सहायता का प्रतिमान 30 प्रतिशत ऋण तथा 20 प्रतिशत अनुदान है ।

(ग) अभी तक काज़ीरंगा को राष्ट्रीय पार्क घोषित नहीं किया गया है ।

ग्वालियर में हवाई अड्डा

894. **श्री आत्म दास :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में ग्वालियर में एक असैनिक हवाई अड्डा बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसका निर्माण कब तक हो जायेगा ।

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : ग्वालियर में एक सिविल हवाई अड्डा बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

लेबनान से प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता से दिल्ली राज्य के गांवों का विकास

895. **श्री आत्म दास :**

श्री मोहन स्वरूप :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लेबनान सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता से दिल्ली राज्य के तीन गांवों का विकास करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो यह विकास किस प्रकार किया जायेगा;

(ग) क्या मध्य प्रदेश में गांवों के विकास के लिए अन्य देशों से इस प्रकार की सहायता मिली है; और

(घ) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी, नहीं। दिल्ली राज्य के तीन गांवों के विकास के लिए लेबनान सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दिये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, लेबनान के राष्ट्रपति के संरक्षण में "इंडिया डे कैम्पेन" के नाम से एक राष्ट्रीय समिति गठित की गई थी और उसने 4 लाख रुपये की राशि एकत्र की है। इस अभियान का उद्देश्य लेबनान और भारत के लोगों के बीच मित्रता एवं एकता के भाव का प्रदर्शन करना था। इस अभियान के आयोजकों की यह इच्छा थी कि इस धन को दिल्ली के समीप किसी एक गांव या कुछ गांवों के विकास तथा राहत-कार्यों पर खर्च करके उपयोग में लाया जाये। भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को सिद्धान्त रूप में मान लिया है तथा विकास और राहत परियोजना के ब्यौरे को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) प्रस्तावित विकास का ब्यौरा अभी विचाराधीन है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

डकोटा विमान सेवा से इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को हुई हानि

896. श्री गिरिराज शरण सिंह :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री मीठा लाल :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डकोटा विमान चलाने से इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को प्रति यात्री प्रति मील कितनी हानि उठानी पड़ी है?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : डकोटा विमान चलाने से इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को 1965-66 के दौरान प्रति-यात्री प्रति-मील 35 पैसे की हानि हुई।

एवरो जेट विमान

897. श्री गिरिराज शरण सिंह :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री मीठा लाल :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने डकोटा विमानों के स्थान पर चलाने के लिए एवरो जेट विमान खरीदने का आदेश सर्वप्रथम कब दिया था;

(ख) कितने एवरो जेट विमान खरीदने के आदेश दिये गये हैं और वे विमान कितने मूल्य पर खरीदे जायेंगे; और

(ग) ये विमान कब प्राप्त हो जायेंगे?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) विमानों की खरीद का अभिप्राय सूचना पत्र (लेटर ऑफ इटेंट) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, कानपुर को 5 अक्टूबर, 1965 को जारी किया गया था।

(ख) नौ एवरो. 748 (एच. एस. 748) सीरीज II विमान खरीदने के आदेश दिये जा चुके हैं। प्रत्येक विमान का मूल्य 82·53 लाख रुपये है।

(ग) इन विमानों की डिलीवरी निम्न प्रकार मिलेगी :—

विमानों की संख्या	डिलीवरी मिलने का महीना
1	मई, 1967
1	दिसम्बर, 1967
1	फरवरी, 1968
1	मई, 1968
1	जुलाई, 1968
1	सितम्बर, 1968
1	दिसम्बर, 1968
1	फरवरी, 1969
1	मार्च, 1969

भारत में खाद्य उत्पादन

898. श्री बलराज मधोक :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में ऐसे व्यक्ति कितने प्रतिशत हैं जो प्रति वर्ष भारत में उगाया गया अनाज खाते हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : भारत में ऐसे व्यक्ति कितने प्रतिशत हैं जो प्रति वर्ष देश में उगाया गया अनाज खाते हैं। इस सम्बन्ध में जानकारी देना सम्भव नहीं है क्योंकि सरकारी वितरण में उपभोक्ताओं को बेचने के लिए देशी तथा आयातित अनाजों को एक जगह एकत्रित किया जाता है। चावल, गेहूँ के अलावा अन्य मोटे अनाज तथा दालें भी होती हैं और जो लोग सरकारी वितरण द्वारा आयातित अनाज लेते हैं वे भी देशी अनाज खाते हैं।

सिलचर-मनीपुर सड़क

899. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिलचर—मनीपुर सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो यह कब तक पूरा होगा ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) आसाम और मणिपुर के बीच सीमान्त पर सिलचर से जीरी नदी तक एक सड़क पहिले ही है। संभवत: माननीय सदस्य का संकेत मणिपुर राज्य में निर्माणाधीन नई कचार सड़क (जीरी–इंफल) के भाग से है। इस सड़क का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है।

(ख) इस सड़क के 1970 तक पूर्ण हो जाने की आशा है।

भूमिहीन कृषि श्रमिकों को बसाना

900. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमिहीन कृषि श्रमिकों को बसाने के लिए राज्यों की सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त योजनाओं की क्रियान्विति में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) राज्यवार इसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भूमिहीन कृषि श्रमिकों को बसाने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत अब तक 96,527 परिवारों को बसाया जा चुका है।

(ख) उपरोक्त योजना के अन्तर्गत परिवारों का राज्यवार ब्यौरा निम्न प्रकार है :

क्रम संख्या	राज्य	बसाये गये परिवारों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	3,352
2.	आसाम	30
3.	बिहार	14,775
4.	गुजरात	5,342
5.	मद्रास	927
6.	मध्य प्रदेश	7,959
7.	मैसूर	100
8.	उड़ीसा	360
9.	केरल	4,000
10.	पंजाब	41,526
11.	महाराष्ट्र	16,124
12.	उत्तर प्रदेश	936
13.	त्रिपुरा	1,096
	कुल	96,527

बिहार के लिये खाद्यान्न का कोटा

901. **श्री देवेन सेन** :
श्री मधु लिमये :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र ने मार्च, अप्रैल और मई, 1967 के महीनों के लिये बिहार को खाद्यान्न का कितना कोटा देने का वायदा किया था ;

(ख) राज्य को वस्तुतः कितना कोटा दिया गया ;

(ग) उक्त महीनों में दिये गये खाद्यान्नों में माइलो और गेहूँ का क्या अनुपात था ;

(घ) अन्य राज्यों को दिये गये खाद्यान्न के कोटे में माइलो और गेहूँ का क्या अनुपात था ।

(ङ) बिहार को खाद्यान्न का जितना कोटा देने का वायदा किया गया था उससे कम कोटा देने का क्या कारण है; और

(च) माइलो और गेहूँ के अनुपात के मामले में बिहार के साथ भेदभाव करने का क्या कारण है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्बे) : (क) बिहार को किए गए आवंटन इस प्रकार हैं :—

मार्च	178,000 मीटरी टन
अप्रैल	197,000 ,,
मई	225,000 ,,

(ख) भेजी मात्राएं इस प्रकार हैं—

मार्च	172,000 मीटरी टन	
अप्रैल	196,600 ,,	
मई	180,400 ,,	(20–5–67 तक)

(ग) इन महीनों के दौरान भेजी गयी कुल मात्रा में आधा गेहूँ और आधी माइलो थी ।

(घ) अन्य राज्यों के मामले में माइलो का अनुपात ५२ प्रतिशत से ० प्रतिशत के बीच था ।

(ङ) यह कमी नाम मात्र थी और यह जहाज के देर से आने, बन्दरगाहों पर हड़ताल, वैगनों के न मिलने आदि जैसे कई कारणों के कारण हुई थी।

(च) किसी भी राज्य के मामले में कोई भेद-भाव नहीं किया गया था । राज्य के कोटे में गेहूँ और माइलो के अनुपात का निर्धारण इन दोनों प्रकार के अनाजों की उपलब्धि और कमी से प्रभावित क्षेत्रों में सस्ते अनाजों के सुलभ करने की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है ।

राजपथ विकास कार्यक्रम

902. **श्री देवेन सेन** :

श्री मधु लिमये :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिये राजपथ विकास कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं। राष्ट्रीय मुख्य मार्गों तथा अन्य केन्द्रीय सहायित सड़क परियोजनाओं के बारे में चतुर्थ योजना अवधि में मुख्य मार्ग विकास कार्यक्रम को अन्तिम रूप देना संभव नहीं हो सका है क्योंकि स्वयं योजना ही अभी विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पटसन उत्पादन का लक्ष्य

903 **श्री फ० गो० सेन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967–68 में पटसन के उत्पादन का क्या लक्ष्य है ;

(ख) इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं; और

(ग) क्या पटसन का उत्पादन बढ़ाने के लिए मूल्य में प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 94·00 लाख गांठें–जूट व मेस्ता दोनों।

(ख) उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं :—

(1) पश्चिम बंगाल में गहरे नलकूपों के क्षेत्रों व कोसी व हीराकुंड परियोजनाओं के नये सिंचित क्षेत्रों के और बड़े क्षेत्र में जूट की खेती की बुवाई शुरू करना ;

(2) सिंचित क्षेत्रों में धान व आलू के साथ हेर-फेर से दूसरी खेती के रूप में जूट की खेती को प्रोत्साहन देना;

(3) वर्त्तमान रेशे के स्थान पर अधिक उत्पादन वाली व खाद से अच्छी तरह से फलने-फूलने वाली किस्मों को शुरू करना; और

(4) खेती की उन्नत विधियों को शुरू करना जिनमें यूरिया का फ़ोलियर स्प्रे करना; लाइन में बुवाई करना, कीटों, रोगों व घास पात पर नियन्त्रण करना भी शामिल है।

(ग) कलकत्ता में डिलिवर की गई आसाम बाटम किस्म का न्यूनतम सहाय्य मूल्य जो 1966–67 में 35 रुपये प्रति मन था वह 1967–68 में बढ़ाकर 40 रुपये प्रति मन कर दिया गया है ताकि जूट के कृषकों को उपयुक्त लाभ मिल सके।

कलकत्ता बन्दरगाह में जहाजी कर्मचारियों की हड़ताल

904. **श्री फ० गो० सेन** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जहाजी कर्मचारियों द्वारा अचानक हड़ताल कर दिये जाने के कारण 5 अप्रैल, 1967 को कलकत्ता बन्दरगाह में जहाजों का आना-जाना रुक गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) कलकत्ता पत्तन में मुख्य यांत्रिक इंजीनियर के अधीन क्रेन पोतों के कर्मीदल ने 30 मार्च, 1967 को हड़ताल करदी थी। यह हड़ताल इसके एक दिन पूर्व एक फ्लोटिंग क्रेन के कार्यभारी इंजीनियर पर कर्मीदल के एक सदस्य द्वारा कथित आक्रमण करने पर उसके निलंबित किये जाने पर हुई। पत्तन के पोतों के समस्त कर्मीदल ने 4 अप्रैल, 1967 से सहानुभूतिक हड़ताल कर दी। इसके परिणामस्वरूप 4 अप्रैल, 1967 से 7 अप्रैल, 1967 तक विभिन्न सीमाओं तक पोतों का आवागमन रुक गया।

(ग) 7 अप्रैल, 1967 को क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के सम्मुख कलकत्ता पोर्ट कमिश्नरों और सम्बद्ध संघ द्वारा समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जाने के परिणामस्वरूप हड़ताल वापस ले ली गई। इस समझौते की शर्तों के अनुसार क्रेन ड्राईवर के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच के लिये नियुक्त जांच अधिकारी ने निलबित आदेश की औचित्यता की पहले प्रारम्भिक जांच की। उन्होंने अपना निष्कर्ष दिया है कि निलंबित आदेश अनुचित न था। वे अपनी अन्तिम रिपोर्ट शीघ्र ही देंगे।

FOOD POLICY

905. **Shri P. L. Barupal : Will the** Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the action being taken by the Union Government in regard to the slackness on the part of States in implementing the food policy;

(b) the names of the States which are not following the Central Food Policy;

(c) whether it is a fact that there is a great disparity between the prices of foodgrains in Haryana, Punjab and Rajasthan; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde):(a) and (b) : The food policy in its various aspects is evolved in consultation with the State Chief Ministers and a review of this policy is also made from time to time. The State Governments are trying to implement the policies to the best of their abilities in the context of the conditions in the respective States.

(c) and (d) : There is some disparity in the market prices of various food-grains in the States of Haryana, Punjab and Rajasthan which is unavoidable due to factors like production and supply, purchasing power of the people, consumer preference for different grains in different States etc.

CENTRAL AGRICULTURAL FARM IN RAJASTHAN

906. Shri P. L. Barupal : Will the Minister of **Food and Argriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Agricultural Farm in Rajasthan managed by the Government is running at a loss since long; and

(b) if so, the years in which profits were made and the years in which loss was incurred since the establishment of this farm ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b) : It is only in 1965-66 that the Suartgrah Farm has shown both net loss as well as gross loss. In 1958-59 and 1960-61, the Farm showed both a net profit as well as a gross profit In the remaining years, the farm showed a net loss and a gross profit.

CAMEL FARM AT BIKANER (RAJASTHAN)

907. Shri P. L. Barupal : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether any camel farm has been started at Bikaner (Rajasthan) for conducting research in improving camel breed; and

(b) if so, when this farm was started, the expenditure incurred on it and the amount provided by the Central and the State Governments separately ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes, A scheme for development of camel in Rajasthan had been approved by the Indian Council of Agricultural Research.

(b) Started on 1. 9. 1959.

Total amount sanctioned for the scheme for six years from 1. 9. 1959 to 31. 8. 1965.

Share of State Government..................Rs. 7,02,920/-

Share of I. C. A. R..........................Rs. 4,15,830/-

Scheme terminated thereafter.

Rs. 2,32,800/- has been remitted to the State Government towards the share of Indian Council of Agricultural Research.

FOREIGN TOURISTS

908. Shri P. L. Barupal : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the number of tourists who came to India from abroad from Ist January 1964 to 30th March 1967; and

(b) the foreign exchange earned from these tourists ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) The number of foreign tourists to India during the period Ist January 1964 to 30th March 1967 was as follows :

PERIOD		NUMBER OF TOURISTS
January — December 1964	..	156,673
January — December 1965	..	147,900
January — December 1966	..	159,603
January — March 1967	..	40,800 (Provisional)
	Total	504,976

(b) the provisional estimates of foreign exchange earning due to tourism for the above period were :—

PERIOD		EARNING (Rs. in crores)
January — December 1964	..	23.00
January — December 1965	..	21.59
January — December 1966 / January — March 1967	..	Not available

केन्द्रीय देशान्तर्गत जल परिवहन निगम

909. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा
श्री य० अ० प्रसाद
श्री हेम बरुआ
डा० रानेन सेन
श्री नाथ पाई
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिवर स्टीम नैवीगेशन कम्पनी लिमिटेड की आस्तियों को अपने नियन्त्रण में लेने के लिये केन्द्रीय देशांतर्गत जल परिवहन निगम की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस निगम की अधिकृत पूंजी कितनी है और नियन्त्रण में ली जा रही रिवर स्टीम नैवीगेशन कम्पनी लिमिटेड के दायित्व और आस्तियां कितनी कितनी हैं; और

(ग) निगम के कितने कर्मचारी हैं और नियन्त्रण में ली जा रही रिवर स्टीम नैवीगेशन कम्पनी लिमिटेड के कितने कर्मचारी हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव०) (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम की अधिकृत पूंजी 4 करोड़ रुपये हैं जो 1000 रु० के 40,000 शेयरों में है । रिवर स्टीम नेविगेशन कम्पनी की देयताएं जो हम अपने ऊपर लेने की आशा करते हैं 7.72 करोड़ रुपये होगी जिसमें 31-3-1967 तक का ब्याज भी शामिल है और परिसंपति जिसे हम अपने हाथ में लेने की आशा करते हैं 4 करोड़ रुपये होगी ।

(ग) रिवर स्टीम नेविगेशन कम्पनी के कुल 7500 कर्मचारियों में से संभवत: 5000 कर्मचारी केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन ले लेगा ।

आंध्र प्रदेश में प्रयोगात्मक नलकूप संगठन

910. श्री मि० सू० मूर्ति : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में प्रयोगात्मक नलकूप संगठन ने कुछ नलकूप लगाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने नलकूप लगाये गये हैं तथा कितने नलकूप सफल साबित हुए ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : (क) तथा (ख) : आंध्र प्रदेश में भूमिगत जल की खोज के दौरान प्रयोगात्मक नलकूप संगठन ने 15 प्रयोगात्मक बोर खोदे जिसमें से 11 सफल सिद्ध हुए।

बड़ौदा के लिए हवाई सेवा

911. श्री मणिभाई जे० पटेल : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ौदा के लिए विमान सेवा की उड़ानें रोक दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन सेवाओं को कब तक पुनः चालू किया जायेगा;

(ग) क्या बड़ौदा की हवाई पट्टी विमान उतरने के लिए ठीक नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है।

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) : बड़ौदा की हवाई पट्टी विमान परिचालनों के लिए अनुपयोगी हो गयी है। धावन-पथ को सुधारने के प्राक्कलन मंजूर हो गये हैं और यह सुधार का काम इस महीने दे दिया गया है। इस कार्य के लगभग 18 महीने में पूरा हो जाने की आशा है। सुधार—कार्य पूरा होते ही बड़ौदा से होकर विमान सेवाओं के पुनः चालू करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

गन्ने की खेती वाली भूमि का क्षेत्रफल

912. श्री नीतीराजसिंह चौधरी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965–66, 1966–67 और 1967–68 में प्रत्येक राज्य में कितनी भूमि में गन्ने की खेती की गई ;

(ख) 1965–66 और 1966–67 में प्रत्येक राज्य में गन्ने का कितना उत्पादन हुआ; और

(ग) 1967-68 में राज्यवार कितनी चीनी तैयार होने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) (क) और (ख) : 1965-66 और 1966-67 की अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है। 1967-68 में गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्र के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं है :—

राज्य	गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्र (हजार एकड़)		चीनी का कुल उत्पादन (हजार मीट्रिक टन)	
	1965-66	1966-67 (दूसरा अनुमान)	1965-66	1966-67 (15-5-67 तक)
उत्तर प्रदेश	3660	3059	1370	714
बिहार	420	368	371	210
पंजाब	887	887	159	85
असम	74	75	9	6
पश्चिमी बंगाल	97	81	13	8
उड़ीसा	115	129	11	9
मध्य प्रदेश	169	155	36	7
राजस्थान	140	119	18	8
महाराष्ट्र	387	370	764	620
गुजरात	87	78	55	40
आंध्र प्रदेश	295	211	294	146
मद्रास	213	224	228	159
मैसूर	190	183	145	78
केरल	23	21	23	8
पांडिचेरी	5	उपलब्ध नहीं	12	7

(ग) यह बताना अभी मुश्किल है कि 1967-68 में चीनी का कितना अनुमानित उत्पादन होगा।

बिहार तथा उत्तर प्रदेश के अकालग्रस्त क्षेत्र के लिए सहायता

913. **श्री पार्थासार्थी**
श्री आर० डी० रेड्डी

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार और उत्तर प्रदेश के अकालग्रस्त क्षेत्रों के लिए कितने देशों ने सहानुभूति दर्शाई और सहायता भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो विदेशों से कुल कितने रुपये की सहायता मिली है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) भारत सरकार को वर्ष 1966-67 के सूखे से उत्पन्न खाद्य कमी से राहत पहुंचाने के लिए विदेशों से, विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों। गैर सरकारी ऐजेंसियों से प्राप्त उपहार। सहायता उनका रुपयों में मूल्य सहित, बताने वाला एक विवरण संलग्न है। प्राप्त सहायता देश के कमी से प्रभावित क्षेत्रों की सहायता के लिए है जिनमें बिहार और उत्तर प्रदेश के इलाके भी शामिल हैं। [पुस्तकालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 447/67]

पटना और मधुवन तथा पटना और सहरसा के बीच हवाई सेवा

914. श्री शिव चन्द्र झा : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना-मधुबन और पटना-सहरसा के बीच कोई नियमित हवाई सेवा नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) (क) और (ख) : मधुबन में केवल अच्छे मौसम के लिये एक 1500 फुट लम्बी हवाई पट्टी है, और सहरसा में एक 2400 फुट लम्बी पी० एस० पी० (चिरी हुई फौलाद की चादरों की) हवाई पट्टी है। ये दोनों ही नियमित हवाई सेवाओं के परिचालन के लिये, चाहे वे डकोटा विमानों द्वारा ही हों, उपयुक्त नहीं।

WHEAT DONATION FROM U. S. S. R.

915. Shri Ramavtar Shastri : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the U. S. S. R. Government has supplied two lakh tonnes of wheat for free distribution amongst the famine-stricken people of Bihar and Eastern Uttar Pradesh ;

(b) whether it is a fact that Government have not so far distributed the said quantity ;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) the action Government propose to take in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) to (d) : The Government of U. S. S. R. made a gift of two lakh tonnes of wheat to alleviate the distress in the scarcity areas of the country without stipulating conditions about its free distribution or distribution only amongst the affected population of Bihar and Eastern U. P. Wheat received from U. S. S. R. has been merged with the stocks of wheat imported from other sources and issued through the normal channels. The value of this wheat will, however, be credited to the Scarcity Relief and Rural Development Fund.

भारतीय पर्यटक कार्यालय, लन्दन

916. श्री प्र० कु० घोष :
श्री कार्तिक ओराओं :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लन्दन स्थित भारतीय पर्यटक कार्यालय ने इंग्लैण्ड में भारत पर्यटन के प्रति अधिक आकर्षण पैदा करने का कार्य एक ब्रिटिश पब्लिसिटी एजेन्सी को दे दिया है ;

(ख) क्या उक्त एजेंसी ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके नियम तथा शर्तें क्या हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्णसिंह) : (क) यह मान लिया जाता है कि संभवतया यह निर्देश लंदन में उस 'जन सम्पर्क एजेंसी' की ओर है जिसकी भारत सरकार के लंदन स्थित पर्यटन कार्यालय की सहायता के लिये नियुक्ति का प्रस्ताव है। अभी तक इस विषय में कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

वैलोर हवाई अड्डा

917. श्री जी० कुचेलर : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि मद्रास राज्य के अब्दुल्लापुरम के वैलोर हवाई अड्डे का प्रयोग नहीं किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस हवाई अड्डे को बन्द करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके विकास करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्णसिंह) : (क) से (घ) : इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन की निकट भविष्य में वैलोर से होकर अनुसूचित विमान सेवाएं चलाने की कोई योजना नहीं है और वैलोर में अच्छे मौसम की हवाई पट्टी के, जो इस समय मद्रास फ्लाइंग क्लब प्रशिक्षण वायुयानों द्वारा क्षेत्र-पार (क्रॉस कन्ट्री) उड़ानों के लिए इस्तेमाल की जा रही है, विकास का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पाराद्वीप पत्तन

918. श्री ए० दीपा :
श्री प्र० के० देव :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री डी० एन० देव :
श्री जी० सी० नायक :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण कार्य के प्रथम चरण में सम्मिलित पारादीप पत्तन परियोजना सम्बन्धी समस्त निर्माण-कार्य पूरे हो गये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) : जब भारत सरकार ने पत्तन परियोजना अपने हाथ में ली तब निर्माण कार्यों का पुर्नविलोकन किया गया था और कुछ निर्माण की मदें काट दी गई थी या सुधारी गई थी। अनुमोदित कार्यक्रम को इस क्रम में रखा गया है कि जिससे पत्तन 20 लाख टन लौह धातु को प्रति वर्ष धर उठा सके। इस प्रकार निम्न मुख्य निर्माण कार्य पूरे हो गये हैं और पत्तन नवम्बर, 1966 से चालू है—

1–पहुँच और प्रवेश जल मार्गों सहित लागू का निकर्षण।

2–पहुँच जल मार्गों और लागून की रक्षा के लिये दो पनकट दीवार।

3–लौह धातु घाट कच्ची धातु उठाने धरने वाली संयंत्र सहित।

4–कार्यालय और अमला के लिये न्यूनतम आवश्यक इमारतें।

(2) सैंड पम्प-कम-शोर आधारित ड्रेजर के लिये एक घोड़ी पुल ड्रेजर के लिये घाट मूउद्धरण और तिरते जलयानों के मरम्मत के लिये स्लिपवे के निर्माण के लिये ठेके दे दिये गये हैं। ये निर्माण कार्य पत्तन के तुरन्त संचालन से सम्बधित नहीं है। फिर भी इन सब कार्यों के इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूरा होने की आशा है।

(3) एक ड्रेजर, दो हारबर टगो और एक सैंड-पम्प-कम-शोर आधारित ड्रेजर के लिये आर्डर दे दिया गया है। इनके 1967–68 के अन्त तक मिलने की आशा है। इनके चीजों के लेने में देर मुख्यत: विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण हुई है।

उड़ीसा की गेहूं की आवश्यकता

919. श्री ए० दीपा :
श्री डी० एन० देव :
श्री प्र० के० देव :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री जी० सी० नायक :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1967 के पश्चात् उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से हर माह कितने गेहूँ की मांग की और केन्द्रीय सरकार ने प्रति मास कितना गेहूँ दिया; और

(ख) यदि उड़ीसा को उसकी मांग के अनुसार गेहूँ की पूरी मात्रा नहीं भेजी गई तो इसके क्या कारण थे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) (क) और (ख) : उड़ीसा सरकार ने 15000 मीटरी टन गेहूँ प्रति मास आवंटित करने की प्रार्थना की थी। कम आमद होने और कमी से प्रभावित क्षेत्रों की न्यूनतम सप्लाई बनाए

रखने की आवश्यकता को देखते हुए उड़ीसा को मार्च में केवल 6,800 मीटरी टन और अप्रैल में 4,800 मीटरी टन गेहूँ की सप्लाई की जा सकी। मई के लिए 10,400 मीटरी टन गेहूँ का नियतन किया गया है और सप्लाई की जा रही है।

BORING MACHINES

920. Shri Sidheswar Prasad :
Shri Shashi Ranjan :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the State-wise break-up of the number of rigs boring machines used for boring tube wells in the hilly areas ;

(b) the number of such machines obtained during the last six months for the famine-stricken areas of Bihar and drought-affected areas of U. P. ; and

(c) the number of such machines imported during the above period ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) to (c) A statement giving the information available is attached. [**Placed in Library, See No. LT. 448/67**]

दिल्ली में दूध का मूल्य

921. **श्री अनन्तराव पाटिल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में दूध सप्लाई करने वालों ने हाल ही में दिल्ली में दूध का मूल्य बढ़ाने की कोई मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) 9 मई, 1967 से उत्तर प्रदेश के मेरठ तथा बुलन्दशहर जिलों तथा हरियाणा के गुड़गांव जिले में दूध के क्रय का मूल्य 82·50 रुपये प्रति क्विन्टल से बढ़ाकर 90 रुपये प्रति क्विन्टल कर दिया गया है। करनाल के निकट के क्षेत्रों में दूध का मूल्य 30 अप्रैल, 1967 से 72·00 रुपये प्रति क्विन्टल से बढ़ाकर 77·00 रुपये प्रति क्विन्टल कर दिया गया है।

Accommodation for Air India Crew in Delhi

922. Shri Har Dayal Devgun : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that accommodation is provided to the crew of Air India International in a private hotel in Delhi;

(b) if so, the expenses per head paid to the hotel; and

(c) the reasons for not providing accommodation to the crew in a Government owned hotel ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) to (c) : Air-India are not required to provide any regular hotel accommodation in Delhi to their crew, as Delhi is not a crew change-over station. On the rare occasions when it becomes necessary to provide accommodation for the crew in Delhi, they are accommodated in State owned hotels.

माही में पर्यटक केन्द्र

923. **श्री श्रीधरन :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए माही में एक पर्यटक केन्द्र खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) : ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) : साधनों के सीमित होने के कारण, पर्यटक-रुचि के स्थानों के विकास के कार्य को चयनात्मक आधार पर किया जाता है। अतः चौथी योजना की अवधि में कोवालम, पेरियार, कोचीन, कन्नानूर तथा केरल के अन्तर्जलीय प्रदेशों में पर्यटन सुविधाओं के विकास का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

कप्पड़ में पर्यटक केन्द्र

924. **श्री श्रीधरन :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) : क्या कप्पड़ में जहां कि वास्कोडिगामा उतरा था एक पर्यटक केन्द्र को स्थापित करना विचाराधीन है ; और

(ख) : यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क): ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) : प्रश्न ही नहीं उठता।

Bridge At Buxar

925. **Shri Chandrika Prasad :** Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state the progress so far made in regard to the scheme for the construction of a bridge at Buxar between Banaras and Patna ?

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V. K. R. V. Rao) : The progress in regard to the Scheme for the construction of a bridge over the Ganga at Buxar is tied

up with the progress of the studies of schemes for bridges at a few more sites over the Ganga in Uttar Pradesh and Bihar, viz. Ghazipur, Mirzapur, Farrukhabad, Raoli, Hardwar, Patna and Sakrigalighat. The responsibility for the construction of all these bridges primarily rests with the State Governments concerned, as these bridges fall on State roads. In order to determine the interse priority among them and to facilitate their selection for inclusion in the Fourth Plans of the States concerned, an economic feasibility study is in progress and a final decision about them, including the proposed bridge at Buxar, can be taken only after this study has been completed.

उड़ीसा को उर्वरकों का सम्भरण

926. श्री रामचन्द्र उलाका : श्री ख० प्रधानी :
श्री धुलेश्वर मीना : श्री हीरजी भाई :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) 1966–67 के दौरान उड़ीसा को कितना उर्वरक दिया गया;

(ख) क्या 1967–68 के दौरान कोटे में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) - (क) 1966–67 में उड़ीसा सरकार को विभिन्न प्रकार के उर्वरकों की अलाट की गई मात्रा तथा 12 मई, 1967 तक वास्तव में सप्लाई की गई मात्रा निम्न प्रकार है :—

उर्वरक की किस्म	1966–67 में अलाट की गई मात्रा	12–5–67 तक दी गई मात्रा
सल्फेट आफ अमोनिया	23,445	23,445
यूरिया	5,204	4,512
सी०ए०एन०	26,449	24,630
अमोनियम फास्फेट	12,000	11,447
डाई अमोनियम फास्फेट	13,167	12,841
कुल नाइट्रोजन के रूप में	17,763	16,649

(ख) विभिन्न उत्पादन कार्यक्रमों, आयात के लिए विदेशी मुद्रा की उपलब्धि तथा अनुमानित देशी उत्पादन व 1967–68 के लिए मांग को दृष्टि में रखते हुए 1967–68 की अवधि में नाईट्रोजन के रूप में उड़ीसा को 25,720 मीटरी टन उर्वरकों की मात्रा अलाट की जायेगी।

(ग) नाईट्रोजन पूरक उर्वरकों की मात्रा केन्द्रीय सरकार द्वारा त्रैमासिक आधार पर अलाट की जाती है। पहले 3 मास की अवधि (अर्थात् अप्रेल से जून तक) के लिए नाईट्रोजन पूरक उर्वरकों की निम्नलिखित मात्रा अलाट की गई है :—

	मीटरी टन
सल्फेट आफ अमोनिया	11,428
यूरिया	14,501
डाई अमोनिया फास्फेट	2,174
नाईट्रोजन के रूप में कुल मात्रा	9,462

आगामी तीन त्रैमासिक अवधियों में (अर्थात् जुलाई से सितम्बर, अक्तूबर से दिसम्बर 1967 तथा जनवरी से मार्च 1968 में) बाकी 16,258 मीटरी टन नाईट्रोजन की मात्रा अलाट की जायेगी।

उड़ीसा और राजस्थान में कृषि उत्पादन

927. श्री रामचन्द्र उलाका : श्री ख० प्रधानी :
श्री धुलेश्वर मीना : श्री हीरजी भाई

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या 1966-67 के दौरान उड़ीसा और राजस्थान की सरकारों को कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई अल्पकालीन ऋण दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) तथा (ख) : जी हां। ब्योरा निम्न प्रकार है :—

	उड़ीसा	राजस्थान
	(रुपये लाखों में)	
उर्वरक विपणन	115.69	167.71
उर्वरकों के लिए तकावी ऋण	100.00	66.53
कीटनाशक दवाईयां	40.00	33.00
बीज	—	80.70
कुल	255.69	347.94

Integration of Departments of Agriculture, Community Development & Cooperation

928. Shri Ramchandra Veerappa : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 7 on the 1st November, 1966 and state the further progress since made in the implementation of the Centre's suggestion to integrate the Department of Agriculture, Community Development and Co-operation ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : A statement containing the replies received from some States is laid on the Table of the Sabha. **[Placed in Library, See.** No. LT—**449/67]**

Aerodrome at Beedar (Mysore)

929. **Shri Ramchandra Veerappa :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether there is any proposal to construct an aerodrome at Beedar in Mysore State for the convenience of people during the Fourth Plan; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b) There is already an aerodrome at Beedar (commonly spelt as Bidar).

Grant to Mysore State for Agricultural Production

930. **Shri Ramchandra Veerappa :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Government of Mysore had requested the Centre for the sanction of grants to raise agricultural production during 1965—66;

(b) if so. the outcome thereof; and

(c) the purposes for which they were utilised ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) to (c) : The total assistance given to Mysore Government for agricultural production under the Plan during 1965—66 was Rs. 848.95 lakhs. The purpose for which amounts were given is indicated below separately under loans and grants :

(in lakhs)

	Loan	Grant
1. Agri. Production including land development	Rs. 36.81	Rs. 67.57
2. Minor irrigation	602.35	29.09
3. Animal Husbandry and Dairying	19.35	28.69
4. Forest	9.63	5.50
5. Soil Conservation	30.19	19.77
	698.33	150.62

This includes additional allocations given in response to a request made by the State Government for additional assistance for Minor Irrigation Schemes.

Damage to Foodgrains in Central Government Godowns

931. **Shri Ramchandra Veerappa :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that large quantities of foodgrains in the Central Government's godowns in Andhra Pradesh, Mysore and Maharashtra have been damaged during the last two years;

(b) whe causes of such losses and the total value of loss suffered; and

(c) whether any action has been taken against the persons responsible for such losses ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) : No, Sir. Only a small quantity of 8.8 tonnes of foodgrains was damaged in the Central Government godowns in Maharashtra State. The Central Government godowns in Andhra Pradesh and Mysore were handed over to the Food Corporation of India on 1-4-1965.

(b) : The loss occured due to overflowing of valley gutters of the godowns. Out of the total quantity of 8.8 tonnes, 3.6 tonnes has so far been disposed of. The loss on the quantity disposed of is Rs. 966.20. The loss on the balance quantity will be known when it is disposed of.

(c) : The loss occured on account of circumstances beyond anybody's control. No individual was found responsible for the said loss.

राज्यों में चावल का मूल्य कम करने के लिए सहायता

932. **श्री मोहसिन :** **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री अब्राहम : **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :**
श्री श्रद्धाकर सूपकार : **श्री नम्बियार :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों ने चावल के मूल्य कम करने के लिये केन्द्र से सहायता की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो जिन राज्यों ने ऐसी सहायता की मांग की है, उनके नाम क्या हैं; और

(ग) सरकार की इस बारे में प्रतिक्रिया क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

निजामाबाद और बीदर में हुए निर्वाचन

933. **श्री मोहसिन :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस आशय की कोई शिकायतें आई हैं कि आन्ध्र प्रदेश में निजामाबाद में तथा मैसूर में बीदर में निर्वाचन शान्तिपूर्ण ढंग से नहीं हुए ; और

(ख) क्या यह सच है कि निर्वाचन वाले दिन शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिये सेना बुलायी गयी थी और उसके बावजूद भी निर्वाचनों के दौरान बल्वे हुए तथा लूट मची ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) निजामाबाद जिले में निर्वाचनों के बारे में निर्वाचन आयोग को कोई ऐसी शिकायत प्राप्त नहीं हुई। बीदर जिले के बारे में, भारत के राष्ट्रपति को सम्बोधित एक तार को छोड़कर जिसमें कि साम्प्रदायिक गड़बड़ होने का अभिकथन

था और सैनिक नियंत्रण का सुझाव दिया गया था, निर्वाचन आयोग को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई कि निर्वाचन शान्तिमय ढंग से नहीं हुए।

(ख) ऐसी कोई जानकारी उपलभ्य नहीं है।

संयुक्त फार्म प्रायोगिक योजनाएं

934. **श्री रामचन्द्र उंलाका :** **श्री ख० प्रधानी :**

श्री धुलेश्वर मीना : **श्री हीरजी भाई :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1967–68 के दौरान उड़ीसा तथा राजस्थान राज्यों में संयुक्त फार्म अग्रिम योजनाएं चलाने पर विचार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) और (ख) : वर्ष 1967–68 के दौरान उड़ीसा में 5 संयुक्त फार्म समितियां तथा राजस्थान में 55 संयुक्त, फार्म समितियां बनाने का प्रस्ताव है।

चौथी योजना में अग्रिम योजनाओं की कोई विशेष श्रेणी नहीं है।

राजस्थान को उर्वरकों का भेजा जाना

935. **श्री रामचन्द्र उलाका :** **श्री ख० प्रधानी :**

श्री धुलेश्वर मीना : **श्री हीरजी भाई :**

क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966–67 तक राजस्थान को कितने उर्वरक भेजे गये ;

(ख) क्या 1967–68 के दौरान इसके कोटे में वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इसका कोटा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) 1966–67 की अवधि में राजस्थान सरकार को अलाट की गई विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजनपूरक उर्वरकों की मात्रा तथा 12–5–67 तक वस्तुतः सप्लाई की गई मात्रा निम्न प्रकार है :—

(आंकड़े मीटरी टनों में)

उर्वरक की किस्म	1966–67 के लिए अलाट की गई मात्रा	12–5–67 तक दी गई मात्रा
सल्फेट आफ अमोनिया	37,338	30,070
यूरिया	4,989	2,435
सी० ए० एन०	28,643	26,884
अमोनियम फास्फेट	5,000	5,000
डाई अमोनियम फास्फेट	6,521	01
सल्फेट आफ पोटाश	100	96
कुल नाईट्रोजन के रूप में	18,520	15,571

(ख) विभिन्न उत्पादन कार्यक्रमों, आयात के लिए विदेशी मुद्रा की उपलब्धि तथा अनुमानित देशी उत्पादन व 1967–68 के लिए मांग को दृष्टि में रखते हुए 1967–68 की अवधि में नाईट्रोजन के रूप में राजस्थान को 28,160 मीटरी टन उर्वरकों की मात्रा अलाट की जायेगी।

(ग) नाईट्रोजन पूरक उर्वरकों की मात्रा केन्द्रीय सरकार द्वारा त्रैमासिक आधार पर अलाट की जाती है। पहले 3 मासों में (अर्थात् अप्रैल से जून तक) नाईट्रोजनपूरक उर्वरकों की निम्नलिखित मात्रा अलाट की गई है :—

सल्फेट आफ अमोनिया	14,286 मीटरी टन
यूरिया	6,533 ,, ,,
सी०ए०एन०	4,463 ,, ,,
अमोनियम फास्फेट	4,675 ,, ,,
कुल नाइट्रोजन के रूप में	7,855 मीटरी टन

आगामी 3 तिमाहियों में (अर्थात् जुलाई से सितम्बर, अक्तूबर से दिसम्बर, 1967 तथा जनवरी से मार्च 1968 में) बाकी 20,305 मीटरी टन नाईट्रोजन की मात्रा अलाट की जायेगी।

राजस्थान में बागबानी का विकास

936. **श्री रामचन्द्र उलाका :** **श्री ख० प्रधानी :**
श्री धुलेश्वर मीना : **श्री हीरजी भाई :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

कि वर्ष 1967–68 के दौरान राजस्थान सरकार को, बागबानी के किसवा के लिये, कितनी धन-राशि देने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय नें राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : ऐसा समझा जाता है कि राजस्थान सरकार 1967–68 में बागबानी के विकास के

लिए 7.62 लाख रुपये की व्यवस्था कर रही है। किन्तु अभी हमारे पास निश्चित जानकारी नहीं है। केन्द्रीय आर्थिक सहायता विशेष योजनाओं के लिए स्वीकृत नहीं की जाती है बल्कि विकास के सभी शीर्षकों के लिए इकट्ठी स्वीकृत की जाती है। इसलिए बागबानी योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता सम्बन्धी आंकड़े देना सम्भव नहीं है।

राजस्थान में गन्ने की खेती का विकास

937. श्री धुलेश्वर मीना : श्री हीरजी भाई :
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री ख० प्रधानी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1966–67 में राजस्थान में गन्ने की खेती बढ़ाने के लिये उस राज्य को कोई वित्तीय सहायता दी थी;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) उस अवधि में उस राज्य में कुल कितने एकड़ भूमि पर गन्ने की खेती की गई है; और

(घ) उस अवधि में उस राज्य में गन्ने का कितना उत्पादन हुआ ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) राज्यों की गन्ना विकास योजनाएं 'कृषि उत्पादन' शीर्ष के अन्तर्गत सम्मिलित की जाती है जिसके लिए 1966–67 में राजस्थान सरकार को 91.17 लाख रुपये (ऋण=4.98 लाख और अनुदान = 86.19 लाख रुपये) केन्द्रीय सहायता के रूप में स्वीकार किए गए थे।

(ग) 1966–67 के गन्ने के अखिल भारतीय द्वितीय अनुमान के अनुसार 1966–67 में राजस्थान में गन्ने के अन्तर्गत कुल 48.1 हजार हैक्टर क्षेत्र था। क्षेत्र के बारे में अन्तिम आंकड़े जून-जुलाई, 1967 में प्राप्त होंगे।

(घ) गन्ने की पैदावार (गुड़ के हिसाब से) 73,000 टन से थोड़ी अधिक होने की आशा है।

राजस्थान और उड़ीसा में युवक होस्टल

938. श्री धुलेश्वर मीना : श्री हीरजी भाई :
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री ख० प्रधानी :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966–67 में राजस्थान और उड़ीसा राज्यों में युवक होस्टल के निर्माण के लिये वास्तव में कितनी धन राशि दी गई;

(ख) इसी कालावधि में किन किन स्थानों पर ऐसे होस्टल बनाये गये ; और

(ग) इस काम के लिये वर्ष 1967–68 में इन राज्यों को कितनी धन राशि देने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) : 1966–67 के दौरान युवक होस्टल बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान सरकार को कोई उपदान नहीं दिया।

(ख) इस अवधि में किसी भी दूसरे स्थान पर युवक होस्टल बनाने के लिए उपदान नहीं दिये गये।

(ग) 'युवक होस्टल' विषय पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय को अभी हाल ही में हस्तान्तरित किया गया है और इसलिए पर्यटन विभाग के चालू वर्ष के बजट में इस मद के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। युवक होस्टलों के बनाने का कार्य-क्रम तथा उनके निर्माण के लिये वित्तीय व्यवस्था के प्रकार (पेटर्न) पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

दांतवाला समिति का प्रतिवेदन

939. **श्री धुलेश्वर मीना** : **श्री ख० प्रधानी** :
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री हीरजी भाई** :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 4 अप्रैल 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 476 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच दांतवाला समिति की सिफारिशों पर कोई नया निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विशाखापत्तनम में ग्रेविंग डाक परियोजना

*940. **श्री धुलेश्वर मीना** : **श्री हीरजी भाई** :
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री ख० प्रधानी** :

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री 4 अप्रैल, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 479 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम में ग्रेविंग डाक परियोजना के बारे में जापानी सलाहकारों से प्राप्त प्रतिवेदन पर इस बीच विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) : यह प्रतिवेदन अभी सरकार के विचाराधीन है।

Production of Manure at Okhla

***941. Shri Maharaj Singh Bharti :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of manure produced at Okhla (Delhi) annually;

(b) the rate at which it is sold to farmers and the mode thereof;

(c) whether the said manure is supplied to other neighbouring States in addition to Delhi and if so the terms thereof; and

(d) the percentage of the said manure used for lawns during the last year ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation : (Shri Annasahib Shinde) : (a) Approximate quantity of manure produced at Okhla per year is 36,000 tons.

(b) Okhla sludge is supplied through Government trucks at the following rates per truck load;

Within 5 miles area	Rs. 15/—
Within 15 miles area	Rs. 20/—
Within 25 miles area	Rs. 25/—
Beyond 25 miles area	Rs. 30/—
Urban areas	Rs. 35/—

Farmers having their own transport arrangements, are also allowed to take the sludge on payment of the cost of sludge at the rate of Rs. 3/— per truck load of 3 tons.

Indents are received through applications alongwith the full cost of sludge in advance. All indents are recorded in chronological order and supplies are made in that order.

(c) Yes. The terms of supply to neighbouring States are the same as those for Delhi Territory.

(d) No record is maintained regarding the sludge used on lawns.

मंगलौर पत्तन परियोजना

*942 **श्री वी० चं० शर्मा :**—क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की तकनीकी रिपोर्ट मिल गई है, जिसमें 28 करोड़ रुपये की लागत वाली मंगलौर पत्तन परियोजना के लिये केन्द्रीय सरकार की अन्तिम स्वीकृति मांगी गई है :—

(ख) क्या सरकार ने उस रिपोर्ट पर विचार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय किया गया है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :—(क) से (ग) : मंगलौर पत्तन से मैग्नेटाइट कच्ची धातु की 40 लाख टन बिक्री की चीजों के उत्पादन की संभावना के बाबत राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की औचित्यता रिपोर्ट 19 मई, 1967 को मिल गयी है और वह विचाराधीन है ।

कृषि नीति

943 * **श्री वी० चं० शर्मा :**
श्री लकप्पा :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के हेतु आर्थिक विकास की गति बढ़ाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :—(क) चौथी योजना के लिए बनाए गए कृषि कार्यक्रमों का उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है। महत्वपूर्ण कार्यक्रम निम्नलिखित हैं :—

(1) पानी का प्रबन्ध करना, बीज की अधिक उपज वाली किस्मों का प्रबन्ध करना।

(2) देश के मुख्य अनाजों में अल्पकालीन किस्में जो दीर्घकालीन किस्मों के समान अच्छी उपज वाली हैं का शुरू करना। इससे देश के उन सिंचित क्षेत्रों में जहां केवल एक फसल उगाई जा रही थी दो फसलें उगाई जा सकती हैं। इस कार्यक्रम से 1970-71 में 30 मिलियन एकड़ भूमि में बुवाई होने की सम्भावना है। इन कार्यक्रमों से जिनमें लघु सिंचाई, भूमि संरक्षण, तथा भूमि विकास के सामान्य कार्यक्रम भी शामिल हैं 1970-71 में 30 मिलियन टोन्ज के उत्पादन उर्वरता उत्पन्न की जा सकती है और इस प्रकार देश के आर्थिक विकास की गति बढ़ेगी।

(ख) 1967-68 में क्रियान्वित किए जाने वाले कृषि उत्पादन कार्यक्रमों के मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं :—

(1) अधिक उपज वाली किस्म कार्यक्रम 15 मिलियन एकड़ भूमि में शुरू किए जायेंगे।

(2) मल्टीपल क्रोपिंग प्रोग्राम लगभग 7.5 मिलियन एकड़ भूमि में आयोजित किए जायेंगे।

(3) विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 13.5 लाख टोन्ज नाइट्रोजन, 5 लाख टोन्ज पी$_2$ ओ तथा 3 लाख टोन्ज के$_2$ ओ उपलब्ध किया जाएगा।

(4) लघु सिंचाई कार्यों द्वारा 3 से 3.5 मिलियन एकड़ अतिरिक्त भूमि पर उपज की जाएगी।

(5) पौद रक्षा उपायों द्वारा जिस क्षेत्र को लाभ पहुंचेगा उसे 126 मिलियन एकड़ तक बढ़ा दिया जायगा।

(6) कृषि भूमि पर भूमि संरक्षण उपायों का लाभ 3.9 मिलियन एकड़ भूमि तक बढ़ा दिया जाएगा ।

(7) बीजों, कीटनाशक दवाइयों, मशीनरी तथा ऋणों को देने के लिए, किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए सहायक प्रबन्ध भी किए गए हैं ।

(ग) 1966–67 का वर्ष प्रयोगात्मक वर्ष था और जो परिणाम अब तक निकले उनसे प्रतीत होता है कि अधिक उपज वाली किस्म कार्यक्रम किसानों को स्वीकार्य है और उत्साहवर्धक है जो निम्नलिखित बातों से प्रकट होता है—

(i) नई किस्मों का परीक्षण करने के लिए किसान इच्छुक हैं ।

(ii) खुले कूए, पम्प सैट, फिल्टर पुवाइंट तथा नलकूपों जैसे अनुपूरक सिंचाई परियोजनाओं में धन लगाने को किसानों की इच्छा ।

(iii) पानी के अनुकूलतम उपयोग के लिए उचित भूमि एकसार करने के लिए किसानों की इच्छा ।

खराब मौसम के बावजूद 1966–67 के दौरान अधिक उपज वाली किस्म कार्यक्रम से उत्साहवर्धक उपज हुई ।

कार्यक्रम पूरी तरह से 1967–68 से शुरू किया गया है । नई नीतियों तथा कार्यक्रमों का परिणाम पूरी तरह से आगामी वर्ष में निकलेगा ।

Samastipur Central Sugar Co. Ltd.

944. Shri Bhogendra Jha : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government took over the management of Samastipur Central Sugar Co., Ltd. in January, 1964:

(b) whether it is proposed to hand it over to the old management after the expiry of its term on the 13th July, 1967;

(c) whether the old management is now capable of managing the said Sugar Mill; and

(d) if not, whether Government propose to examine the question of taking over the mill permanently ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) : Yes, Sir.

(b) : The factory is proposed to be released from control under the Defence of India Rules before 1st July, 1967.

(c) : The share holders of the factory were asked to elect fresh Directors to take over the charge but they passed a resolution saving that they were un willing to take back the management at this time.

(d) : No, Sir.

पर्यटक सप्ताह (मार्च, 1967)

***945 श्री काशी नाथ पाण्डे :**
श्री डी० एन० देव :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मार्च, 1967 में मनाये गये पर्यटक सप्ताह से देश में पर्यटक यातायात पर हुए प्रभाग का अनुमान लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकला है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री : (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : मार्च 1967 में आयोजित पर्यटन सप्ताह केवल दिल्ली में मनाया गया। इसी तरह के पर्यटन सप्ताह मद्रास, जयपुर और चंडीगढ़ में भी आयोजित किये गये हैं, और अन्य राज्यों की भी इस वर्ष के दौरान पर्यटन सप्ताह मनाने की योजनाएं हैं।

इस देश में आने वाले पर्यटकों पर अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन सप्ताह समारोह का प्रभाव अभी इतनी जल्दी नहीं आंका जा सकता। अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष के अन्तर्गत दी जा रही विभिन्न सुविधाओं तथा रियायतों और किये जा रहे अन्य कार्य-कलापों का परिणाम सम्भवतः 1967 के अन्त तथा मालूम होगा जबकि इस वर्ष देश में आने वाले पर्यटकों की पिछले वर्ष आये पर्यटकों से तुलना करना सम्भव हो सकेगा।

संघीय सड़क परिवहन प्राधिकरण

***946 श्री काशी नाथ पांडे :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघीय सड़क परिवहन प्राधिकरण स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, इसके कृत्य क्या होंगे तथा इसका गठन किस प्रकार किया जायेगा ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) : फिलहाल इस प्रश्न पर कोई औपचारिक प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कलकत्ता में एक भाषण में परिवहन और नौवहन के मंत्री ने कहा था कि कालान्तर में राष्ट्रीय नीति और बढ़े साधनों सहित एक संघीय सड़क परिवहन अधिकरण की कल्पना आवश्यक हो सकती है किन्तु इसका स्वामित्व और प्रशासन राज्यों के साथ संयुक्तरूप से होगा और संभव हुआ तो गैर सरकारी क्षेत्र के साथ भी और यह रेल तथा अन्य परिवहन के रूपों जैसे अन्तर्देशी जल परिवहन तथा तटीय परिवहन के समन्वय में कार्य करेगा। इस सम्बन्ध में समस्त संबद्ध सामग्री संकलित की जा रही है। इसके पश्चात विचार करने के लिये प्रस्ताव बनाने पर निर्णय किया जायेगा।

"सूरज सलामत" पाल वाला जहाज

***947 श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **परिवहन तथा नौवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ?

(क) क्या यह सच है कि 23 मार्च, 1967 को सौराष्ट्र के तट पर तूफान आजाने के कारण "सूरज सलामत" पाल वाला जहाज, जिसमें प्याज और लौह अयस्क लदे हुए थे, अशान्त सागर में बिलीमोरा क्षेत्र में डूब गया ;

(ख) यदि हां, तो इससे कुल कितनी हांनि हुई ; और

(ग) जहाजों को ऐसी घटनाओं से बचाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० बी० के० आर० बी० राव) : (क) जी हां। पोत 19 मार्च 1967 को डूब गया।

(ख) पोत और माल का क्रमशः 10,000 रु०, और 5000 रु० का बीमा किया हुआ था जो पूर्णतया नष्ट हो गये। कोई जन-हानि नहीं हुई।

(ग) पाल पोतों की दुर्घटनाओं में कमी के लिये निम्न उपाय काम में लाये जा रहे हैं :—

1. पाल पोतों में यात्रियों या माल ले जाने के नियमन के लिये और ऐसे पोतों में रखे हुए माल और यात्रा करने वाले व्यक्तियों के लिये, वाणिज्य नौवहन अधिनियम 1958 के भाग 15 के अंतर्गत सरकार के पास शक्ति है।

2. जल परिवहन विभाग के प्रधान अधिकारियों और तट के सब अधिकारियों को नौवहन आयोग्य असुरक्षित पाल पोतों को समुद्र में चलने से रोकने की शक्ति दी गयी है।

3. हवा आती विभाग से सूचना प्राप्त होने पर पत्नन अधिकारी आंधी के चेतावनी संकेतों का प्रदर्शन करते हैं। वे माल पोतों के टिंडलों को भी खराब मौसम की स्थिति में समुद्र में जाने के खतरे को बताते हैं।

4. व्यवहारिक नौवहन, अग्नि शमन, जीवन रक्षा साधनों, प्रकाश और ध्वनि, संकेतों और अन्य संवैधिक उपस्करों, भोजन के नियमों, हवा पानी विज्ञान, इत्यादि के प्रशिक्षण के लिए सरकार ने लघु आवधिक प्रशिक्षण मन्जूरी दे दी है। ये प्रशिक्षण सम्बन्धित राज्य सरकारों की सलाह में स्थायी बना दिया गया है।

5. गहरे समुद्रों में कठिनाई में पड़े जहाजों की मदद के लिए सरकार ने वायु। समुद्र खोज और रक्षा संगठन की स्थापना की है। यह संगठन जिसकी सहायता पाल पोतों को भी उपलब्ध है, किसी पाल पोत के दुख ग्रस्त होने की सूचना के प्राप्त होते ही अपनी कार्यवाही शुरू कर देता है।

6. समुद्रवर्ती राज्य सरकारों ने कुछ ऐसे छोटे पतनों पर जो पालपोतों की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझे गये हैं, वायरलेस रिसीवर सेट लगा दिये हैं या लगाये जा रहे हैं जिससे पत्नन अधिकारी समुद्र में चलने वाले पोतों का समय रहते सुरक्षित स्थान पर आने की पहले ही चेतावनी दे सकें।

7. विभिन्न पाल पोत संस्थाओं को अनुदेश दिये गये हैं कि समुद्रगामी पाल पोतों के मालिकों को सलाह दी जाए कि वे पोत स्वेच्छा के तौर पर अपने साथ रेडियो

ले जायें ताकि वे भारतीय हवा पानी विभाग की सलाह से आकाश वाणी द्वारा प्रसारित आवधिक मौस बुलेटिन सुन सके ।

सान्ताक्रुज हवाई अड्डा

***948 श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई के सान्ताक्रुज हवाई अड्ड को सरकार फिर से नया रूप देने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) इस योजना पर कुल कितना खर्च आयेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) (क) से (ग) जी हां ।

सान्ताक्रुज टर्मीनल बिल्डिंग के अन्तर्राष्ट्रीय पक्ष (इन्टरनेशनल विंग) के विस्तार का कार्य हाल ही में लगभग 12.5 लाख रुपये की लागत से पूर्ण किया गया है । लगभग 40 लाख रुपये की लागत के कुछ परिवर्धनों व परिवर्तनों की मंजूरी हाल ही में दी जा चुकी है । इन कार्यों के 1968 के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है। एक नये एंटरनेशनल टर्मीनल कॉम्प्लेक्स बनाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

हिमाचल प्रदेश में खाद्य पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि

***949 श्री बलराज मधोक :**

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रत्येक राज्य का पृथक् खाद्य खण्ड बनाने के परिणाम स्वरुप हिमाचल प्रदेश में खाद्य पदार्थों के मूल्यों में एक दम वृद्धि हो गई है;

(ख) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश को उचित दर पर पर्याप्त खाद्य वस्तुओं का सम्भरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश का पुनः एक खाद्य खण्ड बनाने का कोई प्रस्ताव ,है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) कुछ खाद्यान्नों के भावों में जो कि एकहरा राज्य क्षेत्रों के निर्माण के बाद तुरन्त बढ़ने लगे थे, हाल ही में कुछ गिरावट आयी है ।

(ख) हिमाचल प्रदेश को हुई, 1967 में केन्द्रीय भण्डारों से तथा पंजाब सरकार द्वारा गेहूँ और चावल की अतिरिक्त मात्राएँ सुलभ की गयी हैं।

(ग) हिमाचल सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था ।

कॉन्टाज के सिडनी जाने वाले बोइंग विमान की दुर्घटना

950. **श्री विश्वनाथ पाण्डय** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च, 1967 मे कॉन्टाज एयरलाइन्स के सिडनी जाने वाले बोइंग विमान के कलकत्ता में दमदम हवाई अड्डे पर उतरने से पहले अचानक गिर जाने से यात्रियों तथा विमान के कुछ कर्मचारी घायल हो गये थे ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण थे ; और

(ग) कितने व्यक्ति घायल हुए ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : **(क) से (ग)** : कॉन्टाज एम्पायर एयरवेज बोइंग वायुयान को 27 मार्च, 1967, को लन्दन से सिडनी की अनुसूचित सेवा पर उड़ान करते समय करांची-कलकत्ता सेक्टर पर जमशेदपुर के पास अत्यधिक विक्षोभ का सामना करना पड़ा; जिसके परिणामस्वरूप पेटियों से असंनद्ध आठ यात्री तथा दो 'फ्लाइट स्टूअर्ड' विमान के केबिन में इधर से उधर ढुलकते रहे तथा उन्हें चोट आई। वायुयान को अवतरण प्राथमिकता (प्रायोरिटी लैंडिंग) प्रदान की गयी तथा वह इस घटना के 23 मिनट बाद कलकत्ता में उतरा। 6 यात्रियों की, जिन्हें मामूली चोटें आई थीं, प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड) की गयी और उन्हें विमान पर आगे जाने दिया गया। अवशिष्ट दो यात्रियों तथा दोनों फ्लाइट स्टूअर्डों को कलकत्ता में अस्पताल में दाखिल कर दिया गया।

Taichung Natiue—I Paddy

951. **Shri Maharaj Singh Bharti** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the target fixed in terms of acres for sowing Taichung Native—1 paddy during the coming Kharif crop and the details of the target and supply schemes regarding manure and insecticides in this connection;

(b) the arrangements made for proper irrigation in the aforesaid areas; and

(c) the kinds of paddy other than the one cited above which would be shown and the area likely to be cultivated for this purpose and the resources to be exploited in this regard ?

The Minister of state in the ministry of Food, Agriculture, community development & Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) to (c) It is planned to bring a total area of about 41.36 lakh acres under the high-yielding varieties of paddy during kharif, 1967. The area proposed to be covered under different varieties is as under :—

1.	Taichung Native—1	19.03 Lakh acres
2.	ADT—27	8.65 ,, ,,
3.	Tainan—3	3.12 ,, ,,
4.	Taichung—65	3.32 ,, ,,
5.	IR—8	2.20 ,, ,,
6.	Other varieties	5.04 ,, ,,
		41.36 Lakh acres

The above programme will be taken up in areas having assured irrigation/ rainfall.

The State Governments have made their own arrangements for supply of seeds of these varieties to cover the targetted area. In case of shortages, the National Seeds Corporation would arrange to supply the required quantities when approached by the needy States. As regards fertilizers, a quantity of 1.5 lakh tonnes of nitrogen will be made available to the States to meet the full requirements of the above area. About 55% of this quantity has already been allocated to the States from the Central Pool for the quarter April-June, 1967. As regards pesticides, the State Governments have got adequate stocks to meet the requirements of the programme.

The Reserve Bank of India have agreed to sanction adequate credit limits to meet the requirements of agricultural credit under the High Yielding Varieties Programme in respect of the members of cooperatives. In the case of non-members, the State Governments, as in the previous year, would arrange to provide taccavi loans to farmers to enable them to take up the cultivation of high yielding varieties. In view of the large size of the programme for 1967-68, the State Governments have been advised to take full advantage of the liberal credit limits to be sanctioned by the Reserve Bank of India. The discussions held with the State Governments, however, indicate that generally there will be no difficulty in meeting the requirements of short term credit for the High-Yielding Varieties Programme 1967-68.

Use of compost manure in Shahdra-Delhi.

952. **Shri Maharaj Singh Bharti :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the garbage dumped in Shahra-Delhi is not being turned into compost manure at present but is being used for levelling the low lying areas;

(b) whether it is also a fact that the pebbles, stones, glass pieces, etc. are not removed from the garbage which is converted into compost and whether this is the reason as to why farmers do not purchase the Delhi manure; and

(c) whether Government propose to set up a fertiliser factory with foreign collaboration and use the said compost manure as raw material ?

The Minister of state in the ministry of Food, Agriculture, Community Development and Coop. (Shri Annasahib Shinde) : It is true that the Municipal Corporation of Delhi is at present utilising the garbage for levelling the low lying areas. The compost formed by the heap method from the garbage previously dumped by the Municipal Corporation at Shahdra/Dumping ground does contain inert material such as pebbles, stones, glass pieces, etc. Due to this, farmers do not purchase this manure. They are, however, allowed to remove this manure free of cost. The Delhi Administration is arranging to sieve some of this manure for sale to cultivators.

(c) No, Sir.

Prices of Foodgrains in States

953. **Dr. Mahadeva Prasad :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that prices of commodities specially of foodgrains have gone down in the States where there are non-Congress Governments; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministery of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annnsaheb Shinde) : (a) No distinction has been noticeable between the States with Congress Government and States with non-Congress Government in the matter of rise or fall in the prices of agricultural commodities, including foodgrains, for which information is available in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation.

(b) Does not arise.

बिहार में उपहार स्वरूप प्राप्त कपड़ों की बिक्री

954. **श्री काशीनाथ पाण्डे :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूरोप तथा उत्तरी अमरीका से उपहार स्वरूप प्राप्त कपड़ों को, जो कि बिहार में दरिद्र व्यक्तियों में बांटे गये थे, खुले बाजार में दुकानदारों को बेचा गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के कार्य को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : कमी से प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ित व्यक्तियों में बांटने के लिये केन्द्रीय सहायता समिति (भारत) नई दिल्ली को केवल योरूप से विदेशी कपड़ों के उपहार प्राप्त हुये हैं। बिहार सहायता समिति जिसे केन्द्रीय सहायता समिति ने बिहार के कमी से प्रभावित क्षेत्रों में इन कपड़ों को बांटने का काम सौंपा था, को इन कपड़ों के खुले बाजार में दुकामदारों के हाथ बेचे जाने के बारे में कोई प्रत्यक्ष जानकारी नहीं है ;

पोर्ट ब्लेयर में जहाजों का रोका जाना

955. **श्री गणेश :** क्या **परिवहन तथा नौवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुख्य भाग तथा द्वीप के बीच चलने वाला जहाज "एम० वी० निकोबार" जो पोर्ट ब्लेयर के बाहर 2 मई, 1967 को अपनी यात्रा पर था, लगभग 10 दिन तक पोर्ट ब्लेयर में रोका गया था:

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे;

(ग) पोर्ट ब्लेयर में जहाज सामान्यतया कितने दिन रुकते हैं; और

(घ) "एम० बी० निकोबार" के, जो कि 2 मई, 1967 को पोर्ट ब्लेयर के बाहर अपनी यात्रा पर था, जबरदस्ती रोके जाने के कारण सरकार को कितना अतिरिक्त अवरोधन शुल्क देना पड़ा ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) : जी हां। यात्रियों की भीड़ के कारण और छुट्टियों में मुख्य भूमि के लिये निःशुल्क यात्रा करने वाले अध्यापक और उनके परिवार के लिये तीन या चार दिनों तक पोत को रोका गया।

(ग) सामान्यतः पोत आठ या दस दिनों तक रुकता है जो रितु और धरने उतारने के माल की प्रकृति या मात्रा पर निर्भर करता है।

(घ) यदि रोकने के प्रभार कोई अदा करने को होते हैं तो, पोत के चालन के वार्षिक हिसाब की प्राप्ति के बाद जाने जाते हैं। ये चालू वित्तीय वर्ष के अन्त में शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा दिये जाते हैं।

कलकत्ता से पोर्ट ब्लेयर को इण्डियन एयरलाइन्स की निर्धारित उड़ानें

956. **श्री गणेश** :
श्री आर० के० सिन्हा :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमान "स्काईमास्टर" को, जो कि पोर्ट ब्लेयर के लिये अपनी निर्धारित उड़ान पर था, 15 मई, 1967 को पोर्ट ब्लेयर में बादलों के घिर आने के कारण पोर्ट ब्लेयर के निकट से कलकत्ता वापस लौटना पड़ा था;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त विमान कार-निकोबार स्थित इण्डियन एयर फार्स टर्मिनल बेस से सम्पर्क स्थापित नहीं कर सका था;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे; और

(घ) क्या सरकार का विचार कार-निकोबार स्थित इण्डियन एयर फोर्स टर्मिनल बेस को यह निर्देश देने का है कि वह पोर्ट ब्लेयर तथा कलकत्ता को अपनी निर्धारित उड़ानों पर आने-जाने वाले इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमानों की उड़ान पर निगरानी रखे ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) और (ख) : जी हां।

(ग) और (घ) : चूंकि पोर्ट ब्लेयर में आंधी-पानी और भारी वर्षा थी और पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे के निकट के पहाड़ों की चोटियां बादलों से ढकी थी, इसलिए विमान का वहाँ उतरना संभव नहीं था। विमान-चालक ने मौसम का हाल मालूम करने के लिए कार-निकोबार से सम्पर्क स्थापित करने का प्रयत्न किया लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। आई० ए० सी० की अनुसूचित उड़ानों के लिए कार-निकोबार को पोर्ट ब्लेयर का वैकल्पिक हवाई अड्डा निर्दिष्ट किया गया है। कार-निकोबार हवाई अड्डे के, विमानों के वहां पहुंचने के प्रत्याशित समय के एक घण्टा पहले और रवाना होने के प्रत्याशित समय के एक घण्टे बाद तक खुला रहने के लिए पहले से प्रबन्ध मौजूद है। उन परिस्थितियों की जिनके कारण विमान-चालक उस विशेष दिन कार-निकोबार से सम्पर्क स्थापित नहीं कर सका, जाँच की जा रही है।

अन्दमान लेबर फोर्स कापरेटिव सोसाइटी

957. **श्री के० आर० गणेश** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान लेबर फोर्स कॉपरेटिव सोसाइटी अब काम नहीं कर रही है;

(ख) क्या इस समिति के लेखों की लेखा परीक्षा कर ली गई है;

(ग) लेखा-परीक्षकों के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं;

(घ) क्या बहुत से शेयर होल्डरों को उनके शेयरों की राशि वापस दी गई है; और

(ड) यदि हां, तो ऐसे कितने शेयर होल्डर हैं, और इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ड) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पोर्ट ब्लेयर से जहाज सेवा

958. **श्री गणेश** : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) 2 और 3 मई, 1967 को अथवा उसके आस पास पोर्ट ब्लेयर से "एम० वी० अन्दमान" और "एम० वी० निकोबार" नामक जहाजों में यात्रा के लिये कितने मुसाफिरों ने आवेदन किया था;

(ख) इनमें से कितने मुसाफिरों को इन जहाजों में स्थान नहीं दिया गया;

(ग) इन जहाजों में आम जनता को कितने स्थान दिये गये तथा इन जहाजों में कुल स्थान का यह कितनी प्रतिशत थे;

(घ) ऐसे मुसाफिरों की संख्या क्या है जिन्हें लगातार इन दो जहाजों की तीन यात्राओं के दौरान स्थान नहीं दिया गया;

(ड.) क्या यह सच है कि द्वीपसमूह के विभिन्न भागों से आये हुए मुसाफिर पोर्ट ब्लेयर में रुके पड़े हैं, और

(च) यदि हां, तो गत कुछ महीनों से इन जहाजों में स्थान प्राप्त करने के लिये पड़े हुए यात्रियों को जहाजों में स्थान देने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) वा० पो० निकोबार (कलकत्ता के लिये 2 मई को रवाना हुआ) और वा० पो० अन्दमान (मद्रास के लिये 3 मई को रवाना हुआ) द्वारा पोर्ट ब्लेयर से सलून, बंक और डेक में यात्रा के लिये अर्जी देने वाले यात्रियों की संख्या 2701 है।

(ख) 1852

(ग) 86 यह दस प्रतिशत से थोड़ा अधिक है।

(घ) और (ड.) : सूचना उपलब्ध नहीं है। सूचना एकत्रित की जायेगी और सभा पटल पर पेश कर दी जायेगी।

(च) तुरन्त आवश्यकता की पूर्ति के लिये जून के प्रथम सप्ताह में एक विशेष सेवा चलाने का प्रस्ताव है।

दीर्घ कालीन प्रबन्ध के लिये इस वर्ष के जून के अन्तिम सप्ताह से एक बड़े पोत में इस सेवा को चलाने का प्रस्ताव है।

Supply of Foodgrains To Bihar

959. **Shri Gunanand Thakur :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the allotted quantity of foodgrains to Bihar was not supplied between January to April, 1967;

(b) whether it is also a fact that foodgrains do not reach Bihar in time; and

(c) if so, the arrangements proposed to be made by Government to remove all these short comings ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) There were some marginal short supplies during the months January to March, 1967. April quota was suppled in full. (b) and (c) Despatches of imported foodgrains depend on arrivals of ships at the ports, which cannot be precisely regulated. Some movements also take place on long distances and delay in transit in such cases is inevitable. To tide over the periods of short receipts, releases are often made from local reserves of Central Government maintained for the purpose.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

कुछ केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा बिड़ला बन्धुओं से वेतन पाने के बारे में छपे समाचार

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं माननीय प्रधान मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"कुछ केन्द्रीय मन्त्रियों द्वारा बिड़ला बन्धुओं से वेतन पाने के बारे में छपे समाचार",

Shri George Fernandes (Bombay-south) : On a point of Order, Sir. The Prime Minister should not answer this question. Shri Birla told me that he is working for the election of Mrs. Indira Gandhi to the office of Prime Minister.

अध्यक्ष महोदय : किसी निजी बातचीत पर यहां चर्चा नहीं की जा सकती। प्रधान मंत्री का ध्यान इस मामले की ओर दिलाया गया है। उन्हें उत्तर देना होगा ! **(अन्तर्बाधायें)**।

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : क्या यह बिड़ला की सरकार है ?

अध्यक्ष महोदय : आप इसे बिड़ला की सरकार समझ सकते हैं और सरकार आपका किसी का एजेंट समझा सकती है। इससे कोई लाभ नहीं होगा।

प्रधान मन्त्री तथा अणुशक्ति मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मालूम होता है कि श्री बिड़ला को श्री फर्नेन्डीज पर विश्वास है। यह बात मुझे अथवा किसी अन्य व्यक्ति को नहीं कही गई।

कांग्रेस संसदीय दल की अभी हाल ही की एक बैठक में श्री अर्जुन अरोड़ा ने कहा था कि कुछ मंत्री बिड़ला से वेतन पाते हैं। मैंने श्री अरोड़ा से कहा है कि इस बारे में जो भी जानकारी उनके पास है, उसे वह पेश करें। उन्होंने ऐसा करने का वचन दिया है। यह सूचना मिलने पर मैं स्वाभाविक ही उसकी जांच करूंगी। तब तक कुछ और बात कहना उचित नहीं होगा।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि मंत्री मण्डल के एक मंत्री तथा एक राज्य मंत्री अभी तक बिड़ला बन्धुओं से मानदेय ले रहे हैं। मंत्री मण्डल के मंत्री बिड़ला ट्रस्ट के अध्यक्ष थे या उपाध्यक्ष थे। राज्य मंत्री 1966 में राज्य मंत्री नहीं थे। क्या यह भी सच है कि मंत्री मण्डल के एक सदस्य के पुत्र को 1966 में बिड़ला बन्धुओं से 1,80,000 रुपये कमीशन के रूप में मिले थे ?

प्रधान मंत्री को जानकारी देने से इनकार नहीं करना चाहिए। जानकारी केवल दो कारणों में ही रोकी जा सकती है। एक तो यह कि जानकारी देना देश की सुरक्षा के हित में नहीं है और दूसरा यह कि ऐसा करना लोक हित में नहीं है। यह मामला इन दोनों में से किसी के अन्तर्गत नहीं आता।

कुछ माननीय सदस्य : उन मन्त्रियों के नाम बताये जायें (अन्तर्बाधायें)

श्री स० मो० बनर्जी : एक श्री सत्य नारायण सिंह हैं और दूसरे श्री कृष्ण चन्द्र पन्त प्रधान मंत्री को बताना चाहिये कि उन्हें इसकी जानकारी है अथवा नहीं। श्री अर्जुन अरोड़ा पर नाम न बताने के लिए जोर डाला जा रहा है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जब तक इन आरोपों की जांच न की जाये, कुछ नहीं कहा जा सकता है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : These charges have appeared in the newspapers. It is, therefore, no more a party matter. It has now become a public matter. It should, therefore, be taken up as a question of privilege. When such charges are levelled against the ministers, the only course left to us is to ask the person, who has levelled. the charges, to prove the veracity of such charges. If the person concerned is able to substantiate the charges, action should be taken against the Ministers, but if he fails to substantiate them, action should be taken against him.

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपका ध्यान नियम 41 (2) (नौ) तथा (दस) की ओर दिलाना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

Shri Madhu Limaye : It does not matter whether the Minister concerned is a member of Lok Sabha or Rajya Sabha. The matter should either be referred to the Committee of Privileges or it should be referred to any other Committee comprising of 15 Members of Parliament. Some of them may be from Rajya Sabha. I have already given a notice to that effect. This matter should not be taken to be a matter

concerning the Congress party alone. It also does not concern to Shri Ajrun Arora, Deputy Prime Minister and Prime Minister alone.

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : श्री मधु लिमये ने एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया था। आप यह नहीं कह सकते कि इस मामले पर बाद में विचार किया जायेगा। इस सम्बन्ध में यदि प्रधान मन्त्री द्वारा अपने दल के अन्दर ही जांच की जाती रहेगी तो प्रधान मन्त्री, श्री देसाई, श्री चव्हाण तथा सभी पर सन्देह बना रहेगा **(अन्तर्बाधायें)**।

यह ऐसा मामला है जिस पर समूचे सदन द्वारा विचार किया जाना चाहिये, न कि प्रधान मंत्री द्वारा जिन पर स्वयं आरोप लग सकता है। यह तथ्य बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं परन्तु उन्हें जांच के लिए किसी संसदीय समिति के समक्ष लाना चाहिये न कि इस प्रकार की × × **(अन्तर्बाधायें)**

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : यह × × शब्द आपत्तिजनक हैं। संसद × × नहीं है।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : संसद × × नहीं है। ऐसा नहीं कहा जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह शब्द कार्यवाही से निकाल रहा हूं।

उप-प्रधान मंत्री तथा विधि मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : माननीय सदस्य को इसके लिए क्षमा मांगनी चाहिये।

श्री ही० ना० मुकर्जी : मैं समझता था कि माननीय वित्त मंत्री मजाक को बुरा नहीं समझेंगे। मुझे यह शब्द वापिस लेने में कोई आपत्ति नहीं।

Shri Hardayal Devgun (East Delhi) : Shri Arjun Arora had levelled the charges in a meeting of Congress Parliamentary Party on 26th May. The Prime Minister had asked him 5 or 6 days ago to give the names of such ministers. The names have not been given so far and it appears that there is something wrong at the bottom. This causes suspicion about the whole of the cabinet.

Shri K. N. Tiwari (Bettiah) : Sir, I want to know whether anything that is published in papers or is said in Party meeting can be the subject of a calling attention notice ?

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur) : Sir, the first question has not been answered. The question is whether the Prime Minister has tried to ascertain the facts from Shri Arjun Arora ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैंने श्री अरोडा से कहा है कि वह मुझे तथ्य बतावें। जब मुझे पता चला तो मैं देखूंगी।

× × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

× × Expunged as ordered by the chair.

Shri Bal Raj Madhok (South Delhi) : Mr. Speake, Sir, Publio life in our country is becoming polluted. The ruling Party has been associated with big business houses. There have been allegations like this from time to time. Now a member of the ruling Party has disclosed some secrets. The Cabinet has joint responsibility. How can the Prime Minister be accused and judge ? **(Interruptions)**. An enquiry must be held. A Parliamentary Committee should be appointed and Shri Arjun Arora and all other concerned should place facts before the Committee.

Dr. Ram Subhag Singh : Sir, I rise on a point of order. Shri Madhok has used an improper word for the Prime Minister. He should withdraw that word.

मैं जानना चाहता हूँ क्या यह शब्द संसदीय है। इसे सभा की कार्यवाही में शामिल न किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : श्री मधोक ने कहा है कि समिति गठित की जानी चाहिये।

डा० राम सुभगसिंह : श्रीमान जी मेरी बात का उत्तर नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय : यदि यह शब्द प्रधान मंत्री के बारे में कहे गये हैं तो मुझ खेद है।

श्री बलराज मधोक : मैंने किसी के विरुद्ध कोई शब्द नहीं कहा है। यह किसी के विरुद्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : श्री मधोक ने यह शब्द प्रधानमंत्री के विरुद्ध नहीं कहा।

श्री बलराज मधोक : मैंने तो केवल हिन्दी की एक लोकोक्ति का प्रयोग किया है। मैंने प्रधान मंत्री को चोर नहीं कहा है।

श्री रंगा : प्रधानमंत्री को श्री मधोक के प्रश्न का उत्तर देना चाहिये।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यदि किसी मंत्री के विरुद्ध आरोप लगाया जाता है तो उस पर विचार किया जाता है। परन्तु निराधार आरोपों के बारे में जाँच नहीं हो सकती।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : श्रीमान जी बहुत गम्भीर आरोप लगाये गये हैं। मैं चाहता हूँ कि उच्चतम न्यायपालिका की राय जाननी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं इन सुझावों पर विचार करूंगा।

श्री श्री० अ० डांगे (बम्बई-मध्य-दक्षिण) : जब आप श्री मधु लिमये के प्रस्ताव पर विचार करें तो हमारे भूतपूर्व गृह–कार्य मंत्री श्री नन्दा की इस बात पर ध्यान दें कि इस सभा के 45 सदस्य बिड़ला से वेतन पाते हैं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

राजस्व प्राप्तियों के बारे में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल), 1967

उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं (1) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत राजस्व प्राप्तियों के बारे में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल), 1967 की एक प्रति सभा पटल रखता हूँ। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 450/67]**

कोचीन पत्तन न्यास का वर्ष 1965-66 का प्रतिवेदन

परिवहन तथा नौवहन (डा० वी० के० आर० वी० राव) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :—

(एक) बड़े पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कोच्चिन पत्तन न्यास के 1965–66 के वार्षिक लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 105/67]**

(दो) मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

**(एक) दिल्ली मोटर गाड़ी (तीसरा संशोधन) नियम, 1966 जो दिनांक 22 दिसम्बर, 1966 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ 3(13)/65–66 ट्रांसपोर्ट में प्रकाशित हुए थे ।

***(दो) अधिसूचना संख्या 158/66/एफ० संख्या 68–332/66–पब० जो दिनांक 5 दिसम्बर, 1966 के अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह मोटर गाड़ी नियम, 1939 में कतिपय संशोधन किये गये ।

***(तीन) अधिसूचना संख्या 166/66 एफ० संख्या 68/261/66–पब० जो दिनांक 27 दिसम्बर, 1966 के अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह मोटर गाड़ी नियम, 1939 में कतिपय संशोधन किये गये । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 196/67]**

(2) बड़े पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के 1964–65 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 451/67]**

(दो) मरमुगाओ पत्तन न्यास के 1964-65 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 452/67]**

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–क की उपधारा (1) के अन्तर्गत सेंट्रल रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, के 1965–66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 453/67]**

(3) बड़े पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 122 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) मरमुगाओ पत्तन न्यास (न्यासधारियों को फीस और भत्तों की अदायगी) संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 24 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1977 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 451/67**]

(दो) बड़े पत्तन न्यास (न्यासधारियों को फीस भत्तों की अदायगी) संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 31 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2027 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 455/67**]

श्रम मन्त्री की वार्ता की बंगला भाषा में प्रति

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथि) : मैं पश्चिमी बंगाल के श्रम मंत्री, श्री सुबोध बनर्जी की वार्ता, जो 1 मई, 1967 को रेडियो पर दी जानी थी, की बंगला भाषा में एक प्रति, उसके अंग्रेजी अनुवाद सहित सभा पटल पर रखती हूँ। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 456/67**]

विमान अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :—

विमान अधिनियम, 1934 की धारा 14–क के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं, व्याख्यात्मक टिप्पण सहित, की एक-एक प्रति :—

(एक) विमान (संशोधन) नियम, 1967 जो दिनांक 8 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 484 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विमान (दूसरा संशोधन) नियम, 1967 जो दिनांक 15 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 511 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विमान (तीसरा संशोधन) नियम, 1967 जो दिनांक 22 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 548 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 457/67**]

धान कूटन उद्योग (विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहब शिन्दे) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) धान कूटन उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 22 की उपधारा (4) के अन्तर्गत धान कूटन उद्योग (विनियमन तथा लाइसेंस देना) संशोधन नियम, 1967 की एक प्रति पुनः सभा-पटल पर रखेंगे जो दिनांक 11 फरवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में

अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 187 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 28/67]**

(2) (एक) धान कूटन उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 22 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत धान कूटन उद्योग (विनियमन तथा लाइसेंस देना) दूसरा संशोधन नियम, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 20 मई, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 735 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 458/67**]

(3) (दो) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 उप-धारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 497 जो दिनांक 5 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 1 फरवरी, 1967 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 153 में एक संशोधन किया गया।

(दो) जी० एस० आर० 499 जो दिनांक 10 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पश्चिमी बंगाल अत्यावश्यक वस्तु (वहन पर प्रतिबन्ध) नियन्त्रण आदेश, 1965 का प्रतिसंहरण किया गया।

(तीन) राजस्थान खाद्यान्न (सीमा पर वहन पर प्रतिबन्ध) दूसरा संशोधन आदेश, 1967 जो दिनांक 22 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 561 में प्रकाशित हुआ था।

(चार) अन्त: क्षेत्रीय गेहूं तथा गेहूं उत्पादन (वहन नियन्त्रण) चौथा संशोधन आदेश, 1967 जो दिनांक 22 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 562 में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) जी० एस० आर० 563 जो दिनांक 22 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गुजरात बेलन मिलें मिश्रित आटा (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1966 का प्रतिसंहरण किया गया।

(छ:) अन्त:क्षेत्रीय गेहूं तथा गेहूं उत्पाद (वहन नियन्त्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 1967 जो दिनांक 15 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 567 में प्रकाशित हुआ था।

(सात) दिल्ली निर्धारित खाद्य वस्तु (वहन नियन्त्रण) संशोधन आदेश, 1967 जो दिनांक 15 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 568 में प्रकाशित हुआ था।

(आठ) उत्तरी अन्त: क्षेत्रीय चावल (वहन नियन्त्रण) आदेश, 1967 जो दिनांक 18 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 573 में प्रकाशित हुआ था।

(नौ) जी० एस० आर० 574 जो दिनांक 18 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उत्तरी क्षेत्र धान (निर्यात पर प्रतिबन्ध) आदेश, 1959 का प्रतिसंहरण किया गया।

(दस) उत्तरी अन्तः क्षेत्रीय चना (वहन नियन्त्रण) आदेश, 1967 जो दिनांक 18 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 575 में प्रकाशित हुआ था।

(ग्यारह) उत्तरी अन्तः क्षेत्रीय मक्का (वहन नियन्त्रण) आदेश, 1967 जो दिनांक 3 मई, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 658 में प्रकाशित हुआ था।

(बारह) जी० एस० आर० 708 जो दिनांक 10 मई, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1842 में कतिपय संशोधन किये गये।

(तेरह) राजस्थान खाद्यान्न (सीमा पर वहन पर प्रतिबन्ध) तीसरा संशोधन आदेश, 1967 जो दिनांक 20 मई, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 736 में प्रकाशित हुआ था। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 459/67**]

(4) (तीन) पशु कल्याण बोर्ड मद्रास के 1965–66 के वार्षिक लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 460/67**]

परिसीमन आयोग अधिनियम के अन्तर्गत आदेश

विधि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री द० र० चव्हाण) : मैं इन पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) परिसीमन आयोग अधिनियम, 1962 की धारा 11 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति :—

(एक) आदेश संख्या 5–सी जो दिनांक 11 जनवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 147 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 2 जून, 1966 के परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 5 में कतिपय संशोधन किये गये।

(दो) आदेश संख्या 15-ए जो दिनांक 27 जनवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 352 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 23 मई, 1966 के परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 15 में कतिपय शुद्धियां की गईं

(तीन) आदेश संख्या 5-डी जो दिनांक 31 जनवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 420 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा

बिहार राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 2 जून, 1966 के परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 5 में कतिपय शुद्धियां की गई। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 461/67**]

(2) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन (मैसूर) संशोधन आदेश, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 26 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 626 में प्रकाशित हुआ था। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 462/67**]

(3) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 28 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निर्वाचनों का रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 1 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1127 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 463/67**]

(4) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 169 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 25 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1542 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखा गई। देखिये संख्या एल० टी० 464/67**]

याचिका का उपस्थापन

PRESENTATION OF PETITION

Shri George, Fernandes (Bombay-South) :—Sir, I present a petition of Shri Vasant Vasudeo Kulkarni and others of Ahmednagar on transfer of Vehicles Research Development Establishment from Ahmednagar to Avadi.

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिय स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the clock.

लोकसभा दो बजे म० प० पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha re-assembled at fourteen of the clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the chair]

केरल को सप्लाई किये गये अनाज के बारे में निदेश 115 के अन्तर्गत वक्तव्य

STATEMENT UNDER DIRECTION 115 RE. FOOD GRAINS SUPPLIED TO KERALA

श्री वासुदेवन नायर (परिमेड) : श्रीमान् जी अध्यक्ष के निदेश संख्या 115 (1) के अन्तर्गत मैं खाद्य मंत्री के वक्तव्य में शुद्धि करना चाहता हूं। यह केरल को प्रतिमास खाद्यान्नों

की सप्लाई के बारे में है। मंत्री महोदय ने जो मात्रा बतायी थी उससे कम अनाज़ वहां भेजा गया है। अप्रैल के महीने में 10,000 टन का अन्तर है। मंत्री महोदय का वक्तव्य ठीक नहीं है।

केरल को भारत खाद्य निगम के द्वारा अनाज भेजा जाता है। मैंने कोई गलत बात नहीं कही है।

श्री अ० क० गोपालन (कैसरगोड) : केरल मुख्य मंत्री तथा खाद्य मंत्री ने आंकड़े दिये हैं। उनके आंकड़ों तथा केन्द्रीय खाद्य मंत्री के आंकड़ों में अन्तर है। इस बारे में जांच होनी चाहिये। और पता लगाना चाहिये कि किसके आंकड़े गलत हैं।

श्री नायनार (पालघाट) : मंत्री महोदय को यहां पर क्षमा याचना करनी चाहिये।

श्री अ० क० गोपालन : एक जहाज को कोचीन बन्दरगाह पर अनाज उतारने को भेजा गया था परन्तु उसका पूरा अनाज वहां नहीं उतारा गया और किसी और स्थान पर भेज दिया गया।

श्री जगजीवन राम : कई स्रोतों से केरल को अनाज की सप्लाई की जाती है। हो सकता है खाद्य निगम के आकड़ों में कोई गलती हो। मेरे पास पिछले वर्ष तथा इस वर्ष के आंकड़े हैं। केरल को जनवरी में 66,300 टन, फरवरी में 48,000 टन, मार्च में 70,700 टन और अप्रैल में 45,2000 टन चावल सप्लाई किया गया है। यह आंकड़े हमारे पास आये हैं। इसमें जो अन्तर बताया गया है उसके बारे में मैं पता चलाऊंगा। इस बारे में राज्य सरकार से भी पता लगाया जायेगा। अप्रैल की सप्लाई के बारे में जो अन्तर है उसकी जांच की जायेगी। मैं किसी प्रकार की जानकारी छिपाना नहीं चाहता।

श्री पी. राममूर्ति : मई के महीने में कितनी मात्रा भेजी गई है ?

श्री जगजीवन राम : मेरे पास आज तक के आंकड़े नहीं हैं।

श्री पी० राममूर्ति : क्या यह नहीं है कि 24 तारीख तक केवल 29,000 टन सप्लाई किये गये हैं जबकि वायदा 63,000 टन का था।

श्री अ. क. गोपालन---यह बहुत गम्भीर विषय है। मैंने स्वयं मंत्री महोदय को एक पत्र लिखा था और आंकड़े दिये थे। माननीय मंत्री को चाहिये था कि पूरी जानकारी लेकर आते। माननीय मंत्री को राज्य सरकार से जानकारी मंगानी चाहिये थी। मुझे पता चला है कि राज्य सरकार ने कुछ जानकारी भेजी भी थी। यहां पर गलत आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये जाने चाहिये। इन्होंने मेरे पत्र का उत्तर तक नहीं दिया।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम)---कुछ गलतफहमी हो गई है। यहां पर खाद्य निगम की जानकारी के अनुसार आंकड़े रखे जाते हैं।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) :—The hon. Minister should admit his mistake and own the responsibility for this.

I don't want that a particular officer should be blamed that he has done this thing. I am talking about the Minister and he should accept full responsibility,

Shri Jagjivan Ram : I accept full responsibility, These figures are in connection with the supplies from stocks of the Food Corporation to the fair price and other shops of the Kerala State.

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : जो चावल बांटा गया है उसमें भी 10,000 टन का अन्तर है। मंत्रालय ने प्रेस को बताया है कि 70,000 टन चावल केरल को दिया गया है जबकि वहां के मुख्य मंत्री ने कहा है कि 60,000 टन चावल दिया गया है। इस प्रकार गलत आंकड़े बताने का कारण क्या है।

श्री जगजीवन राम : यहां दो प्रकार के आंकड़ों का उल्लेख है। एक आंकड़े वे हैं जिनका सम्बन्ध केरल में पहुंच जाने वाले चावल से है दूसरे वे हैं जिनका सम्बन्ध यहां से भेजने से है। इन दोनों आंकड़ों में एक या दो हजार टन का अन्तर होना स्वाभाविक है **(व्यवधान)** फिर भी यदि आंकड़ों में कोई अन्तर है तो मैं इसके कारण का पता लगाऊंगा।

श्री राममूर्ति (मदुरै) : बात ऐसी नहीं जैसी मंत्री महोदय ने बताई है। वास्तव में जो 100,00 टन चावल स्टीमर द्वारा केरल पहुंचने वाला था उसे भी इन आंकड़ों में सम्मिलित कर लिया गया है। परन्तु केरल के खाद्य मंत्री ने केन्द्रीय खाद्य मंत्री को अपने पत्र में बताया था कि वह स्टीमर 5000 टन चावल उतार कर बम्बई को चला गया था। उन्होंने खाद्य मंत्रालय को कई बार तारें भेजीं कि सारा चावल कोचीन में उतार दिया जाये, परन्तु फिर भी ऐसा नहीं किया गया। मंत्री महोदय केवल खाद्य निगम पर आरोप नहीं लगा सकते। मंत्री महोदय ने जान बूझ कर सभा को भ्रम में रखा। 22 तारीख को इस सभा में कहा गया कि इस मास की 30 तारीख को 63000 टन चावल केरल पहुंच जायेगा परन्तु तीन दिन बाद राज्य सभा में इन्होंने कहा कि 63,000 टन नहीं, 60,000 टन और 27 तारीख को प्रेस को 50,000 टन की मात्रा बताई गई। क्या इन भ्रमोत्पादक आंकड़ों के लिए खाद्य निगम जिम्मेदार है ?

श्री जगजीवन राम : जहां तक 10,000 टन की मात्रा का सम्बन्ध है उसमें से 5,000 टन चावल ही गिना गया है **(व्यवधान)** जहां तक चावल भेजने का सम्बन्ध है वह आंध्र पर निर्भर है। दक्षिण खण्ड परिषद में आंध्र ने आश्वासन दिया था कि संभरण की मात्रा बढ़ा दी जायेगी। इसी आधार पर मैंने आशा व्यक्त की थी कि केरल को अधिक मात्रा में चावल भेजा जा सकेगा। मैंने यह कभी नहीं कहा कि यह चावल भेज दिया गया है।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : यह अजीब बात है कि कल्पना के आधार पर मंत्री महोदय ने इस सभा में वक्तव्य दिया जिसके कारण भ्रमपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है। मुख्य मंत्री ने अभी अगले दिन कहा है कि छः महीने की कालावधि में 80,000 टन कम अनाज मिला है। मन्त्री महोदय कहते हैं कि यदि आप आंकड़ों का सावधानी से अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि खाद्य निगम के सम्भरण से कमी पूरी हो जाने की आशा है। इस भ्रमपूर्ण स्थिति का कारण यह है कि केन्द्रीय सरकार हमें कुछ आंकड़े बताती है और मुख्य मंत्री कुछ

बताते हैं। ऐसी अवस्था में मन्त्री महोदय को चाहिये था कि वह अपने आप सभा को यह बताते कि उन्होंने केरल को चावल भेजने से सम्बन्धित जो आंकड़े सभा को बताये थे वह गलत प्रमाणित हुए हैं। परन्तु विरोधी दल को यह स्पष्टीकरण मांगना पड़ा, जो उचित नहीं है। इस समस्या का कुछ समाधान होना चाहिए।

श्री राममूर्ति : भारत सरकार के खाद्य मन्त्री इतनी बात नहीं समझ रहे कि खाद्य निगम को केवल देश में उपलब्ध अनाज का वितरण ही नहीं करना बल्कि बाहर से मंगवाये गये अनाज का भी वितरण करना है। उन्होंने 22 मई को यहां वक्तव्य दिया। हमने पूछा कि विदेशों से कितना अनाज मंगवाया गया है। केन्द्र सरकार ने 75,000 टन चावल प्रति मास केरल को देने का आश्वासन दिया था। इस बात की चर्चा यहां हो रही थी परन्तु हमारे खाद्य मन्त्री जैसे कुछ जानते ही नहीं या उन्हें यह मानना चाहिए कि वह सभा को भ्रम में डाल रहे हैं।

Shri K. N. Tiwari (Bettiah): When Central Government gives money for fertilizer and other irrigation facilities for increase in food output, is it not the responsibility of States to feed their own people? The Centre may, however, help them when consider necessary (Interruptions).

उपाध्यक्ष महोदय : इस बात का विचाराधीन चर्चा से कोई सम्बन्ध नहीं **(व्यवधान)**। यहां पर सम्भरण के आंकड़ों में गलती की चर्चा हो रही है **(व्यवधान)** सब माननीय सदस्य अपने अपने स्थान पर बैठ जायें। इस चर्चा पर बहुत समय लग गया है अब इस सम्बन्ध में और तर्क-वितर्क की आवश्यकता नहीं।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : अब यह स्पष्ट हो गया है कि मन्त्री महोदय ने जो बात 22 मई को कही थी, वह गलत थी। उन्होंने बताया कि खाद्य निगम ने कितना अनाज वसूल किया है या कितना वितरित किया है उसकी ठीक जानकारी उन्हें नहीं। केरल के मुख्य मन्त्री ने कहा है कि दिसम्बर से मई तक 3,94,059 टन चावल दिया जाना था जिसमें से 3,14,269 टन दिया गया है मुख्य मन्त्री का यह विवरण मैं सभा पटल पर रख सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रकार के विवरण खाद्य मन्त्री को भेज दिये जाने चाहिये ताकि वह उन्हें पढ़ लें। इन्हें सभा-पटल पर रखने की आवश्यकता नहीं।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं यह जानना चाहता हूं कि वह विवरण ठीक है या नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है।

श्री वेंगलराया नायडू (वित्तूर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। क्या हमें खाद्य मन्त्री के विवरण पर विश्वास करना चाहिये या किसी ऐसे व्यक्ति के विवरण पर, जिसका सम्बन्ध इस सभा के साथ नहीं है? **(व्यवधान)** यदि यह चलता रहा तो आन्ध्र से और चावल नहीं मिलेगा। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपने मुख्य मन्त्री की बात कह कर उसका स्पष्टीकरण केन्द्रीय खाद्य मन्त्री से माँग सकते हैं।

श्री तन्नेटि विश्वानाथम (विशाखापतनम) : अभी अभी आन्ध्र के एक माननीय सदस्य ने कहा था कि यदि ऐसा चलता रहा तो आन्ध्र से केरल को चावल नहीं मिलेगा। क्या मैंने यह ठीक ही सुना था ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह उनके व्यक्तिगत विचार हैं।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर : दो सप्ताह पूर्व आन्ध्र सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा था कि केरल का उचित रवैया न होने के कारण केरल को प्राथमिकता नहीं दी जायेगी। हम किसी से चावल मांगने नहीं जाते। यदि आप चावल नहीं दे सकते तो आप हमें विदेशी मुद्रा दीजिये हम बाहर से चावल मंगवा लेंगे।

श्री जगजीवन राम : जहां तक आंकड़ों का सम्बन्ध है मैं केरल राज्य के मुख्य मंत्री अथवा खाद्य मंत्री द्वारा दिये गये आंकड़ों को मान लेता हूँ और मैं केरल में जितना चावल पहुंचा है, उस से सम्बन्धित अपने आंकड़ों को उनके आंकड़ों से मिला कर देखूंगा।

जहां तक आंध्र का सम्बन्ध है हम हर सम्भव प्रयास करेंगे कि आन्ध्र हमें केरल को देने के लिए 6 लाख टन चावल देने का अपना वचन पूरा करे।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम) : आन्ध्र प्रदेश अन्य राज्यों की सहायता के लिए सदा तत्पर रहा है। इसलिए इस सम्बन्ध में कोई गलत फ़हमी नहीं होनी चाहिये।

समितियों के लिये निर्वाचन

ELECTIONS TO COMMITTEE

(एक) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के नियमों के नियम 3 (13) के अनुसरण में, लोक सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निर्देश दें, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से चार सदस्य चुने।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के नियमों के नियम 3 (13) के अनुसरण में, लोक सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से चार सदस्य चुने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

(दो) राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : श्री वी० के० आर० वी० राव की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि व्यापारिक नौवहन अधिनियम, 1958 की धारा 4 की उपधारा (2) (क) के अनुसरण में, लोक सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, 8 जून 1967 से पुनर्गठित किये जाने वाले राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से चार सदस्य चुने।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि व्यापारिक नौवहन अधिनियम 1958 की धारा 4 की उपधारा (2) (क) के अनुसरण में, लोक सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, 8 जून, 1967 से पुनर्गठित किये जाने वाले राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से चार सदस्य चुने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

(तीन) राष्ट्रीय खाद्य तथा कृषि संगठन सम्पर्क समिति

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अण्णासाहिब शिन्दे) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय के दिनांक 9 सितम्बर, 1966 के संकल्प संख्या एफ-10—1/5 एफ० ए० आई टी, बाद में संशोधन किये गये रूप में, के अनुसरण में, लोक सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए तीन वर्ष की अवधि के लिये राष्ट्रीय खाद्य तथा कृषि संगठन सम्पर्क समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से चार सदस्य चुने।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय के दिनांक 9 सितम्बर, 1966 के संकल्प संख्या एफ—10-1-5 एफ० ए० आई टी, बाद में संशोधन किये गये रूप में, के अनुसरण में, लोक सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए तीन वर्ष की अवधि के लिये राष्ट्रीय खाद्य तथा कृषि संगठन सम्पर्क समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से चार सदस्य चुने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted,

रेलवे आयव्ययक—सामान्य चर्चा (जारी) :

RAILWAY BUDGET—GENERAL DISCUSSION (CONTD.)

उपाध्यक्ष महोदय : अब फिर रेलवे आय व्ययक सम्बन्धी सामान्य चर्चा होगी।

Shri A. B. Vajpayee (बलरामपुर) : This is the first deficit budget presented by the Minister of Railways during the last 25 years, and the reason for the deficit has

been attributed to fall in the quantity of goods transported by the Railways. The quantity of goods to be transported fall by 80 lakh tons as compared to the estimate. But who is responsible for this estimate ? Why the common man should suffer for the fault of the Government. There is competition between the Railways and road transport and the Railways are logging behind. People prefer road transport to Railways irrespective of the fact that road transport is more costly. The reason for this preference is that the goods do not spoil on their way and they also reach their destination in time. When Railways take more time and goods are also not safe, who would like to make use of Railways ? It has been claimed that there has been improvement in the running of trains, but the fact remains that the trains neither leave at correct time nor arrive at time. The Station Masters, Controllers and other officers have different charts of timings. This is a serious thing and I can prove these allegations. This House and the country is being misled. The correct time at which the train arrives at a particular station is not shown in the chart maintained by the controller. I would also suggest that an enquiry should be held so as to find out whether there was shortage of wagons or shortage of goods.

The businessmen do not get the number of wagons they require. The wagons supplied to them are in desperate condition. I want the figures pertaining to the number of wagons required and the number of wagons which are not in working condition. I do not agree with the Hon'ble Minister that the reason of deficit budget is fall in the quantity of goods for transportation. There must be other factors responsible for deficit budget. There are different divisions of Railways and there is tussle between them and the businessmen suffer. The result thereof is that they prefer road transport.

The Railway Minister has claimed that there is fall in the number of Railway accidents during the year 1965-66. May I know the reason of accidents ? I want to say that many accidents could bo avoided. Whenever there is discussion over any accident, the Railway Minister says that the same has taken place due to the failure of human element and the responsibility of accidents is fixed on the employees of Railways. But why should Government not create such conditions under which the Railway staff could perform their duties more effectively. Is it not the responsibility of Ministry of Railways to provide such facilities to its staff ? Had the Railway staff been responsible for railway accidents, the number of accidents would have been very high at the time when the Station Masters had resorted to work to rule campaign from 1st December to 21st December but there was not a single accident during the aforesaid period. In fact accidents take place only when higher officers compell the lower staff to use short cut methods and violate the rules. When the trains are not inspected properly, the accidents take place. In order to prevent the accidents, the lower staff has got to be taken into confidence. The accidents cannot be prevented merely by creation of a huge Safety Organisation or the appointment of a Safety Inspector. Crores of rupees are spent on publicity relating to safety of Railway trains but no one bothers about the working conditions of Railway staff. It was promised by the former Railway Minister that no one will be penalised for his participation for his taking part in 'work to rule, campaign but three officers of Danapur Division are still under suspension and they have not been called back to their duties. Transfers of staff have also not yet been cancelled and thousands of Station Masters have been charge-

[श्री बलराज मधोक पीठासीन हुए
Shri Balraj Madhok in the chair]

sheeted. These charge-sheets have not been taken back. Railway Ministry do not seem to be anxious to fulfil the assurance given by its former Railway Ministers. If the

above assurance is above not implemented we will have to adopt other methods. I am in favour of peace and discipline but at the same time I cannot keep silent if injustice is done to any Railway employee.

There should be good relations between employees and the Railway Department. The Hon'ble Minister has claimed that they have good relations with the all India organisations but what would happen to the employees who are not included in the said organisation.

Unions on the basis of categorywise should be recognised in the railways and a confederation of all these unions should be formed as has been done in the Post and Telegraph.

There is no justification in increasing the railway fare and freight· This should be withdrawn. This could have been done easily by reducing the share of railways in the revenue. The officials of the railways should be deprived of the right of writing off the demurage to the big companies. In this way crores of rupees can be collected.

Three hundred employees were suspended in Kolar division but were taken afterwards on a simple warning. This system of suspension and of serving charge-sheets to the emyloyees should be stopped. This spreads discontentment among the staff.

A thorough enquiry should be made whether security organisations should be continued or not. In my view these should be done away with as the accidents are still on increase.

Saloon facilities should not be provided to the railway officials. They should be treated at par with their counterparts in other ministries.

श्री कृष्णकुमार चटर्जी (हावड़ा) : यद्यपि बजट में प्रस्तुत प्रस्तावों का मैं समर्थन करता हूँ तथापि इसमे निहित सिद्धांतों का मैं पूरी तरह समर्थन नहीं कर सकता। अन्तरिम बजट के पेश किये जाने के बाद से स्थिति बिगड़ती ही जा रही है।

परिस्थितयों को देखते हुए किराये तथा माल भाड़े में वृद्धि करने के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं था। बजट को संतुलित करने का यही एक तरीका था।

घाटे का मुख्य कारण यह है कि रेलवे द्वारा माल की ढुलाई में कमी हुई है। गत वर्ष रेलवे द्वारा केवल 200·5 मिलियन टन माल की ढुलाई की गई जबकि अनुमान 245 मिलियन टन माल की ढुलाई करने का था। 1966–67 में यातायात में कमी से भी रेलवे को कम आय हुई है। यदि किराये बढ़ाने का यही कारण है तो किरायों में वृद्धि से यातायात में और कमी हो जायेगी। रेलवे गलत योजना तथा गलत विनिधान का एक स्पष्ट उदाहरण है।

रेलवे मंत्री ने कहा है कि रेलवे में और अधिक विनिधान नहीं किया जायेगा। मेरा निवेदन यह है कि वह दूरदर्शिता तथा ठीक योजना से काम लें क्योंकि बहुत से उद्योग रेलवे के आर्डरों पर ही निर्भर हैं। यदि उनको रेलवे के आर्डर नहीं मिले तो उनकी अर्थ व्यवस्था अस्तव्यस्त हो जायेगी।

यह बड़े दुःख की बात है कि प्रशासन के मामले में हम आजादी के बाद भी वही पुरानी प्रणाली अपना रहे हैं। उसको एक नया रूप देने की आवश्यकता है। रेलवे बोर्ड एक बेकार का

निकाय है। इसको समाप्त करके इसका काम करने के लिए मंत्रालय में एक विभाग खोला जा सकता है।

पूर्वी रेलवे के सांख्यिकीय विभाग में कर्मचारियों के पदोन्नति के मामले में बहुत सी अनियमिततायें बरती गई हैं। कलकत्ते में बंगाली भाषा के एक प्रमुख पत्र ने इन अनियमितताओं का उल्लेख किया है। फरीदाबाद में आई० बी० एम० प्रशिक्षण के लिए चुनाव में मनमानी बरती जाती है। वास्तव में रेलवे बोर्ड के आदेशानुसार मशीन अनुभाग से सम्बन्धित कर्मचारियों को ही प्रशिक्षण के लिए भेजा जाना चाहिये। परन्तु इस मशीन अनुभाग में काम न करने वाले जुनियर कर्मचारियों को फरीदाबाद में इस प्रशिक्षण के लिए भेजा और बाद में उनको वरिष्ठ अधिकारियों के उपर सुपरवाइजर लगा दिया गया।

1958 में जब उत्तर-पूर्वी रेलवे के मुख्यालय को गोरखपुर ले जाया गया था तो रेलवे बोर्ड ने यह अनुदेश दिया था कि जो लोग गोरखपुर जाने से इन्कार करें उनको पूर्वी तथा दक्षिण रेलवे में ही लगाया जाये। उस समय उनको नियमित सवंर्गो में नहीं लगाया गया था परन्तु उनको धीरे धीरे नियमित संवर्ग देने को कहा गया था। परन्तु आठ वर्ष का समय गुजर जाने के पश्चात् भी रेलवे बोर्ड के आदेशों को कार्यान्वित नहीं किया गया है। 1956 में जो ड्राफ्टमैन। एस्टिमेटर्स नियुक्त किये गये थे उन्हें वरिष्ठता के सभी अधिकारों से वंचित रखा गया है।

मन्त्री महोदय को प्रशासन में नये सिरे से सुधार लाने के बारे में सोचना चाहिए। जब तक प्रशासन के व्यय में कमी नहीं होती तब तक किराये तथा माल भाड़े को बढ़ाने के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है और लोगों की कठिनाइयां ज्यूं कि त्यूं बनी रहेंगी।

Shri Ram Charan (Khurja) : All the public undertakings are running into loss and railway is no exception.

As the hon. Minister has stated that the deficit has occurred because the movement of goods has slowed down and also because the cost of material and maintenance has gone up. I would say that shortfall in the movement of goods through railways is due to the insecurity which prevails in the railways to-day. People prefer road transport than the railways.Moreover railways have to pay huge amounts in compensation.

Fifty percent of the money spent on the maintenance in the railways is wasted. There is too much extravagance in the electric, mechanical and civil departments of the railways. Most of the people performed ticketless travel on the branch lines, because there are arrangements for the safety of ticket-checkers. With more vigilance and proper care in the maintenance expenditure this deficit can be made good.

A shuttle train running between Gaziabad and Delhi should be extended to Aligarh. This will provide more convenience to the businessmen and other daily comers and goers and the railway income will also increase.

Dearness allowance of the railway employees should be attached to the cost index. House rent allowance should also be given to the employees who have not been provided housing accommodation. All other facilities such as of education and medical should be provided to the railway employees.

The main reason for the railway accidents is that the concerned employees are not paying full attention to their duties. The higher officers put the burden on the junior officers which are not capable of holding the responsibility. Some concrete steps should be taken in this regard to avoid the accidents. A huge quantity of coal is wasted in the loco sheds. This coal is sold in the market. With little more vigilance this wastage can be avoided. In this matter I shall suggest that people from outside should do the vigilance work.

Deficit in the budget can be made good by increasing the efficiency of the administration. Security arrangements should be increased alongwith the increase in fare and freight.

श्री न० कु० सांघी (जोधपुर) : इस बजट से लोगों को बहुत निराशा हुई है। खर्च में वृद्धि हुई है और माल की ढुलाई में कमी होने के कारण आय कम हुई है। बजट को संतुलित बनाने के लिए किराये तथा माल भाड़े में वृद्धि करनी पड़ी है। इससे स्पष्ट है कि रेलवे में गतिशीलता का अभाव है। पिछले 20 वर्षों से रेलवे के कार्य की आलोचना की जा रही है। भ्रष्टाचार, माल की चोरी तथा तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिए सुविधाओं के अभाव का उल्लेख किया गया है। परन्तु स्थिति में सुधार करने के लिये कुछ भी नहीं किया गया है। मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि संसद सदस्यों को रेलवे मंत्रालय द्वारा फर्स्ट क्लास का पास दे दिया गया है जिस कारण तीसरे दर्जे के यात्रियों की कठिनाइयां वैसे ही बनी हुई है। इस बजट से तीसरे दर्जे के यात्रियों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। उनकी समस्याओं को सुलझाने की ओर रेलवे प्रशासन को तुरन्त ध्यान देना चाहिये। राजस्थान मे नई लाइनें नहीं बिछाई गई हैं। इस क्षेत्र में माल तथा यात्री यातायात बहुत धीमा है। उदयपुर से जोधपुर आने में 16 घन्टे लगते हैं। यह फासला केवल 295 किलोमीटर है। इसको तेज किया जाना चाहिये और नई लाइनों का विकास किया जाना चाहिये।

जोधपुर के पत्थर के कारखाने से राजस्थान के सभी स्टेशनों को पत्थर भेजा जाता है। परन्तु मालगाड़ी के डिब्बों के अभाव के कारण उनके यातायात में बाधा पड़ गई है। माल डिब्बों की सप्लाई को बढ़ाया जाना चाहिये इससे रेलवे की आय में भी वृद्धि होगी।

गत अनेक वर्षों से राजस्थान में अकाल की स्थिति है। लोगों को पानी सप्लाई करने की कोई व्यवस्था नहीं है। रेलवे में पानी ले जाने वालों टैंकों की कमी है। ऐसे पानी ले जाने वाले टैंकों की तुरन्त व्यवस्था की जानी चाहिये।

राजस्थान एक सीमावर्ती राज्य है क्योंकि इसकी सीमा पाकिस्तान से मिलती है। भारत-पाक संघर्ष के दौरान राजस्थान को संघर्ष का पर्याप्त बोझ वहन करना पड़ा था। तभी 1965 में पोकरन से जेसलमेर तक रेलवे लाइन बिछाने की बात पर रेलवे प्रशासन द्वारा विचार किया गया। परन्तु संघर्ष की समाप्ति के पश्चात इस ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। देश की रक्षा को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में रेलवे लाइनों का बिछाया जाना आवश्यक है।

राजस्थान नहर का कार्य पर्याप्त प्रगति कर रहा है। केन्द्रीय सरकार इस पर काफी धन व्यय कर रही है परन्तु दुःख की बात है कि नहर के साथ साथ रेल बिछाने की कोई व्यवस्था

नहीं की गई है। इस ओर कार्यवाही करने के लिए वर्तमान समय उचित है। विमान यातायात पर अधिक जोर देने की अपेक्षा हमें रेलवे में गतिशीलता लाने पर अधिक जोर देना चाहिये। संसार भर के आंकड़ों के देखने से यह सिद्ध हो जाता है कि गाड़ियों की गति को तेज करने से दुर्घटनाएं भी कम होती है। इससे रेलवे प्रशासन को बचत भी अधिक होगी क्योंकि संचालन का समय कम हो जाता है।

रेलवे प्लेटफार्मों से माल को हटाया जाना चाहिए। इससे यात्रियों को बहुत असुविधा होती है।

* **श्री सामिनाथन** (गोबीचेट्टिपलयम) : रेलवे आयव्ययक सभी पहलुओं से बहुत निराशा-जनक है, इससे जनसाधारण पर बहुत बोझ पड़ता है और यह आयव्ययक जनता विरोधी हैं। पिछले वर्ष रेलों के भाड़े में आने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर वृद्धि नहीं की गई थी परन्तु इस वर्ष सभी भाड़ों में वृद्धि की गई है और तीसरे दर्जे के यात्री भी इससे नहीं बच पाये हैं। रेलवे, यात्रियों की सुविधाओं की ओर ध्यान दिये बिना जनता पर अधिक बोझा डालती जा रही है।

रेलों में भीड़ भाड़ में बहुत वृद्धि हो रही है और भीड़ भाड़ इतनी है कि एक गाड़ी में दो गाड़ियों जितने यात्री यात्रा करते हैं। यात्री किरायों तथा भाड़ा की दरों में वृद्धि से रेलवे को 38 करोड़ रुपये की अधिक आय होगी परन्तु कुल मुनाफा केवल 1.28 करोड़ रुपये दिखाया गया है। इससे जनता में रेलों की क्रियान्विति के प्रति विश्वास नहीं हो सकता। यह खेद की बात है कि तीसरे दर्जे के यात्रियों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। यदि भाड़ों की विदेशों में भाड़ों से तुलना की जाती है, तो उन देशों में तीसरे दर्जे के यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं से भी हमारे यहां की सुविधाओं की तुलना की जानी चाहिये।

रेलवे में स्थान सुरक्षित कराने के लिए लोगों को कई दिनों तक स्टेशन पर जाना पड़ता है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के 20 वर्ष बाद भी स्थिति यही है। रेलवे की डाईनिंग कारों में मांसाहारी तथा शाकाहारी भोजनों के दामों में वृद्धि कर दी गई है। भोजन पहले की तुलना में अच्छा नहीं है। रेलवे मंत्री को सभा को बताना चाहिये कि इस वृद्धि का कारण क्या है। मैं रेलवे मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस महत्वपूर्ण पहलू पर विचार करें और देखें कि रेलें ऐसा कोई कार्य न करें जिससे मूल्यों में वृद्धि हो। मद्रास में द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम की सरकार ने चावल के मूल्य में कमी कर दी है। यदि मद्रास में ऐसा किया जा सकता है तो रेलों का भोजन के मूल्य में वृद्धि करना, विशेषतया मद्रास राज्य मे, बिलकुल उचित नहीं है।

चौथी पंचवर्षीय योजना में तमिलनाड के लिए सलेम–बंगलौर लाइन के अतिरिक्त कोई लाइन नहीं रखी गई है। पिछले दस वर्षों से भी अधिक समय से जनता इस बात की बलपूर्वक मांग कर रही है कि सत्यमंगलम तथा गोबीचेट्टिपलयम से होकर ईरोड से मैसूर राज्य में चामराजगर तक रेलवे लाईन बनाई जाये। यह नई योजना निश्चय ही वित्तीय दृष्टि से भी

* मूल तामिल के अंग्रेजी अनुवाद से अनूदित
English translation of speech delivered in Tamil.

लाभप्रद होगी । इस लाइन के अतिरिक्त अन्य लाइनें खोलने के प्रस्ताव भी हैं । मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह मेरे सुझावों पर विचार करें और उन्हें यथासम्भव शीघ्र क्रियान्वित करें ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Deputy–Speaker in the chair.]

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to submit that there were no reporters to record the speech of hon. Member, who spoke just now. There should be reporters in all the languages.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का भाषण टेप रिकार्ड कर लिया गया है ।

Shri Hem Raj (Kangra) : There is no doubt that the Railway Minister has made every effort to make this budget a balanced budget, but I feel he would not have faced all this difficulty if he had looked into the working of railway administration. If there had been better planning in railway administration, this rise in railway fares and freights could have been avoided. There is no punctuality of trains. Ticketless travel is on the increase. The claims of the Railways are also mounting. The theft of coal on the railways is going on a large scale. If all these things are looked into and improved upon, the income of railways will go very high and there will be no necessity of increase in fares and freights.

Three types of police organisations are working on the railways. There is civil police. There is also railway police and the third is Railway Protection Force. The three wings lack co-ordination, and as a consequence, theft is going on. The worst part of it is that the railway employees themselves indulge in theft. This should be stopped.

The Kunzru Committee has recommended that the narrow guage lines should be closed since their performance is not satisfactory. The Government have accepted this recommendation but it has not been implemented. The lines which are to be closed, should be closed forthwith. The performance of other lines should be improved upon.

I endorse the point made by the Member, who spoke before me that the railway saloons should be discontinued. If they are discontinued, the passengers will be able to get more accommodation on the railways. The officers travelling by saloons can travel by first class.

The largest proportion of railway income accrues from third class passangers. In spite of that, fair of third class has been enhanced.

There are only two narrow guage railway lines in Himachal Pradesh. One of them, namely Kangra Valley line, should be converted into broad guage. Paonta should be connected with Jagadhri or Dehradun by a broad guage line. Nangal-Una line has already been surveyed. The work on that line should be taken in hand. Arrangements for water should be made on the railway stations in our area, particularly Jawalamukhi road station, where a large fair is held.

There should be a railway out-agency in Kulu valley. The fruits grow in abundance in that valley and they are despatched to every part of the country. An out-agency was sanctioned for the despatch of fruits but it has not yet started functioning. I urge the hon Minister to expedite the matter.

श्री दत्तात्रय कुंटे (कोलाबा) : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कोई रेलवे लाईन नहीं है। यह निर्वाचन क्षेत्र बम्बई नगर के बिलकुल निकट है। पश्चिमी घाट पर बम्बई तथा मारमागोआ जैसे सुन्दर पत्तन है। बम्बई तथा मंगलौर के बीच कोई रेल सम्पर्क नहीं है। इससे यात्रियों को बहुत कठिनाई होती है। इन दोनों स्थानों के बीच का अन्तर 350 मील से अधिक नहीं है परन्तु कोई सीधा मार्ग न होने के कारण यात्रियों को बहुत घूम कर आना पड़ता है। इसके अतिरिक्त उस क्षेत्र में बहुत खनिज होते हैं। जिनका निर्यात किया जाता है, इन खनिजों का निर्यात करने के लिए पत्तनों के विकास पर बहुत राशि व्यय की जाती है परन्तु उनका ठीक प्रकार से प्रयोग नहीं किया जा सकता जब तक उन्हें रेलवे लाइन से न जोड़ा जाये। मेरे विचार में माननीय मंत्री बंगलोर क्षेत्र के बारे में मुझ से अधिक जानते हैं।

इसलिए, बम्बई तथा मंगलौर को मिलाने वाली लाइन के निर्माण यथासम्भव शीघ्र हाथ में लिया जाना चाहिये। यदि किसी एक पत्तन पर काम अधिक हो तो यदि रेलवे सुविधायें उपलब्ध हों तो माल दूसरे पत्तन पर उतारा जा सकता है और वहां से रेल द्वारा भेजा जा सकता है।

एक और बात को ध्यान में रखना होगा। बम्बई अदन के पूर्व में नहीं है बल्कि उसके उत्तर-पूर्व में है। अदन के पूर्व में मारमागाओ तथा मंगलौर हैं। यदि इन पत्तनों को जोड़ने वाले रेलवे लाइन बनाई जाये तो उस क्षेत्र को अधिक अच्छा विकास हो सकता है। रेलवे को इस ओर यथासम्भव शीघ्र ध्यान देना चाहिये।

मराठवाड़ा क्षेत्र के विकास के लिये वहां पर बड़ी लाईनें बिछाई जानी चाहिये। पन्डरपुर जाने वाले यात्रियों के लिये सवारी गाड़ियों की व्यवस्था की जानी चाहिये। अब उन्हें माल डिब्बों में जाना पड़ता है। रेलवे की यात्रा को लोकप्रिय बनाने के लिये सरकार को किराये तथा भाड़े में वृद्धि नहीं करनी चाहिये थी। इस वृद्धि से सड़क परिवहन वाले लाभ उठायेंगे। सरकार किराया बढ़ाने जा रही है परन्तु इसके साथ जनता के लिये सुविधाएं भी बढ़ाई जानी चाहिये। आजकल गाडियों में बहुत भीड़ होती है। इस बारे में कुछ कदम उठाये जाने चाहिये।

रेलवे को जनता की सेवा अपना मुख्य उद्देश्य समझना चाहिये और एक वाणिज्यक संस्था के रूप में कार्य नहीं करना चाहिये। रेलवे मंत्री को वित्त मंत्री को स्पष्ट रूप से बता देना चाहिये था कि रेल के किराया तथा भाड़ा बढ़ाया नहीं जा सकता। अब तो मूल्यों में और वृद्धि होने की आशंका है। क्या किरायों तथा भाड़ों की वृद्धि से लाभ होगा ? माननीय मंत्री अभी अभी रेलवे मंत्री बने हैं। उन्हें कम से कम दो वर्ष तक किराये नहीं बढ़ाने चाहिये। रेलवे में अधिकारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इससे व्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। बड़े बड़े अधिकारियों के लिये सैलून नहीं होने चाहिये।

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि रेलवे लाइनों के समीप की भूमि को कृषि के उद्देश्य के लिए प्रयोग में लाया जाना चाहिये। ऐसी भूमि का क्षेत्र लगभग 90,000 एकड़ है। इसमें से 42,000 एकड़ भूमि पहले ही राज्य सरकारों को सौंप दी गई है ताकि कृषि के काम में लायी जा सके। शेष भूमि के बारे में भी बातचीत चल रही है। इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि करने में सहायता मिलेगी।

बेंगेल स्टेशन के स्थानान्तरण को जनता की सुविधा को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। इस बारे में बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं परन्तु हमने सभी पहलुओं पर विचार कर लिया है। हल्दिया बन्दरगाह के यातायात का भी ध्यान रखना था। हमें जनहित सर्वोपरि समझना चाहिये।

श्री बिस्वास ने मांग की है कि रेल कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में तुरन्त वृद्धि कर दी जाये और गजेन्द्रगाडकर आयोग की रिपोर्ट की प्रतीक्षा न की जाये। परन्तु ऐसा करना उचित नहीं होगा। हमें इस उच्च शक्ति प्राप्त आयोग की सिफारिशों के जानने के बाद निर्णय करना चाहिये। आकस्मिक मजदूरों के बारे में कहना चाहता हूं कि वे दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जिन्हें किसी परियोजना में कार्य पर लगाया जाता है और दूसरे वे जिन्हें कुछ अधिक अवधि के लिए रखा जाता है। दूसरी श्रेणी वालों को एक नियत समय के बाद अतिरिक्त सुविधायें दे दी जाती है।

यहां पर यह भी कहा गया है कि गार्डों को ड्राइवरों से अधिक वेतन मिलना चाहिये। क्योंकि पहले ऐसा ही था। मेरे विचार में यह ठीक नहीं। ड्राइवरों को सदैव गार्डों से अधिक वेतन मिलता रहा है।

रेलवे अपनी आवश्यकता का कोयला कोयला नियंत्रक द्वारा निर्धारित दरों पर ही खरीदती है। जब किसी विशेष प्रकार के कोयले की आवश्यकता होती है उस समय टेन्डर द्वारा कोयला खरीदा जाता है। ऐसे कोयले के लिये अधिकतम मूल्य भी निर्धारित कर दिया जाता है। अतः जो आरोप लगाये गये हैं वे निराधार हैं।

रेलवे प्रशासन द्वारा माल के डिब्बों के आर्डर में कमी के कारण यह भावना फैल गई है कि कुछ उद्योगों में, मुख्यतः कलकत्ता क्षेत्र में मन्दा आ जायेगा। हां, यह ठीक है कि चार पहिये के डिब्बों में कुछ कमी हुई है परन्तु इसके बावजूद भी जिन उद्योगों को ये आर्डर दिये गये थे वे उन माल गाड़ी के डिब्बों को भी नहीं भेज सके।

सैलूनों के बारे में एक प्रकार का भ्रम फैल गया है। कुछ लोग निरीक्षण कोचों को भी सैलून समझने लगे हैं। जब अधिकारी लोग कार्य पर बाहर जाते हैं तो वे सैलून या निरीक्षण कोच में जाते हैं।

Shri Raghuvir Singh Shastri (Baghpat) : I want to express concern over the conditions of S. S. Light Railway which is called Shahdara Saharanpur Light Railway. The trains run very slow on this line and they are always late. The speed of these trains is 13 miles per hour only. The Express trains take seven hours to cover 92 miles from Shahdara to Saharanpur and the passenger trains take ten hours.

While the villagers have changed the outlook of their villages altogether with their own efforts, but there is no change in S. S. Light Railways. The bogies and the engines used are very old ones. Even after 20 years independence this is the state of affairs of my constituency. This Railway is owned by Martin Burn and Company. An amount of Rs. 27 lakhs was invested in this Railway in 1907 and a sum of Rs. 15 lakhs was collected by public shares. This company also secured a loan of 2 lakh pounds

from some agency in London on which an interest of Rs. 1,25,550 is being paid annually since then.

In accordance with one of provisions of agreement entered into with this company, after the payment of interest and deduction of 4% of the profit, the 50% of remaining profit is required to be given to Government of India. But since 1958 not a single penny has been given to the Government of India. Thousands of acres of land is being used by this Railway without paying any revenue to the Government.

In one of the clauses of the said agreement it has been mentioned that if Government wants to take over this Railway, Government has to pay 25 times of three years profit or 125 times of its cost. As this Railway has not been showing any profit for the last eight to nine years, it is high time for the Government to take over this Railway. This is the only Railway which does not contribute anything towards general revenues. The pay and allowance of the General Manager of this railway is much higher than the General Manager of Northern Railway.

The bogies and engines are in very desperate conditions. There is always great rush in these trains. The safety aspect of this Railways also needs attention. There is no level crossing on this Railway. The facilities of transportation of goods are quite negligible. The staff of this Railway is paid very low and their service conditions are very poor.

This Railway will now increase its fares on the same lines it has been done by the other Railways but they have neither to pay higher salaries to their staff nor to provide any additional facilities for the people. In view of this I would request the Government to take over this Railway so that people of this area may get rid of this constant trouble. Till such time, the Government should have control over the budget of this Railway and an Advisory Committee should also be appointed who could make suggestion for its improvement; A High-power commission should be appointed by the Government to enquire into the cases of irregularities and corruption and necessary measures should be taken to remove our difficulties on the recommendations of that Commission.

श्री चंगलराया नायडू (चित्तूर) : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 21 तारीख को एक भयानक दुर्घटना हुई। यह दुर्घटना लापरवाही के कारण हुई। बंगलौर से गाड़ी जब चली तो रास्ते में ड्राइवर ने देखा कि वैक्यूम ब्रेक ठीक काम नहीं कर रही। परन्तु वह उसे ठीक करने में असफल रहा, क्योंकि ब्रेक ठीक करने के औजार उसके पास नहीं थे। उसने रास्ते में भी ब्रेक ठीक करने का सामान प्राप्त करना चाहा परन्तु उसे नहीं मिला। दुर्घटना के समय गाड़ी की रफतार 60 मील प्रति घण्टा थी और ड्राइवर मकैनिकल ब्रेक लगाने में भी असफल रहा। जिस समय ड्राइवर को यह पता चल जाता है कि अब दुर्घटना होने वाली है तो वह बिना यात्रियों की परवाह किये गाड़ी से कूद जाता है और बच जाता है। इस दुर्घटना में काफी लोग हताहत हुए। यात्रियों के बचाव के लिये रेलवे के पास कोई व्यवस्था नहीं थी। मृतकों अथवा कुचले जा रहे व्यक्तियों को बाहिर निकालने की भी कोई व्यवस्था नहीं थी।

पहले इन्जन के पीछे सामान वाले डिब्बे लगाये जाते थे परन्तु अब यात्रियों वाले डिब्बे लगाये जाते हैं जिसके फलस्वरूप अधिक लोग हताहत होते हैं। वास्तव में अब भी इन्जन के पीछे कुछ सामान वाले डिब्बे लगाये जाने चाहिये जिससे जन हानि अधिक न हो। मैं मन्त्री महोदय से

निवेदन करता हूँ कि वह ऐसे नियम बनाये जिनके अनुसार ऐसी दुर्घटना होने पर रेलवे बोर्ड के सदस्य को त्याग-पत्र देना पड़े नहीं तो उसे नौकरी से हटा दिया जाये। मेरे विचार में रेल-यात्रा से पूर्व यात्रियों का बीमा होना चाहिये क्योंकि आजकल दुर्घटनायें बहुत अधिक हो रही है। इस बीमे का खर्च का भार रेलवे विभाग को उठाना चाहिये। आजकल रेल यात्रा की अपेक्षा हवाई-जहाज की यात्रा अधिक सुरक्षित है।

मैं रेलवे मन्त्री से प्रार्थना करता हूँ कि वह तीसरे दर्जे के यात्रियों से अधिक किराया न लें। तीसरे दर्जे के डिब्बों में यात्रा करने वालों की सुविधाओं में कोई सुधार नहीं हुआ। प्लेटफार्मों पर बहुत गंदगी होती है ऐसा लगता है जैसे वे पशुओं के रहने के स्थान हों। तीसरे दर्जे के प्रतीक्षालयों में शौचालय तो बहुत ही गन्दे होते हैं। भोजनालयों की कोई उचित व्यवस्था नहीं, वहां गला-सड़ा खाना दिया जाता है। इन सब कठिनाइयों को दूर करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिये। रेलवे की स्थिति को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि आज बीस या तीस वर्ष पूर्व रेलवे की स्थिति अधिक अच्छी थी। राष्ट्रीयकरण के पश्चात इसकी स्थिति बहुत बिगड़ गई है। ठीक प्रकार से पर्यवेक्षण निरीक्षण के लिये रेलवे बोर्ड को समाप्त कर इसके स्थान पर कोई और व्यवस्था की जानी चाहिये। अधिकारियों के लिये विशेष डिब्बों को लगाने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि उच्च अधिकारी तो प्रथम दर्जे के डिब्बे में सफर कर सकते हैं विशेषकर जब वे तीसरे दर्जे के यात्रियों को आवश्यक सुविधायें देने की व्यवस्था नहीं कर सकते।

रेलवे विभाग राजामुन्दरी में रेल पुल के ऊपर सड़क पुल की व्यवस्था करने के लिये सहमत हो गया है। परन्तु वह इस पुल की 15 फुट चौड़ाई चाहते हैं जो बिल्कुल अपर्याप्त है। मेरे विचार में इसकी चौड़ाई 20 से 25 फुट तक होनी चाहिये।

कोठागडम के पास कोयले की खाने हैं। माल-डिब्बे न मिलने के कारण यहां उत्पादन घटा कर आधा कर दिया गया है। सब जगह कोयले की कमी है परन्तु रेलवे उक्त स्थान से कोयला ढो नहीं पा रही है। इस समय कोयला ढोने का दर 40 किलो मीटर तक की दूरी के लिये 6 रु० 16 पैसे प्रति टन है। परन्तु रेलवे विभाग 6 या 7 मील की दूरी के लिये भी, जहां यह स्थान है, उतना ही भाड़ा वसूल करता है जो अनुचित है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि यह भाड़ा 6 या 7 मील की दूरी के लिये ही लिया जाये।

श्री अजमल खां (पेरियाकुलम) : रेलवे के किराये बढ़ाने के स्थान पर और ऐसे बहुत से अन्य उपाय अपनाये जा सकते थे जिनसे रेलवे की आय बढ़ सकती थी। तीसरे दर्जे के किराये तो बिलकुल नहीं बढ़ाए जाये जाने चाहियें क्योंकि इस दर्जे के यात्रियों की स्थिति बहुत अधिक शोचनीय है। इसके साथ ही अब दुर्घटनाओं के खतरे अधिक बढ़ गये हैं। ऐसे समय में जब आवश्यक वस्तुओं के दरों में वृद्धि के कारण जनता पहले ही बहुत दुःखी है, माल-भाड़े की दर में वृद्धि करना अन्याय होगा। किराये बढ़ाने के स्थान पर यदि रेलवे वाणिज्यिक क्षमता वाले क्षेत्रों में नई रेलवे लाइने बिछाने पर विचार करे तो उससे अत्यधिक आय हो सकती है। उदाहरण के लिये मदुरै जिले में डिण्डीगुल-गुडालुर लाइन की व्यवस्था की जानी चाहिये। इससे सरकार को अत्यधिक राजस्व मिलेगा और केरल और मद्रास में भी सीधा सम्पर्क स्थापित हो सकेगा।

Shrimati Savitri Shyam (Aonla) : There has been alround expansion of Railways during the Third Five Year Plan. On one side there has been additional revenue and

on the other side it has fulfilled its social obligations. Railways have given great help in maintaining the supply of food grains in drought affected areas.

It has been said by some hon'ble members here that saloons should not be provided to the Railway officers but in my opinion it is fully justified. These officers have to work in forests and other isolated areas and in such circumstances they cannot leave their families alone. In view of above provision of saloons for theso officers is all the more necessary. The facilities of Rest Houses for the Railway staff and officers should also continue.

I do not find any justification for the deficit budget of Railways. Deficit budget could have been avoided, had all the resources of income been explored. Fifty percent of travellers travel without ticket, thirty percent travel by passes and only twenty percent purchase tickets. The travelling without ticket should be checked effectively.

Thefts are committed in the Railway workshops and if an enquiry of these cases is conducted, it will be found that Railway officers, Engineers and E. M. E. are responsible for them.

Out of a line going of 12 person only five or six person go on round of supervision. Rest of the persons work some where else but their salaries are distributed amongst the officers and other staff. In fact there is utmost need of economy and if we do not require so many posts, we should abolish them.

The assessment of goods traffic had not been done correctly and as a result thereof the goods wagons were lying idle. Similarly Howrah-Kanpur line has not been electrified as scheduled. It is also proposed to take over the work of communications from Post and Telegraphs Department. In my opinion Railway is not in a position to carry this additional burden and it should be postponed for the present. We should not waste our money for imports of engines from different countries. The diesel engines manufacture in Banaras and Aleco engines of U. S. A. are working quite satisfactorily.

The increase in fares of Third class passengers is wholly unjustified especially in the absence of any facilities and by increase in freight rate the prices of commodities will undoubtedly go up.

There is only one bogie reserved for women in Mail or Express trains which is quite insufficient keeping in view the requirements. The women passengers are not provided with any facilities in our largest democracy. Arrangements for drinking water are quite in adequate. The Railway authoities should realise their social obligations towards the society. A wooden bridge at Bareilly needs immediate replacement and steps should be taken to complete this work. I would request the Railway authorities to increase the number of trains from Delhi to Lucknow as the trains on this line are very much crowded. Arrangements should be made for one exclusive train from Agra to Lucknow and an additional train from Meerut to Lucknow.

कुछ आरोपों के बारे में नियम ३५७ के अन्तर्गत व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

PERSONAL EXPLANATION UNDER RULE 357. RE : CERTAIN ALLEGATIONS.

बिना विभाग के मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : आज प्रातः श्री स० मो० बनर्जी ने मुझ पर आरोप लगाया कि मैं किसी बिड़ला ट्रस्ट का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हूं और उनसे मुझे कुछ

धन मिलता है। यह गलत बात है। मैं बिड़ला के दो शिक्षा ट्रस्टों—एक पिलानी और दूसरा रांची के शिक्षा ट्रस्ट का एक सदस्य मात्र हूं। ये दोनों कोई व्यापारिक संस्थाएं नहीं हैं। मैं पिलानी के ट्रस्ट का सदस्य डा० राजेन्द्र प्रसाद के राष्ट्रपति पद को सम्भालने के बाद बना और पिछले 15 वर्षों में मैंने इस ट्रस्ट की चार या पांच बैठकों में भाग लिया है। इसलिए मैं इस आरोप का खंडन करता हूं कि मैंने बिड़ला से किसी रूप में धन लिया है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : आज प्रातः श्री स० मो० बनर्जी ने मुझ पर कुछ व्यक्तिगत आरोप लगाये। मैं तकनीकी जानकारी रखने वाला एक प्रशिक्षित व्यक्ति हूं और इस व्यावसायिक प्रशिक्षण से मैं अपना जीवन व्यतीत करता हूं। मैं मंत्री पद को सम्भालने से पूर्व बिड़ला के एक समवाय में अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर था। मेरा इस समवाय से व्यावसायिक सम्बन्ध था। वस्तुतः इसके साथ मैं किसी एक और समवाय में भी तकनीकी निदेशक के रूप में काम करता था जिसका बिड़ला गुट से कोई सम्बन्ध नहीं था। मंत्री पद को सम्भालने से पूर्व मैंने दोनों समवायों से त्याग-पत्र दे दिया था। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैंने अपनी वेतन के अतिरिक्त और किसी रूप में कोई धन नहीं लिया। वास्तव में एक समवाय से तो मैंने मंत्री पद सम्भालने से कई महीने पूर्व त्याग पत्र दे दिया था।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक सभा बुद्धवार, 31 मई, 1967/10 ज्येष्ठ, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday, the 31st May, 1967/10 Jyaistha, 1889 (Saka)